गांवों में कोविड-19
छुपा हुआ संकट

खाद्य तेलों में क्यों
लगी है आग

सुशील कुमार
खड़े-खड़े चित पहलवान

16 जून, 2021 40 रुपए

इंडिया टुडे

“अर्थव्यवस्था बड़ी चुनौती है लेकिन हम तैयार हैं”

खास बातचीत
निर्मला सीतारमण, *वित्त मंत्री*

साथ में प्रमुख अर्थशास्त्रियों की राय में बहाली का खाका

RNI NO 45823/86 REGISTERED NO. DL(ND)-11/6042/2021-22-2023; LICENSED TO POST WPP NO U(C)-31/2021-23; FARIDABAD/46/2020-22

www.indiatodayhindi.in

OC

VISIT…

INDIA TODAY

We tell the story

Not the moral of the story

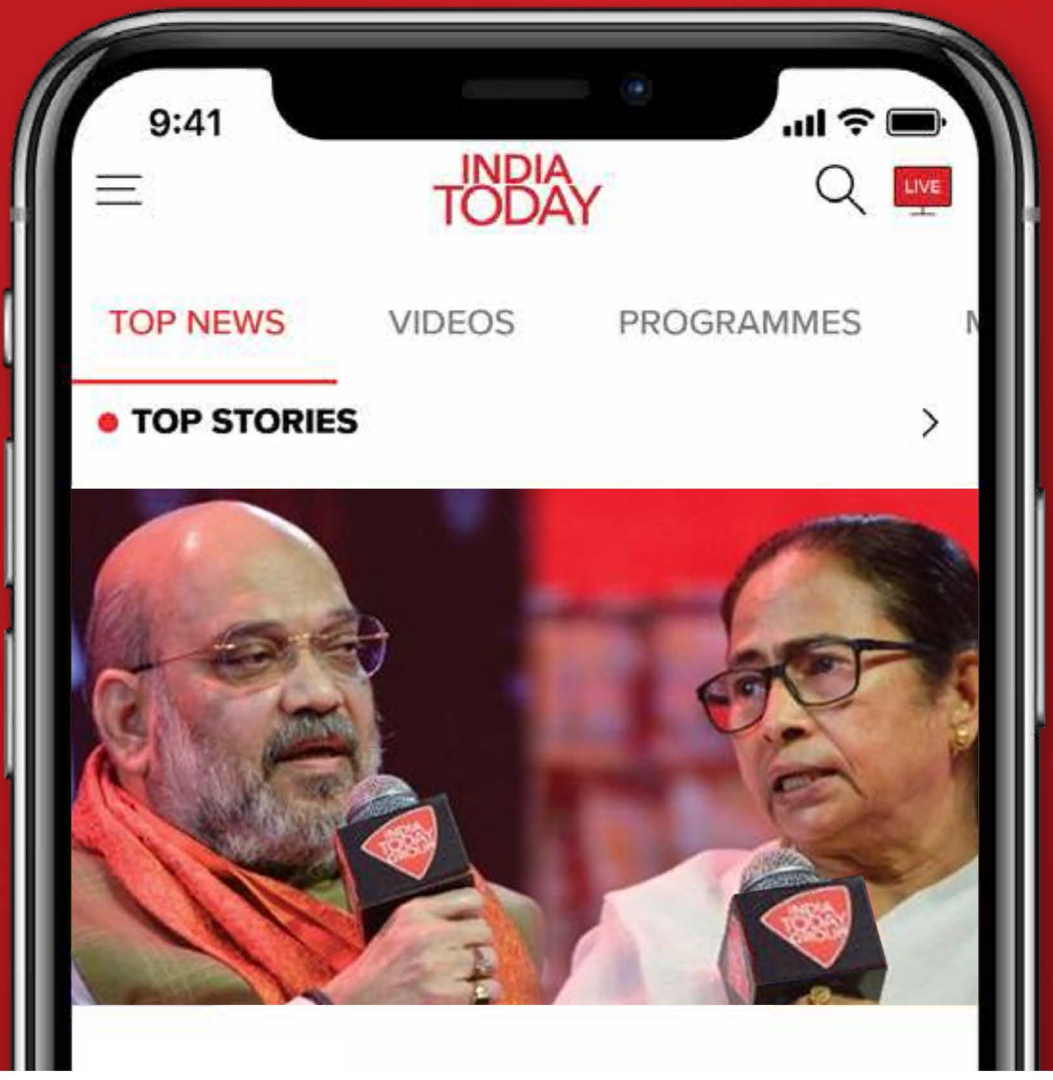

DOWNLOAD THE APP NOW

AVAILABLE ON

Only Books Magazine

प्रधान संपादक की कलम से

भारत इस वक्त भीषण सांसत में फंसा है. एक तरफ बढ़ता स्वास्थ्य संकट है और दूसरी तरफ भारतीय अर्थव्यवस्था की तेज गिरावट. दोनों मानवीय संकट हैं. एक जिंदगी और मौत का मामला है, दूसरा रोजी-रोटी का. दोनों में करीबी रिश्ता है. अर्थव्यवस्था के लिए अनिश्चितता से बदतर कुछ नहीं. वायरस की राह सचमुच नामालूम है और अर्थव्यवस्था भी अनिश्चितता की छाया में है कि कब वह पूरी या आंशिक बंद हो जाएगी. बदकिस्मती से भारतीय अर्थव्यवस्था 2016-17 वित्तीय साल की तीसरी तिमाही से ही लगातार गिर रही है, जब उसकी गिरावट 8.6 फीसद से शुरू होकर 2019-20 की आखिरी तिमाही में 4 फीसद पर जा पहुंची. करीब-करीब यही वह वक्त था जब महामारी ने धावा बोला और 24 मार्च को देश को महज चार घंटे के नोटिस पर 68 दिनों के लॉकडाउन में धकेल दिया. कई जानकार महामारी से पहले चार सालों की गिरावट के लिए 8 नवंबर, 2016 को घोषित 86 फीसद भारतीय मुद्रा की नोटबंदी को जिम्मेदार ठहराते हैं. इसके बाद हड़बड़ी में लागू पेचीदा जीएसटी (माल और सेवा कर) आया. बैंकिंग व्यवस्था पहले ही अनचुके कर्जों के जबरदस्त बोझ से दबी थी. सरकार कहती है कि यह गिरावट चक्रीय थी. दिक्कत यह है कि जब महामारी ने हमला बोला तब भारतीय अर्थव्यवस्था के पास कोई सहारा नहीं था और सरकार ने अपने को कुएं और खाई के बीच पाया.

नए सरकारी आंकड़े अर्थव्यवस्था के आइसीयू में होने की और भी डरावनी तस्वीर पेश करते हैं. पिछले वित्तीय वर्ष में अर्थव्यवस्था 7.3 फीसद संकुचित हुई. यह 1979-80 में जीडीपी के 5.2 फीसद सिकुड़ने के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था का पहला पूरे साल का संकुचन है. उम्मीद की हल्की किरण वित्तीय साल 2021 की चौथी तिमाही में आई, जब अर्थव्यवस्था 1.6 फीसद बढ़ी, लेकिन उसे भी इस साल अप्रैल में महामारी के खतरनाक नए उभार ने चूर-चूर कर दिया.

दूसरी लहर ने, जिसका अनुमान लगाने में सरकार पूरी तरह नाकाम रही, कारोबारों को धूल-धूसरित कर दिया, लाखों की नौकरियां ले ली और कई और लोगों को गरीबी में धकेल दिया. फैक्ट्रियों में बंदी और छंटनी से बेरोजगारी नई ऊंचाई पर पहुंच गई. सीएमआइई (सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी) के मुताबिक, कामगारों की संख्या 11 लाख कम हो गई और काम-धंधे की नाकाम खोज कर रहे लोगों की तादाद में 62 लाख—मार्च में 2.77 करोड़ से बढ़कर अप्रैल में 3.39 करोड़—का इजाफा हुआ. लॉकडाउन की पाबंदियों ने इस साल फरवरी और अप्रैल के बीच नब्बे लाख वैतनिक नौकरियां लील लीं. निवेश फर्म बार्कलेज का अनुमान है कि पूरे मई के दौरान, जब 98 फीसद देश लॉकडाउन की गिरफ्त में था, भारत ने हर हफ्ते 58,000 करोड़ रुपए गंवाए. ग्रामीण भारत में नौकरियों के अवसर देने वाले तीन बड़े क्षेत्र—कृषि, निर्माण और छोटे पैमाने की मैन्युफैक्चरिंग—ध्वस्त हो गए. कृषि जिंसों की कीमतें गिर रही हैं जबकि आगत लागतें बढ़ रही हैं. बड़ा नियोक्ता निजी निर्माण ठहराव का शिकार है.

रुपए-पैसे की लगातार किल्लत ज्यादातर लोगों को अर्थव्यवस्था के पिरामिड के रसातल में धकेल रही है. अमेरिका स्थित प्यू रिसर्च सेंटर की मार्च की एक रिपोर्ट से पता चला कि महामारी ने करीब 3.2 करोड़ हिंदुस्तानियों को मध्यम वर्ग के दायरे से बाहर धकेल दिया, वह भी तब जब मध्यम वर्ग की परिभाषा का मानदंड बहुत छोटा है—वे जो एक दिन में 10 डॉलर (724 रुपए) और 20 डॉलर (1,449 रुपए) के बीच कमाते हैं. महामारी से पहले भारतीय मध्यम वर्ग में 9.9 करोड़ लोग थे. एक साल बाद महज 6.6 करोड़ हैं.

हालिया अतीत में आर्थिक वृद्धि की उतनी तत्काल जरूरत पहले कभी नहीं थी जितनी अब है. खासकर जब लोग बेरोजगारी और बढ़ती महंगाई की दोहरी मार झेल रहे हैं. खुशकिस्मती से, लगता है हम दूसरी लहर का शिखर पार कर चुके हैं. लिहाजा, यह देखने का सही वक्त है कि भारतीय अर्थव्यवस्था को एक झटके में फिर शुरू करने के लिए क्या करना जरूरी है.

इस हफ्ते हमारी आवरण कथा के लिए ग्रुप एडिटोरियल डायरेक्टर (पब्लिशिंग) राज चेंगप्पा और *बिजनेस टुडे* के एडिटर राजीव दुबे ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से बातचीत की. अर्थव्यवस्था में जान फूंकने का मुश्किल काम संभाल रहीं सीतारमण ने भरोसा जताया. उन्होंने कहा कि कोविड के बाद अर्थव्यवस्था से निपटने के लिए ढेर सारे उपाय किए गए हैं. एग्जीक्यूटिव एडिटर एम.जी. अरुण और डिप्टी एडिटर श्वेता पुंज ने अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने के तरीकों की पड़ताल की. कारोबार और उद्योग की दुनिया में आम राय है कि सरकार अपने खर्च बढ़ाए, जरूरी हो तो ज्यादा नोट छापकर और लोगों के हाथ में ज्यादा नकदी देकर ऐसा करे, ताकि मांग को बढ़ावा मिले. निजी उपभोग खर्च जीडीपी का 55 फीसद है और जब तक इसे तत्काल बढ़ावा नहीं दिया जाता, अर्थव्यवस्था के पटरी पर लौटने की संभावना कम ही रहेगी. फरवरी में बजट में कहा गया कि सरकार 2020-21 के 34.5 लाख करोड़ रुपए के मुकाबले 34.8 लाख करोड़ रुपए खर्च करेगी. यह 0.95 फीसद की बढ़ोतरी है, जो निजी मांग में तेजी लाने के लिए जरूरी भरोसा नहीं जगाती. शायद पिछले बजट में कुछ सुधार की जरूरत है.

22 अप्रैल, 2020 का आवरण

अगले महीने 1991 के ऐतिहासिक बजट को तीन दशक हो जाएंगे. उस बजट ने भारतीय अर्थव्यवस्था में सुधारों की शुरुआत को हरी झंडी दिखाई थी. हमारा बोर्ड ऑफ इंडिया टुडे इकोनॉमिस्ट (बाइट) आग्रह करता है कि सरकार लोगों को सीधे और ज्यादा नकदी देने की पहल करे. वे मांग करते हैं कि सरकार लोगों की तकलीफों को दूर करने के साथ इस मौके का इस्तेमाल लंबे वक्त से टलते आ रहे बुनियादी सुधारों को अंजाम देने के लिए करे. हमारे विशेषज्ञ सबसे बड़े नियोक्ता रिटेल, हॉस्पिटैलिटी और एमएसएमई क्षेत्रों को प्रोत्साहन पैकेज और तत्काल राहत देने की सिफारिश करते हैं. वे गंभीर रूप से प्रभावित शहरी गरीबों को मदद देने, स्वास्थ्य के ग्रामीण बुनियादी ढांचे को उन्नत बनाने, रोजगार सृजन को सहारा देने के लिए मनरेगा की धनराशि बढ़ाने, आजीविकाओं को बचाने और ग्रामीण गरीबों में भुखमरी टालने के उपायों की वकालत करते हैं. वे एमएसपी योजनाओं की जगह आमदनी बढ़ाने में सहायक कृषि सुधारों की तस्दीक करते हैं.

आगे सरकार के कंधों पर महामारी को पछाड़ने और अर्थव्यवस्था में नई जान फूंकने का जबरदस्त मुश्किल काम है. वक्त बहुत कम है. एक और स्वास्थ्य संकट और उसके बाद आम तौर पर आने वाले आर्थिक संकट से बचने का अकेला तरीका लड़खड़ाती वैक्सीन नीति को दुरुस्त करना है. वायरस के फैलाव पर लगाम कसने और अर्थव्यवस्था पर पसरी अनिश्चितता की चादर को हटाने के लिए जरूरी है कि वह ज्यादा से ज्यादा लोगों को टीके लगाए. सही प्रोत्साहन मिले तो अर्थव्यवस्था फिर ठप्प होने की आशंका के बगैर दुबारा हरकत में आ सकती है. भारतीयों की तरह भारतीय अर्थव्यवस्था भी लोचदार है और इस आर्थिक गर्त से उबर सकती है, बशर्ते सरकार साहस और स्पष्टता से कदम उठाए.

अरुण पुरी

(अरुण पुरी)

इंडिया टुडे

www.indiatodayhindi.in

चेयरमैन और प्रधान संपादक: अरुण पुरी
वाइस चेयरपर्सन: कली पुरी
ग्रुप चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर: दिनेश भाटिया
ग्रुप एडिटोरियल डायरेक्टर: राज चेंगप्पा
चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर: मनोज शर्मा
एडिटर: अंशुमान तिवारी
सीनियर एडिटर: मोहम्मद वक़ास
एसोसिएट एडिटर: शिवकेश मिश्र, शुभम शंखधर
असिस्टेंट एडिटर: मनीष दीक्षित, सुजीत ठाकुर
राज्य ब्यूरो: आशीष मिश्र (लखनऊ), अमिताभ श्रीवास्तव (पटना), रोहित परिहार (जयपुर), एम.जी. अरुण (मुंबई), राहुल नरोन्हा (भोपाल), अमरनाथ के. मेनन (हैदराबाद)
ग्रुप क्रिएटिव एडिटर: नीलांजन दास
एसोसिएट आर्ट डायरेक्टर: चंद्रमोहन ज्योति
चीफ डिजाइनर: असित रॉय
ग्रुप फोटो एडिटर: बंदीप सिंह
फोटो डिपार्टमेंट: यासिर इकबाल, राजवंत रावत, चंद्रदीप कुमार, मंदार सुरेश देवधर (मुंबई)
चीफ फोटो रिसर्चर: प्रभाकर तिवारी
प्रिंसिपल फोटो रिसर्चर: सलोनी वैद
प्रोडक्शन चीफ: अभिनव पुगला
एसोसिएट पब्लिशर: अनिल फर्नांडीस
इंपैक्ट टीम
सीनियर जनरल मैनेजर: जीतेंद्र लाड (वेस्ट)
जनरल मैनेजर: मयूर रस्तोगी (नॉर्थ), उपेंद्र सिंह (बेंगलूरु)
डिप्टी जनरल मैनेजर: इंद्रनील चटर्जी (ईस्ट)
ग्रुप चीफ मार्केटिंग ऑफिसर: विवेक मल्होत्रा
सेल्स एवं ऑपरेशन
सीनियर जनरल मैनेजर: दीपक भट्ट (नेशनल सेल्स)
जनरल मैनेजर: विपिन बग्गा (ऑपरेशंस)
डिप्टी जनरल मैनेजर: राजीव गांधी (नॉर्थ)
रीजनल सेल्स मैनेजर: सैयद आसिफ सलीम (वेस्ट)
डिप्टी रीजनल सेल्स मैनेजर: एस. परमशिवम (साउथ)
सीनियर सेल्स मैनेजर: पीयूष रंजन दास (ईस्ट)

INDIA TODAY GROUP

वर्ष: 35; अंक: 29; 10-16 जून, 2021; प्रत्येक शनिवार को प्रकाशित

- **संपादकीय कॉर्पोरेट कार्यालय:** लिविंग मीडिया इंडिया लिमिटेड, इंडिया टुडे ग्रुप मीडियाप्लेक्स, एफसी-8, सेक्टर 16-ए, फिल्म सिटी, नोएडा-201301, फोन: 0120-4807100;
- **ग्राहकी चंदा भेजें:** इंडिया टुडे (हिंदी), पो. बॉक्स 114, नई दिल्ली-110001
- **ग्राहक सेवा:** कस्टमर केयर, इंडिया टुडे ग्रुप, सी-9, सेक्टर-10, नोएडा (उत्तर प्रदेश)-201301, टोल फ्री फोन नं. 1800 1800 100 (बीएसएनएल/एमटीएनएल लाइनों से) फोन: दिल्ली, फरीदाबाद से (95120) 2479900; शेष भारत से (0120) 2479900. (सोम से शुक्र-सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक), फैक्स: (0120) 4078080. ई-मेल: wecare@intoday.com
- **सर्कुलेशन कार्यालय:** लिविंग मीडिया इंडिया लिमिटेड, सी-9, सेक्टर-10, नोएडा (उत्तर प्रदेश)-201301
- **इंपैक्ट कार्यालय:** 1201, 12वां तल, टावर 2ए, वन इंडियाबुल्स सेंटर, (जुपिटर मिल्स) एस.बी. मार्ग, लोअर परेल (पश्चिम)-मुंबई-400013. फोन: 022-66063355 फैक्स: 022-66063226
- **क्षेत्रीय विज्ञापन कार्यालय:** ए1-ए2, एनके सेंटर, विनुज्य निकुंज, उद्योग विहार, फेज-5, गुड़गांव, हरियाणा, फोन: 0124-4948400;
- 201-204 रिचमंड टावर्स, द्वितीय मंजिल, 12 रिचमंड रोड, बंगलुरु-560 025 फोन: 2212448, 226233, टेलेक्स: 0845-2217 INTO IN. फैक्स: 080-2218335.
- रजिस्टर्ड कार्यालय: एफ-26, फर्स्ट फ्लोर, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली-110001

- लिविंग मीडिया इंडिया लि. विश्व भर में सर्वाधिकार सुरक्षित. किसी भी रूप में सामग्री की नकल प्रतिबंधित. इंडिया टुडे अनिमंत्रित प्रकाशन सामग्री को लौटाने की जिम्मेदारी स्वीकार नहीं करता.
- सभी विवादों का निबटारा दिल्ली/नई दिल्ली की सीमा में आने वाली सक्षम अदालतों और फोरमों में किया जाएगा.

- **लिविंग मीडिया इंडिया लि. के लिए मुद्रक एवं प्रकाशक मनोज शर्मा द्वारा एफ-26, फर्स्ट फ्लोर, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली-110001 से प्रकाशित और थॉमसन प्रेस इंडिया लि., 18-35, माइलस्टोन, दिल्ली-मथुरा रोड, फरीदाबाद-121 007 (हरियाणा) में मुद्रित.**
संपादक: राज चेंगप्पा

सुर्खियां
मोदी-ममता की नई जंग
पेज 5

अर्थात्: ऐसे आती है गरीबी
पेज 18

फुरसत
सवाल-जवाब/टी.एम. कृष्ण: राग की रंगत में विचार
पेज 50

भीतर

बंदीप सिंह

आवरण कथा

‘अर्थव्यवस्था बड़ी चुनौती से दो-चार, पर उससे निबटने की पूरी तैयारी है’

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने खास बातचीत में अर्थव्यवस्था में नई जान डालने की योजना का खुलासा किया.

साथ में: इंडिया टुडे के अर्थशास्त्रियों की बोर्ड की ओर से सुधार का खाका

उत्तर प्रदेश
8 गांव हैं चुनाव की समरभूमि
कोविड से प्रभावित गांवों में सरकार से नाराजगी, जिसे भुनाने में जुटे विभिन्न दल.

खास रपट
38 देहात में दानव
ग्रामीण भारत में अव्यवस्था से महामारी के खिलाफ जंग काफी मुश्किल.

सुशील कुमार
45 दंगल में भला कौन सुशील
ओलंपिक पदक विजेता की गिरफ्तारी ने कुश्ती की दुनिया से परदा उठाया.

तरुण तेजपाल
48 राज्य अब हाइकोर्ट में
तरुण तेजपाल को बरी करने के फैसले को गोवा सरकार ने चुनौती दी.

इंडिया टुडे
इंडिया टुडे मैगजीन मिलने में दिक्कत हो रही है?
9311409555 पर नाम पता या ‘हेलो’ संदेश भेजें.
या मेल करें: Moreinfo@intoday.com
हम आपसे संपर्क कर लेंगे.

आवरण फोटो: बंदीप सिंह

पाठकों के लिए सूचना: कभी-कभी आपको इंडिया टुडे पत्रिका में ‘इम्पैक्ट फीचर’ या ‘एडवरटोरियल’ या ‘फोकस’ के पन्ने नजर आएंगे. ये विज्ञापन होंगे और इन्हें बनाने में पत्रिका के संपादकीय स्टाफ शामिल नहीं होते.

INDIA TODAY GROUP

पाठकों को सलाह दी जाती है कि पत्रिका में प्रकाशित किसी भी वस्तु, सेवा या व्यक्ति के विज्ञापन और प्रचार से संबंधित सामग्री से वचनबद्धता कायम करने, पैसा भेजने या खर्च करने से पहले उचित जांच-पड़ताल कर लें. विज्ञापनदाताओं के किसी भी दावे का उत्तरदायित्व इंडिया टुडे ग्रुप का नहीं है. ऐसे किसी भी तरह के दावों को विज्ञापनदाता अगर नहीं पूरा करता है तो इंडिया टुडे ग्रुप के प्रकाशनों के मुद्रक, प्रकाशक, एडिटर-इन-चीफ और एडिटर इसके लिए जिम्मेदार नहीं होंगे.

Only Books Magazine

उत्तर प्रदेश: कोविड प्रभावित गांव हैं चुनाव की समरभूमि
पेज 8

समाचार सार:
पेनड्राइव परीक्षा
पेज 16

सुर्खियां

तेल का आयात:
क्यों सुलग उठी रसोई?
पेज 14

मुश्किल लहरें
यास साइक्लोन से हुए नुक्सान का सर्वेक्षण करने 28 मई को दीघा आईं ममता बनर्जी और (उनके दाएं) तत्कालीन मुख्य सचिव अलपन बंद्योपाध्याय

पश्चिम बंगाल

मोदी-ममता की नई जंग

कौशिक डेका

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री के रूप में ममता बनर्जी के लिए अपने तीसरे कार्यकाल का पहला महीना बड़ा तूफानी रहा. ऐसा प्रतीत होता है कि भाजपा के शीर्ष नेतृत्व ने चुनावी हार को दिल से लगा लिया है और वह ममता सरकार पर लगातार दबाव बनाए रखना चाहती है. कई केंद्रीय टीम राज्य में 'कानून और व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा' करने के लिए उतारी जा चुकी हैं और ऐसा लगता है कि वर्षों से चल रहे घोटालों की जांच के लिए जांच एजेंसियों की नींद अचानक खुल गई है.

पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव अलपन बंद्योपाध्याय को केंद्र की ओर से वापस बुलाना इस खींचतान की नवीनतम कड़ी है. उसके जवाब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखे एक सार्वजनिक पत्र में ममता ने आदेश को वापस लेने की 'अपील' की क्योंकि उनके अनुसार, बंगाल को उस नौकरशाह की जरूरत थी. पर ऐसा हुआ नहीं और मुख्य सचिव ने आधिकारिक रूप से इस्तीफा दे दिया. अगले तीन वर्षों के लिए उन्हें ममता के मुख्य सलाहकार के रूप में फिर से नियुक्त किया गया है (अब वे केंद्र की अनुशासनात्मक कार्रवाई का भी सामना कर रहे हैं).

ममता की परेशानी उसी दिन, या उनके शब्दों में कहें तो 'उसी मिनट' शुरू हो गई थी जब उन्होंने 5 मई को शपथ ली. यहां तक कि राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने अपने धन्यवाद भाषण में, तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) प्रमुख को राजधर्म की याद दिला दी. राजभवन के बाहर विपक्षी भाजपा राज्य में चुनाव के बाद की हिंसा और 'कानून व्यवस्था की खतरनाक स्थिति' के विरुद्ध धरना दे रही थी.

अगले दिन 6 मई को, केंद्रीय गृह मंत्रालय की एक चार सदस्यीय टीम राज्य सचिवालय नबन्ना पहुंची और संकटग्रस्त जिलों का दौरा करने से पहले वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की. इस बीच, राज्यपाल ने चार साल पुराने नारद वित्तीय घोटाला मामले में दो मौजूदा मंत्रियों (फरहाद हकीम और सुब्रत मुखर्जी) सहित चार टीएमसी दिग्गजों के खिलाफ सीबीआइ अभियोजन को मंजूरी दे दी और टकराव का एक नया मोर्चा खुल गया.

इससे बदतर स्थिति तो अभी बाकी थी.

पीटीआइ

ताकतवर तूफान
कोलकाता में 28 मई को यास चक्रवात को लेकर पीएम मोदी की समीक्षा बैठक जिससे ममता नदारद रहीं

17 मई की सुबह उन चारों टीएमसी नेताओं को हिरासत में ले लिया गया. ममता इसके लिए तैयार नहीं थीं. हकीम कोलकाता नगर निगम के प्रभारी भी हैं. ऐसे वक्त में जब लॉकडाउन लगा था और राज्य की राजधानी में रोजाना कोविड के 12,000 नए मामले आ रहे थे हकीम की गिरफ्तारी से ममता गुस्सा हो गईं.

ममता कोलकाता के सीबीआइ कार्यालय में घुस गईं और छह घंटे तक वहां बनी रहीं जब तक कि नेताओं को पेश नहीं किया गया और सीबीआइ अदालत में उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई नहीं हुई. ममता के धरने की खबर फैलते ही टीएमसी समर्थक सीबीआइ कार्यालय का घेराव करने पहुंचे. यहां तक कि राजभवन के केंद्रीय द्वारों को भी नहीं बख्शा गया. राज्यपाल धनखड़ ने एक के बाद एक ट्वीट करके मामले को हवा देने में कोई समय नहीं गंवाया, तो कैलाश विजयवर्गीय जैसे भाजपा के राष्ट्रीय नेता फिर से राष्ट्रपति शासन की जरूरत का हौव्वा खड़ा करने लगे.

यह सब चल ही रहा था कि चक्रवात यास ने राज्य में दस्तक देकर तबाही मचा दी. ममता राहत कार्य में जुटी थीं कि पीएम मोदी ने बंगाल सरकार को सूचित किया कि वे एक हवाई सर्वेक्षण करना चाहते हैं और 28 मई को मुख्यमंत्री के साथ एक समीक्षा बैठक करना चाहते हैं. ममता शुरू में इसके लिए सहमत हो गईं, पर जब उन्होंने इस बैठक में शामिल होने वाले लोगों के नाम की सूची देखी तो पीछे हट गईं. इस समीक्षा बैठक में शामिल होने वालों की सूची में राज्यपाल, दो केंद्रीय मंत्रियों और विपक्ष के नेता सुवेंदु अधिकारी का नाम शामिल था. उन्होंने बैठक से किनारा कर लिया और उनकी अनुपस्थिति की एक तस्वीर (ऊपर देखें) वायरल हो गई. बाद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उन्होंने इसके पीछे वजह बताई, ''यह पीएम और सीएम की बैठक नहीं थी. यह तो भाजपा पार्टी की एक बड़ी बैठक थी...और दूसरी तरफ मैं अकेली थी.''

उस बैठक के लिए मना करने के बाद, 28 मई को ममता अपने अंदाज में बंद्योपाध्याय को साथ लेकर समीक्षा बैठक में अचानक पहुंच गईं और पीएम को एक रिपोर्ट सौंपी जिसमें पश्चिम बंगाल में हुए नुक्सान का आकलन था, और फिर उन्होंने चक्रवात प्रभावित दीघा में पूर्व निर्धारित प्रशासनिक सत्र का हवाला देते हुए जाने की अनुमति मांग ली.

उसी शाम बंद्योपाध्याय को दिल्ली वापस बुला लिया गया. संयोग से, वे आधिकारिक तौर पर 31 मई को सेवानिवृत्त हो गए होते, अगर केंद्र ने कोविड और फिर चक्रवात यास की चुनौतियों से निपटने के लिए राज्य के अनुरोध पर उनके तीन महीने के सेवा विस्तार को मंजूरी नहीं दी होती. बंद्योपाध्याय ने भले ही इस्तीफा दे दिया हो, लेकिन केंद्र ने उन्हें अन्य बातों के अलावा पीएम (जो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष भी हैं) की चक्रवात यास पर बुलाई गई समीक्षा बैठक से अनुपस्थित रहने के लिए 31 मई को कारण बताओ नोटिस जारी किया. नोटिस में कहा गया है कि बंद्योपाध्याय ने आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 (बी) का उल्लंघन किया है और उन्हें तीन दिनों के भीतर जवाब देने को कहा गया है.

ममता, बंद्योपाध्याय को वापस बुलाने के कदम से चिंतित थीं. तब तक, भगवा ब्रिगेड ममता के बढ़े अहंकार, लोक कल्याण के लिए उनकी कम और दूसरे कार्यों में ज्यादा रुचि जैसी बातों के साथ ट्वीट करते हुए, सोशल मीडिया पर एक कथ्य गढ़ चुका था. ममता ने भी पलटवार किया, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और कहा कि वे केंद्र के दबाव के आगे झुकने वाली नहीं. उन्होंने इस मौके को क्षेत्रीय पहचान की उसी आग को भड़काने के अवसर के रूप में लिया, जिसका भरपूर लाभ उन्होंने चुनावों में लिया था. ममता ने आरोप लगाए कि एक सक्षम अधिकारी को सिर्फ इसलिए परेशान किया जा रहा है क्योंकि वे बंगाली हैं. उन्होंने बार-बार पूछा, ''बंद्योपाध्याय का क्या दोष था? बंगाल को क्यों निशाना बनाया जा रहा है? क्या यह सब इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि आप हार को पचा नहीं पा रहे हैं?''

विपक्षी मुख्यमंत्रियों को केंद्र के खिलाफ एकजुट होने का आह्वान करते हुए ममता बनर्जी ने कहा, ''जो डरते हैं वो मरते हैं''

सियासी करतब

विपक्षी मुख्यमंत्रियों को एकजुट होने और ''तानाशाह हिटलर और स्टालिन की तरह निरंकुश व्यवहार कर रहे केंद्र'' के खिलाफ आवाज उठाने का आह्वान करते हुए ममता ने 31 मई को ब्लॉकबस्टर हिट फिल्म *शोले* का एक बहुचर्चित डायलॉग मारा ''जो डरते हैं, वो मरते हैं.'' भाजपा की योजना उन्हें लगातार उलझाए रखने की है ताकि उनके पास अपने राज्य से परे सोचने के लिए वक्त बहुत कम हो, पर स्पष्ट है कि ममता भाजपा की इस रणनीति के आगे घुटने टेकने वाली नहीं हैं. प्रेसिडेंसी विश्वविद्यालय के प्रोफेसर एमेरिटस, प्रशांत रे कहते हैं, ''ममता अब मोदी के लिए सबसे बड़ी चुनौती हैं. चाहे वह कोविड हो, अर्थव्यवस्था की बदहाली हो या विनिवेश, ममता उन कुछ नेताओं में से एक हैं जो मोदी के कुप्रबंधन पर हमले करने का कोई अवसर नहीं छोड़ते और भाजपा को लगता है कि ममता को घेरने से उसकी बहुत सारी समस्याएं कम हो सकती हैं. लगातार हमले उन्हें व्यस्त और उत्तेजित रखने की एक चाल है.''

ममता का मोदी को लिखा पांच पन्नों का पत्र जिसमें उन्होंने बंधोपाध्याय को वापस बुलाने का आदेश वापस लेने की अपील की, उनके जवाबी हमले का एक आदर्श उदाहरण है. पत्र में उन पंक्तियों की भरमार है जिसमें उन्होंने तर्क दिए हैं कि केंद्र का 'एकतरफा आदेश' कैसे 'राज्य के लोगों के हितों' को हानि पहुंचाएगा. जादवपुर विश्वविद्यालय में अंतरराष्ट्रीय संबंधों के प्रोफेसर इमान कल्याण लाहिड़ी कहते हैं, ''केंद्र दबाव की रणनीति से ममता को काबू में रखने की कोशिश कर रहा है, वहीं ममता भी लगातार कई मौके दे रही हैं. समीक्षा बैठक का बहिष्कार करने की क्या जरूरत थी? एक-दूसरे पर हावी होने के इन पेच-पैतरों का खामियाजा तो आखिरकार बंगाल की जनता को उठाना होगा.''

और इन सबसे सिर्फ बंगाल के लोग ही चिंतित नहीं हैं. बंद्योपाध्याय के मामले से नौकरशाह बिरादरी भी परेशान है. उन्हें चिंता है कि केंद्र और राज्य के बीच की इस जंग में फंसकर वे अगला लक्ष्य हो सकते हैं. ■

सैयदा
हमीद

मेहमान का पन्ना

लालच पर विकास का मुलम्मा

यकीनन विवादास्पद लक्षद्वीप विकास प्राधिकरण नियमन 2021 (एलडीएआर 21) का मसौदा देख केरल, समूचे देश भारत और बेशक उस द्वीप के लोग हिल उठे हैं. एलडीएआर 21 उसी पटकथा की बानगी है, जो पूरे देश में पिछले सात साल से बेहद घातक ढंग से पसरी हुई है. वहां बीफ पर प्रतिबंध की बात है, जहां गायें नहीं हैं; एहतियातन बंदी कानून की बात है, जहां अपराध नहीं है; सड़कों को चौड़ा करने की बात है, जहां किसी सड़क की अधिकतम लंबाई सड़क 11 किलोमीटर है.

इन प्रस्तावित 'सुधारों' पर मेरी अपनी राय की पृष्ठभूमि यह है कि मैं दस साल तक पूर्व योजना आयोग में लक्षद्वीप और अंडमान तथा निकोबार द्वीपसमूहों की प्रभारी सदस्य रही हूं. उसमें प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाले द्वीप विकास प्राधिकरण (आइडीए) के साथ कामकाज और तत्कालीन सांसदों, अंडमान तथा निकोबार के मनोरंजन भक्त और लक्षद्वीप के पी.एम. सईद के साथ संवाद भी शामिल था.

आइडीए की स्थापना 1986 में प्रधानमंत्री राजीव गांधी की ओर से की गई थी, ताकि दोनों द्वीपसमूहों के लिए एकीकृत और पर्यावरण के लिहाज से सुदृढ़ विकास रणनीति बनाई जा सके. देश के अग्रणी भौतिकविद तथा नीति निर्माता एम.जी.के. मेनन के तहत एक समिति बनाई गई थी. 1988 में कवरत्ती में आइडीए की बैठक में देश के द्वीपीय भूभागों के विकास की रूपरेख पारित की गई. सेसिल जे. सलदान्हा की लिखी वह रिपोर्ट 1989 में प्रकाशित हुई.

मैं योजना आयोग में स्त्री अधिकार, मानवाधिकार और सिविल सोसाइटी का नजरिया लेकर पहुंची थी. मैं अकेली महिला सदस्य थी और मेरी अर्थशास्त्र या प्रशासन की कोई पृष्ठभूमि नहीं थी. शीर्ष स्तर के योजना निर्माण में लोगों की भागीदारी तय करने के लिए मैंने सिविल सोसाइटी विंडो का आयोजन किया, जहां लोग योजनाकारों से गुफ्तगू कर सकते थे. 22 जुलाई, 2010 को ऐसे ही एक 'विंडो' का आयोजन 'लक्षद्वीप और अंडमान तथा निकोबार द्वीपसमूहों में पर्यटन और पर्यावरण के मुद्दों' पर हुआ था. बैठक में द्वीपसमूहों के जत्थे, अकादमिक जगत के लोग, पर्यावरणवादी और संबंधित मंत्रालयों के अफसर शामिल हुए. इसमें तीन मुद्दों पर सर्वानुमति हुई और उन्हें योजना आयोग की ओर से आइडीए को सौंपा गया: 1) लक्षद्वीप में भूमि क्षेत्र बहुत छोटा है, इसलिए औद्योगिक गतिविधि का विकास संभव नहीं है; 2) पर्यटन राजस्व के स्रोत के तौर पर उभरा है, पर यह बेहद अहम है कि पंचायतों को इस प्रक्रिया में शामिल किया जाए और स्थानीय आबादी को फायदा मिले; 3) द्वीपों के लिए कोई भी 'मास्टर प्लान' स्थानीय लोगों की सहमति के बाद ही बनाया जाए.

एलडीआर 21 के तहत लक्षद्वीप के लिए प्रस्तावित कई नियम-कायदे इस द्वीप समूह के नाजुक पर्यावरण संतुलन के लिए मौत का फरमान साबित होंगे

लक्षद्वीप के मूल बाशिंदे 100 फीसद मुसलमान हैं. गैर-मुस्लिम तो बस सरकारी अफसर हैं. मूल रूप से द्वीपवासी मलयाली हैं, जिनका कोच्चि और कोझिकोड से संबंध है. इन द्वीपों पर नारियल के पेड़ों की बहुतायत है. समुद्र टुना मछलियों से भरा पड़ा है, जो उनका मुख्य आहार है. यहां येलोफिन टुना भारी तादाद में पाई जाती हैं, जिसे जापान में लजीज माना जाता है और जिसकी अच्छी कीमत मिल सकती है.

37 साल संसद में लक्षद्वीप की नुमाइंदगी करने वाले सईद ने मुझे 10 द्वीप (हर द्वीप में एक) पंचायतों के बारे में बताया था. यहां के लोग द्वीपों के नाजुक पर्यावरण के बारे में बेहद सजग हैं. उन्हें एहसास है कि अगर पर्यटन की खुली छूट दे दी जाए तो यहां शांति और सुरम्य वातावरण की तलाश में पर्यटकों की भेड़ियाधसान शुरू हो जाएगी.

योजना आयोग को खत्म हुए छह साल हो गए और द्वीप में मेरे निजी तजुर्बे को 12 साल हो चुके हैं. छह महीने पहले भाजपा के एक पूर्व मंत्री प्रफुल्ल खोड़ा पटेल को लक्षद्वीप का प्रशासक बनाया गया. उन्होंने कहा, ''लक्षद्वीप के लोग 70 साल बाद भी इतनी दयनीय हालत में हैं.'' आज महामारी के प्रकोप के बीच वे नए नियम-कानूनों की पेशकश करके सुर्खियों में हैं, जो इस द्वीपसमूह के नाजुक पर्यावरण संतुलन के लिए मौत का सबब बन सकते हैं. एलडीआर 21 का सबसे मास्टरस्ट्रोक प्रावधान खनन और खनिज संसाधनों के दोहन की इजाजत देना है, ताकि ये द्वीपसमूह सीमेंट की फैक्ट्री में बदल जाएं. इस इलाके में प्रजनन दर राष्ट्रीय औसत से कम है, वहां आबादी की वृद्धि रोकने, और लोगों की मांग पर लगाई गई नशाबंदी में ढील की कोशिश, दोनों से सांप्रदायिक राजनीति की बू आती है.

यह वह इलाका है, जहां बारिश के पानी का संग्रह करने की विधि 20 साल पहले अपनाई गई थी. यहां पूर्ण साक्षरता है और कोई गरीबी नहीं है. एकमात्र पर्यटन स्थल बंगाराम में न एयरकंडिशनर हैं, न बिजली और फिर भी वहां दुनिया भर का एलीट पहुंचा ही रहता है.

इस बीच, नीति आयोग के सीईओ ने चिह्नित द्वीपों के 'प्रमुख पर्यटन' और 'सर्वांगीण' विकास की बात कही है. उनका आशय मालदीव के मॉडल की तर्ज पर वाटर विला प्रोजेक्ट से है. मिनिकॉय, सुहेली और कदमत 'चिह्नित द्वीप' हैं. विशाल विमान सेवाओं को जगह देने के लिए अगाती हवाई पट्टी के विस्तार की योजना भी है. कब हम विकास के नाम पर लालच को रोकना सीखेंगे?

सैयदा हमीद सामाजिक और महिला अधिकार कार्यकर्ता, शिक्षाविद् और लेखिका हैं.

इलस्ट्रेशनः सिद्धांत जुमडे

मनीष अग्निहोत्री

उत्तर प्रदेश

कोविड प्रभावित गांव हैं चुनाव की समरभूमि

आशीष मिश्र

मई की 22 तारीख को, समाजवादी पार्टी (सपा) के संरक्षक मुलायम सिंह यादव के पैतृक गांव सैफई का पहली बार किसी गैर-सपाई मुख्यमंत्री ने दौरा किया. दरअसल, उत्तर प्रदेश में भाजपा सरकार के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, इटावा जिले के सैफई में स्थित उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय के कुलाधिपति हैं. सैफई विश्वविद्यालय के 200 बिस्तरों वाले एल-3 कोविड अस्पताल और सैफई ब्लॉक के गीजा गांव में कोविड को लेकर सरकारी तैयारियों का निरीक्षण करने के बहाने, योगी का गांव का यह दौरा एक सुविचारित कदम था.

सैफई गांव मुलायम सिंह के संसदीय क्षेत्र मैनपुरी का हिस्सा होने के साथ-साथ जसवंत नगर विधानसभा क्षेत्र का भी हिस्सा है जिसका प्रतिनिधित्व उनके भाई और सपा के बागी नेता शिवपाल सिंह यादव करते हैं. तो, सैफई एक तरह से इटावा और आसपास के कई जिलों में सपा की राजनीति का केंद्र बिंदु है. साल 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में इटावा संसदीय क्षेत्र में जीत हासिल करने वाली भाजपा का, इस साल अप्रैल में हुए पंचायत चुनाव में प्रदर्शन काफी खराब रहा. सत्ताधारी दल, इटावा की जिला पंचायत की 24 सीटों में से केवल एक ही जीत सका. सपा और शिवपाल सिंह यादव की प्रगतिशील समाजवादी पार्टी (लोहिया) ने एक साथ चुनाव लड़ा और इटावा की 24 में से 20 सीटों पर जीत हासिल की.

पंचायत चुनाव के नतीजों ने भाजपा में खतरे की घंटी बजा दी है. योगी पिछले चार साल में दो बार इटावा आए थे, लेकिन उन्होंने जान-बूझकर सैफई जाने से परहेज किया था. उनके इस दौरे को पंचायत चुनाव में हार के बाद अपनी खोई जमीन को वापस पाने का एक प्रयास माना गया. योगी ने सैफई विश्वविद्यालय में ऑक्सीजन संयंत्र का काम दो सप्ताह में पूरा करने का आदेश दिया और अधिकारियों को क्षेत्र में कोविड पीड़ितों का पता लगाने और गांवों में निगरानी समितियों के माध्यम से उन्हें तत्काल उपचार प्रदान करने के लिए कहा. यूपी के करीब 89,512

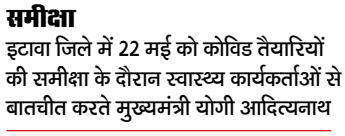

समीक्षा
इटावा जिले में 22 मई को कोविड तैयारियों की समीक्षा के दौरान स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं से बातचीत करते मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ

गांवों में अब सक्रिय निगरानी समितियां हैं. उनके प्रयासों से 28,742 गांवों में कोविड के मरीज पाए गए हैं. सरकारी आंकड़े बताते हैं कि यूपी के एक-तिहाई गांव कोविड वायरस से प्रभावित हुए हैं.

अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी (एएमयू) सेंटर फॉर कम्परेटिव लिटरेचर में पढ़ाने वाले प्रो. जसीम मोहम्मद कहते हैं, ''2022 के विधानसभा चुनाव में अब आठ महीने से भी कम समय बचा है. उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार गांवों में कोविड के प्रसार को रोकने में पूरी तरह असफल साबित हुई है. पंचायत चुनावों में भाजपा के बेहद खराब प्रदर्शन की वजह यही रही. आदित्यनाथ अब डैमेज कंट्रोल मोड में हैं, इसलिए वे गांव-गांव जा रहे हैं.''

भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने इसका खंडन करते हुए कहा, ''पंचायत चुनाव में भाजपा के खराब प्रदर्शन की बातें पूरी तरह से निराधार हैं. 2015 में, हमने केवल 200 जिला पंचायत सदस्य सीटें जीतीं थीं; इस बार हमने 954 सीटें जीती हैं. गांवों में भाजपा का जनाधार और मजबूत हुआ है.''

पंचायत चुनाव खत्म होने के बाद गांवों में कोविड के मामले तेजी से बढ़ने लगे. मई के पहले सप्ताह में यूपी में हर दिन 25,000 से अधिक कोविड के नए मामले देखे गए. योगी ने 8 मई को मुरादाबाद दौरे के बाद जिलों में अपने दौरे शुरू किए. मुख्यमंत्री 31 मई तक यूपी के सभी 18 संभागों के 50 जिलों का दौरा कर चुके थे. वे हर जिले में कम-से-कम एक गांव का दौरा करते हैं और स्वास्थ्य सुविधाओं पर मरीजों से फीडबैक भी लेते हैं.

जय नारायण पीजी कॉलेज, लखनऊ में राजनीति विज्ञान विभाग के एसोसिएट प्रोफेसर बृजेश मिश्र योगी के दौरों को संदर्भ में रखते हुए संख्याओं की व्याख्या करते हैं. मिश्र कहते हैं, ''यूपी की 70 प्रतिशत से अधिक आबादी गांवों में रहती है. अनुपात में देखा जाए तो राज्य की कुल 403 विधानसभा सीटों में से 250 से ज्यादा सीटों पर ग्रामीण मतदाता निर्णायक हैं. 2017 के विधानसभा चुनाव में भाजपा ने 312 सीटें जीती थीं, लेकिन पंचायत चुनावों में उसका खराब प्रदर्शन गांवों में पार्टी की पकड़ के कमजोर होने का संकेत देता है. यही कारण है कि विपक्षी दलों को गांवों में अपना आधार बढ़ता दिख रहा है.''

पंचायत चुनाव आमतौर पर पार्टी के चुनाव चिन्ह पर नहीं लड़े जाते, इसलिए पार्टियां चुनाव परिणामों को लेकर तरह-तरह के दावे कर रही हैं. लेकिन इस साल पहली बार राजनैतिक दलों ने यूपी की 3,051 जिला पंचायत सदस्य सीटों पर चुनाव लड़ा. भाजपा और सपा, दोनों पार्टियां अब दावा कर रही हैं कि उन्होंने 900 से ज्यादा जिला पंचायत सदस्य सीटें जीती हैं. बसपा का कहना है कि उसने 500 सीटों पर कब्जा किया है, जबकि कांग्रेस

ग्रामीण वोट

77%
है उत्तर प्रदेश की ग्रामीण आबादी (जनगणना 2011)

250
सीटों (यूपी विधानसभा के कुल 403 सीटों में से) पर ग्रामीण वोट बेहद महत्वपूर्ण है

59,000
प्रधान चुने गए हैं ग्राम पंचायतों में, जिनका समर्थन साल 2022 के विधानसभा चुनावों में बेहद महत्वपूर्ण साबित होगा

312
सीटें भाजपा ने हासिल की थी 2017 के विधानसभा चुनावों में

का 200 से अधिक सीटों पर जीत का दावा है. अगर इन पार्टियों के दावों को ही सही मानकर चलें तो भाजपा जिला पंचायत सदस्यों की कुल सीटों में से एक तिहाई भी नहीं जीत पाई है. डॉ. भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय, लखनऊ में इतिहास विभाग के एसोसिएट प्रोफेसर सुशील पांडे ने यूपी की जाति की राजनीति पर शोध किया है. वे कहते हैं, ''2017 के विधानसभा चुनाव में, भाजपा को गांवों में कुर्मी, निषाद, बिंद, विश्वकर्मा, कश्यप, कुशवाहा और भुरजी जैसी कई पिछड़ी जातियों का समर्थन मिला था. सामूहिक रूप से, ये जातियां उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या का 10 प्रतिशत से अधिक हैं. ये गरीब पिछड़ी जातियां कोविड संक्रमण की दूसरी लहर के दौरान गांवों में मची अफरा-तफरी के कारण भाजपा से नाराज हैं. इन जातियों का समर्थन हासिल करने के लिए विपक्षी दल, गांवों में कोविड पीड़ितों की मदद के लिए डेरा डाले हुए हैं.''

सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पार्टी के युवा नेताओं के साथ समाजवादी पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ को यह जिम्मेदारी सौंपी है. अखिलेश ने अगस्त 2020 में युवा नेता और एमएलसी राजपाल कश्यप (जो पिछड़ी निषाद जाति के हैं) को समाजवादी पिछड़ा प्रकोष्ठ का प्रदेश अध्यक्ष बनाया था. यह कोविड की पहली लहर के संक्रमण काल के दौरान हुआ था. कश्यप ने पहली बार सपा पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ की प्रदेश से लेकर ब्लॉक स्तर तक, कार्यकारिणी समितियों का गठन किया जो अब पार्टी के लिए सक्रिय रूप से काम करने लगी हैं. कश्यप कहते हैं, ''हम 21 सदस्यीय कार्यकारी समिति के माध्यम से गांवों में कोविड पीड़ितों की पहचान करने और ब्लॉक स्तर पर तुरंत उपचार प्रदान करने में सक्षम हुए हैं. कार्यकारिणी के प्रत्येक नेता को 20-25 गांवों की जिम्मेदारी दी गई है. वे कोविड पीड़ितों की जानकारी लेने और उनकी पहचान करने के लिए नियमित रूप से अपने निर्धारित गांवों के दौरे कर रहे हैं.''

सपा नेता 'समाजवादी किचन' भी चला रहे हैं, जो कोविड मरीजों और पृथकवास (आइसोलेशन) में रह रहे लोगों के परिवारों को खाना मुहैया कराता है. इसके अलावा पिछड़े प्रकोष्ठ के नेताओं ने कोविड मरीजों को आवश्यक दवाओं से युक्त आइसोलेशन किट बांटी है. पार्टी ने दूरदराज के गांवों में गंभीर रूप से बीमार कोविड मरीजों को जिला कोविड अस्पतालों तक पहुंचाने के लिए एंबुलेंस की भी व्यवस्था की है. मेरठ में सपा के जिलाध्यक्ष राजपाल सिंह ने मई में खुद गांवों के 100 से अधिक कोविड रोगियों को शहर के एल-2 कोविड अस्पतालों (अधिक गंभीर मामलों के लिए) में भर्ती कराया है. कश्यप कहते हैं, ''सपा हर गांव में जरूरतमंदों तक पहुंचने की कोशिश कर रही है. हम कोविड से प्रभावित लोगों को भोजन और दवाएं उपलब्ध कराने के अलावा बच्चों को किताबें भी उपलब्ध करा रहे हैं.''

मनीष अग्निहोत्री

अब गांवों में विपक्षी दलों की बढ़ती सक्रियता से निबटने के लिए योगी सरकार ने भी आपनी ताकत झोंक दी है. मुख्यमंत्री योगी ने सभी जिलों के जिलाधिकारियों को गांवों में 'मेरा गांव-कोरोना मुक्त गांव' अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं. इसमें कोरोना नियंत्रण को लेकर सबसे अच्छा काम करने वाले तीन गांवों को पुरस्कार दिया जाएगा. इसके अलावा इन गांवों को सरकार की तरफ से विकास के लिए अतिरिक्त धनराशि भी मुहैया कराई जाएगी. योगी ने सभी भाजपा विधायकों से गांव के अस्पतालों को भी गोद लेकर वहां चिकित्सकीय सुविधाएं मुहैया कराने की अपील की है.

साल 2022 के विधानसभा चुनाव में यूपी की 59,000 ग्राम पंचायतों में नवनिर्वाचित प्रधानों का समर्थन महत्वपूर्ण साबित हो सकता है. मेरठ कॉलेज के अर्थशास्त्र विभाग में एसोसिएट प्रोफेसर और यूपी की ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर गहरी जानकारी रखने वाले मनोज सिवाच कहते हैं, ''हर गांव में, नवनिर्वाचित ग्राम प्रधानों के पास बड़ी संख्या में उनके समर्थक होंगे. ऐसे में इन प्रधानों का समर्थन पार्टियों के लिए गांवों में अपनी स्थिति मजबूत करने में काफी मददगार साबित हो सकता है.'' इसे ध्यान में रखते हुए, योगी आदित्यनाथ ने 28 मई को नवनिर्वाचित प्रधानों के साथ एक वर्चुअल मीटिंग की, जिसमें उन्होंने अन्य बातों के अलावा गांवों में मुफ्त राशन वितरण पर चर्चा की.

योगी की वर्चुअल मीटिंग से दो दिन पहले 26 मई को कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव और यूपी प्रभारी प्रियंका गांधी ने प्रदेश के सभी नए ग्राम प्रधानों को पत्र लिखकर चुनाव जीतने पर बधाई दी और उनसे अपील की कि कोविड के खिलाफ इस युद्ध को एकजुट होकर लड़ने के लिए कांग्रेस के साथ आएं. पार्टी ने गांवों में कोविड-देखभाल सहायता प्रदान करने के लिए 'सेवा सत्याग्रह' कार्यक्रम भी शुरू किया है. अभियान के तहत, प्रियंका ने 10 लाख होम आइसोलेशन किट की व्यवस्था की है, जो मुख्य रूप से यूपी के गांवों में वितरित की जाएंगी. 26 मई को कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने लखनऊ में कांग्रेस मुख्यालय से आइसोलेशन किट वाले वाहनों को जिलों में भेजा.

पार्टी प्रवक्ता प्रियंका गुप्ता कहती हैं, ''अप्रैल में जैसे ही कोविड संक्रमण बढ़ने लगा, हमने लखनऊ स्थित राज्य मुख्यालय के अलावा सभी जिलों में कोविड हेल्प डेस्क शुरू कर दिए थे. इसके जरिए कोविड पीड़ितों की हर संभव मदद की जा रही है.'' कांग्रेस ने यूपी में सेवा सत्याग्रह के तहत 'मेरा गांव, मेरा अभियान' कार्यक्रम भी शुरू किया है. लल्लू बताते हैं, ''इसके तहत राज्य के सभी गांवों में सेनिटाइजेशन का काम शुरू कर दिया गया है.

इस बात को ध्यान में रखते हुए योगी ने नवनिर्वाचित ग्राम प्रधानों के साथ वर्चुअल मीटिंग की कि 2022 के विभानसभा चुनावों में उनका समर्थन अहम साबित होगा

भोजन का इंतजाम
हरदोई में 26 मई को समाजवादी राशन और भोजन के पैकेट वितरित करते सपा पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के प्रमुख राजपाल कश्यप

पार्टी ने इसके लिए 15 लाख लीटर सैनिटाइजर की व्यवस्था की है. गांवों में भी सैनिटाइजर टैंक भेजे जा रहे हैं. गांवों में होम आइसोलेशन में रह रहे कोविड पीड़ितों के लिए कांग्रेस के पदाधिकारी भी दवाओं का इंतजाम कर रहे हैं. यह पंचायत स्तर पर पार्टी समितियों के माध्यम से किया जा रहा है.''

यूपी के गांवों में कोरोना से हुई मौतों के आंकड़े सार्वजनिक नहीं करने के लिए कांग्रेस, भाजपा सरकार पर आरोप लगा रही है. पार्टी ने पूर्व केंद्रीय मंत्री सलमान खुर्शीद की अध्यक्षता में इसके लिए एक सात सदस्यीय फैक्ट फाइंडिंग कमिटी का गठन किया है. कमिटी एक महीने के अंदर अपनी रिपोर्ट देगी. हालांकि भाजपा, कांग्रेस के इन कदमों को दिखावा बताती है. स्वतंत्र देव सिंह कहते हैं, ''मई के पहले सप्ताह में यूपी में कोविड संक्रमण दर 10 फीसद से ज्यादा थी, अब एक फीसद से भी कम है. ऐसा इसलिए है क्योंकि योगी सरकार ने त्वरित कदम उठाए; हमने अपनी 72,000 निगरानी समितियों के 4,00,000 सदस्यों को स्क्रीनिंग करने के लिए गांवों और कस्बों में घर-घर भेजा.''

जाहिर है, हर पार्टी को इस बात का एहसास है कि यूपी के गांव ही विधानसभा के लिए आगामी चुनावी समर के केंद्र बिंदु होंगे. गांव जिनके साथ खड़े हो जाएंगे, उसके लिए लखनऊ की राह आसान हो जाएगी. ■

सूचकांक/टीकाकरण

डबल डोज वाले कितने

साढ़े पांच महीनों से चल रहे कोविड के टीकाकरण अभियान में 1 जून तक पांच करोड़ से भी कम लोगों को दोनों वैक्सीन लग सकी जबकि करीब 30 करोड़ आबादी 45 वर्ष की उम्र से अधिक है, जिसे दोनों टीके लगने हैं. राजस्थान के नागौर जैसे पिछड़े जिले में 2 लाख से ज्यादा लोगों को दूसरी डोज लग चुकी है. लेकिन वाराणसी, गोरखपुर, रायबरेली और अमेठी जैसे जिलों में यह आंकड़ा एक लाख से पीछे था.

मनीष दीक्षित

173 करोड़
टीकों की जरूरत थी देश को 18 साल से ऊपर की आबादी के लिए. टीकाकरण शुरू होने के 136 दिन बाद 151.4 करोड़ टीकों की जरूरत

106 जिलों
में ही दोनों टीका लगवा चुके लोगों की संख्या 1 लाख से ऊपर गई है जबकि देश में 718 जिले हैं

4.48 करोड़
पूर्ण टीकाकरण (दोनों डोज) 16 जनवरी 2021 से

21.60 करोड़
कुल टीकाकरण (पहली+दूसरी डोज)

टीके की रफ्तार

(कुल टीके और राज्यवार 1 लाख से ज्यादा डबल डोज वाले जिले)

1 लाख से अधिक लोगों को दोनों टीके लगाने वाले जिले

0 कुल टीके

नोटः ये आंकड़े 1 जून 2021 दोपहर तक के हैं.

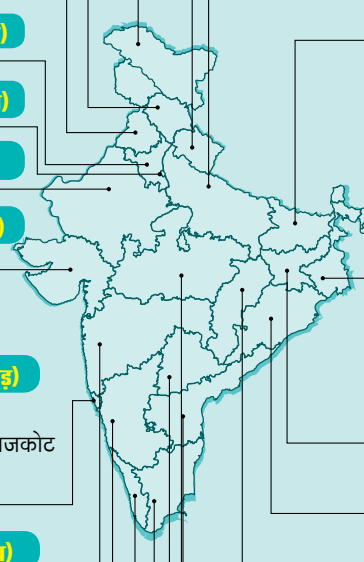

जम्मू-कश्मीर (33.16 लाख) — 1 जिला (जम्मू)

हिमाचल प्रदेश (24.66 लाख) — 0 जिला

पंजाब (46.62 लाख) — 1 जिला (लुधियाना)

हरियाणा (59.26 लाख) — 1 जिला (गुड़गांव)

दिल्ली (54.33 लाख) — 12.30 लाख

राजस्थान (1.3 करोड़) — 11 जिले (अजमेर, अलवर, बाड़मेर, बीकानेर, जयपुर 1 व 2, उदयपुर, सीकर, नागौर, जोधपुर, झुंझुनूं)

गुजरात (1.72 करोड़) — 16 जिले (अहमदाबाद निगम, आनंद, अरावली, बनासकांठा, भरूच, दाहोद, वलसाड, वडोदरा निगम, सूरत निगम, साबरकांठा, राजकोट निगम, पंचमहल, नवसारी, मेहसाणा, कच्छ, खेड़ा)

गोवा (5.3 लाख) — 95 हजार

महाराष्ट्र (2.26 करोड़) — 13 जिले(अहमदनगर, अमरावती, औरंगाबाद, जलगांव, कोल्हापुर, मुंबई, नागपुर, ठाणे, सोलापुर, सतारा, सांगली, पुणे, नासिक)

कर्नाटक (1.37 करोड़) — 6 जिले (बीबीएमपी, बेलगाम, बेल्लारी, दक्षिण कन्नड़, तुमकूर, मैसूर)

केरल (95.09 करोड़) — 10 जिले (अलप्पुझा, एर्णाकुलम, कुन्नूर, कोट्टयम, कोझिकोड, मलापुरम, पलक्कड़, पथनामथिट्टा, तिरुवनंतपुरम, थ्रिसूर,)

आंध्र प्रदेश (99.80 लाख) — सभी 13 जिले

तेलंगाना (61.18 लाख) — 3 जिले (हैदराबाद, मेडचल, रंगारेड्डी)

तमिलनाडु (91.64 लाख) — 2 जिले (चेन्नै, कोयंबटूर)

उत्तराखंड (29.27 लाख) — 1 जिला (देहरादून)

उत्तर प्रदेश (1.85 करोड़) — 4 जिले (गौतम बुद्ध नगर, प्रयागराज, लखनऊ, कानपुर नगर)

बिहार (1.03 करोड़) — 1 (पटना)

असम (41.59 लाख) — 0 जिले

त्रिपुरा (16.13 लाख) — 1 (वेस्ट त्रिपुरा)

पश्चिम बंगाल (1.48 करोड़) — 14 जिले (बांकुरा, दार्जिलिंग, डायमंड हार्बर, ईस्ट बर्धमान, हुगली, हावड़ा, कोलकाता, मालदा, मुर्शिदाबाद, दक्षिण 24 परगना, पूर्व मिदनापुर, पश्चिम मिदनापुर, उत्तर 24 परगना, नादिया)

झारखंड (42.10 लाख) — 0 जिले

ओडिशा (79.21 लाख) — 2 जिले (गंजम, खुर्दा)

छत्तीसगढ़ (62.45 लाख) — 3 (रायपुर, रायगढ़, दुर्ग)

मध्यप्रदेश (1.11 करोड़) — 3 जिले (भोपाल, इंदौर, जबलुपर)

अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नगालैंड, सिक्किम, पुदुच्चेरि और केंद्र शासित शहरों में डबल डोज लेने वालों की संख्या 1 लाख से नीचे है. दिल्ली और गोवा के आंकड़े पूरे राज्य के हैं. क्षेत्र कम होने के कारण प्रशासनिक जिलों अनुसार आंकड़े नहीं दिए गए हैं.

37,262
वैक्सीन सेंटर हैं देश में जिनमें से 1,295 प्राइवेट सेक्टर में हैं

स्रोतः cowin.gov.in

पंजाब

अमरिंदर इस तूफान से पार पा जाएंगे?

अनिलेश एस. महाजन

यह पहली बार नहीं है जब पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह को पार्टी के भीतर से उठे असंतोष का सामना करना पड़ रहा है. मुख्यमंत्री के रूप में अपने पहले कार्यकाल (2002-07) के दौरान, साल 2005 में उनकी डिप्टी राजिंदर कौर भट्टल ने विद्रोह का नेतृत्व किया था. भट्टल ने 25 कांग्रेस विधायकों के साथ नई दिल्ली में डेरा डाल लिया था और कैप्टन को उनके पद से हटाने की मांग पर अड़ गई थीं. बागी खेमे का आरोप था कि अमरिंदर अपने कुछ चहेते अधिकारियों की एक टोली के साथ सरकार चलाते हैं, निर्णय लेते समय पार्टी विधायकों के विचारों की अनदेखी करते हैं और भ्रष्ट मंत्रियों के खिलाफ कार्रवाई की हिम्मत नहीं जुटा पाते. हालांकि कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के समर्थन से कैप्टन उस विद्रोह के बावजूद बच गए, लेकिन कुछ उसी प्रकार के संकट से वे अपने दूसरे कार्यकाल में घिरे दिखते हैं और उनके कैबिनेट के सहयोगी तथा पार्टी के विधायक खुले तौर पर उनके आदेशों की अवहेलना कर रहे हैं.

मई के अंत में, कांग्रेस ने अमरिंदर के खिलाफ शिकायतों की जांच के लिए राज्यसभा सांसद मल्लिकार्जुन खड़गे, (ऑल इंडिया कांग्रेस कमिटी) एआइसीसी महासचिव और पंजाब प्रभारी हरीश रावत और पूर्व सांसद जे.पी. अग्रवाल की तीन सदस्यीय समिति का गठन किया. समिति ने असंतुष्टों से मुलाकात की है, जिनमें कैबिनेट मंत्री चरणजीत सिंह चन्नी और सुखजिंदर सिंह रंधावा, राज्य विधानसभा अध्यक्ष राणा के.पी. सिंह, क्रिकेटर से नेता बने नवजोत सिंह सिद्धू और 23 विधायक शामिल हैं. इस बात की पूरी संभावना है कि पैनल अमरिंदर के करीबी माने जाने वाले अन्य मंत्रियों की राय लेने के साथ-साथ पंजाब कांग्रेस के पूर्व प्रमुख प्रताप सिंह बाजवा, शमशेर सिंह डुल्लो, मोहिंदर सिंह केपी और राजिंदर कौर भट्टल से भी राय-मशविरा करेगा. इनमें से कई नेता अमरिंदर के धुर विरोधी माने जाते हैं.

पंजाब कांग्रेस में पिछले दो वर्षों से जबरदस्त गुटबाजी देखी जा रही है, लेकिन हाल के कुछ घटनाक्रम ने स्थिति को गंभीर बना दिया है. राजनैतिक रूप से महत्वाकांक्षी सिद्धू, कई मुद्दों को लेकर अमरिंदर सिंह सरकार पर हमले करते रहे हैं. इससे बागियों को शह मिली. वे एकजुट होकर मई में लगातार बैठकें करते रहे. सिद्धू का दावा है कि राज्य का सतर्कता विभाग उनके समर्थकों को डरा रहा है, जबकि हॉकी खिलाड़ी से विधायक बने परगट सिंह ने

अपनों से घिरे पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह

एएनआइ

मुख्यमंत्री कार्यालय के एक अधिकारी पर उन्हें धमकाने का आरोप लगाया है. आखिरकार, मई के अंतिम सप्ताह में कांग्रेस महासचिव (संगठन) के.सी. वेणुगोपाल ने चन्नी को सूचित किया कि असंतुष्ट नेताओं की बात सुनने के लिए एक कमेटी गठित कर दी गई है.

बंटी हुई कांग्रेस

अमरिंदर को सोनिया गांधी का करीबी माना जाता है, जबकि सिद्धू और चन्नी जैसे उनके विरोधी राहुल गांधी और प्रियंका गांधी-वाड्रा का वरदहस्त प्राप्त है. दोनों भाई-बहन सिद्धू को ऐसे करिश्माई नेता के रूप में देखते हैं जो पंजाब के युवाओं के बीच अच्छी पकड़ रखते हैं. लेकिन हाल के विधानसभा चुनावों में राहुल और प्रियंका गांधी की विफलता को देखते हुए, यह कहना मुश्किल है कि पंजाब में, पार्टी के मामलों में राहुल और प्रियंका की कितनी चलेगी. पंजाब में 10 महीने में चुनाव होने वाले हैं.

पंजाब एकमात्र कांग्रेस शासित राज्य है जिसने 2014 के बाद से नरेंद्र मोदी की लहर को लगातार बेअसर किया है. पार्टी के राज्य से आठ लोकसभा सांसद (कुल 13 में से 8) और 117 सदस्यीय विधानसभा में 80 विधायक हैं. पार्टी के रणनीतिकारों का एक भी गलत कदम भाजपा को चुनावी लाभ दे सकता है, जो लंबे समय से चल रहे किसानों के आंदोलन और अपने पुराने सहयोगी शिरोमणि अकाली दल के राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन से अलग होने के कारण पंजाब में बैकफुट पर है. भाजपा नेता कांग्रेस के असंतुष्टों की पीठ ठोक रहे हैं तो सिद्धू पर आप (आम आदमी पार्टी) डोरे डाल रही है.

वहीं, दिल्ली में कांग्रेस के शीर्ष नेताओं ने *इंडिया टुडे* को बताया कि पंजाब में एक नए मुख्यमंत्री को गद्दी देने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता है. उन्होंने कहा कि आगामी विधानसभा चुनावों के लिए सारे प्रयास अमरिंदर के समर्थकों तथा उनके विरोधी खेमे को एक साथ लाने के लिए होंगे. लेकिन यह कहना जितना आसान है, करना उतना ही मुश्किल. असंतुष्टों के मन में अमरिंदर के खिलाफ कई शिकायतें हैं. वे विभिन्न बोर्डों और राज्य निकायों में राजनैतिक नियुक्तियों को लेकर बुरी तरह चिढ़े हुए हैं. अपने निर्वाचन क्षेत्रों के लिए विकास निधि जारी करने में 'जानबूझकर विलंब', अमरिंदर के विधायकों के लिए उपलब्ध नहीं होने और सरकार चलाने के लिए नौकरशाहों पर उनकी अत्यधिक निर्भरता से पार्टी के विधायक नाराज हैं. वहीं, वे मुख्यमंत्री के करीबी मंत्रियों और अधिकारियों पर भी भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं.

इन सबसे बढ़कर, 2015 में पंजाब में गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी की घटना अमरिंदर के लिए एक नए विवाद के रूप में सामने आई है. इस साल अप्रैल में, पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने 2015 में फरीदकोट जिले में बेअदबी की उस घटना के विरोध में हुए प्रदर्शन के दौरान हुई पुलिस फायरिंग की एसआइटी (विशेष जांच दल) की जांच पर प्रतिकूल टिप्पणी की और इसकी रिपोर्ट को खारिज कर दिया. इस भावनात्मक मुद्दे पर सबसे पहले सिद्धू ने अमरिंदर को घेरा और बहुत आक्रामक रुख अपनाया था. लेकिन जेल में बंद डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख गुरमीत राम रहीम के साथ अपनी तस्वीरें सामने आने के बाद सिद्धू नरम पड़ गए.

जिन विकल्पों की चर्चा है उनमें अमरिंदर के कुछ भरोसेमंद नौकरशाहों को किनारे लगाना; और एक नई चुनाव प्रचार समिति का गठन करना शामिल है जो उम्मीदवारों के चयन में मुख्यमंत्री को पूरी छूट से वंचित करती है

पंजाब में विभिन्न सिख समूहों का आरोप है कि उन बेअदबी की घटनाओं के पीछे डेरा के शीर्ष पदाधिकारियों का हाथ है. डेरा सच्चा सौदा पर लगे आरोप अमरिंदर के लिए शर्मिंदगी की वजह बन रहे हैं, क्योंकि अतीत में उन्होंने गुरमीत राम रहीम का खुलकर समर्थन किया था.

पंजाब के मालवा क्षेत्र के दलित सिखों के बीच डेरा का अच्छा-खासा प्रभाव है. दलित सिखों का उच्च जाति के सिखों, विशेष रूप से जमींदार जाट सिख समुदाय, के साथ तनावपूर्ण समीकरण है जो पिछले सितंबर में केंद्र की ओर से लाए गए विवादास्पद कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन में सबसे आगे रहा है. राज्य कांग्रेस को चिंता है कि मालवा का उसका पारंपरिक वोट बैंक कहीं छिटककर शिरोमणि अकाली दल और भाजपा जैसे विपक्षी दलों के हाथों में न चला जाए.

सिद्धू का भले ही कांग्रेस विधायकों या जमीनी कार्यकर्ताओं पर ज्यादा प्रभाव न हो, लेकिन अमरिंदर के खिलाफ उनके हमले ने असंतुष्टों को बगावत का बल तो दिया ही है. अमरिंदर ने अमृतसर पूर्व से विधायक सिद्धू पर पलटवार करते हुए दावा किया कि वे केवल कांग्रेस छोड़ने का कोई बहाना तलाश रहे थे, हालांकि उनके पास कांग्रेस के बाहर वास्तव में बहुत कम विकल्प हैं. उन्होंने सिद्धू को उपमुख्यमंत्री या प्रदेश कांग्रेस कमेटी (पीसीसी) अध्यक्ष जैसे किसी आकर्षक पद का प्रस्ताव देकर उन्हें शांत करने से भी साफ इनकार कर दिया है.

संकट प्रबंधन

कैप्टन के लिए थोड़ी राहत की बात यह है कि असंतुष्टों ने भले ही उनके खिलाफ झंडा उठा लिया हो, लेकिन एक नेता के नाम पर उनके बीच भी आम सहमति नहीं है. हालांकि, राजनैतिक टकराव के थमने के कोई संकेत नहीं दिख रहे, ऐसे में मुख्यमंत्री के लिए अपने विश्वासपात्र सुनील जाखड़ को पीसीसी अध्यक्ष बनाए रखते हुए सरकार को आसानी से चलाना मुश्किल हो सकता है. बगावत को शांत कराने का प्रयास कर रहे कांग्रेस नेताओं की ओर से जिन समाधान पर विचार किया जा रहा है उनमें कैबिनेट में फेरबदल का विकल्प भी है. कुछ विवादास्पद मंत्रियों को हटाया जा सकता है और कुछ अन्य दलित चेहरे लाए जा सकते हैं. इसके अलावा जिन विकल्पों की चर्चा है उनमें अमरिंदर के कुछ भरोसेमंद नौकरशाहों को किनारे लगाना; और एक नई चुनाव प्रचार समिति का गठन करना शामिल है जो उम्मीदवारों के चयन में मुख्यमंत्री को पूरी छूट से वंचित करती है.

साल 2005 में, अमरिंदर को सोनिया गांधी, उनके राजनैतिक सलाहकार अहमद पटेल और तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने बागी संकट से उबारा था. लेकिन वे इस बात को बखूबी समझते हैं कि इस बार उतना मजबूत समर्थन उन्हें शायद ही मिल पाए. बाजवा जैसे विद्रोहियों के खिलाफ उनकी शिकायतों को केंद्रीय नेतृत्व ने अक्सर अनसुना ही किया है.

असंतुष्टों ने इस बार सरकार के साथ तगड़ी सौदेबाजी के मंसूबे बांध रखे हैं और आलाकमान उन पर लगाम लगाने में अनिच्छुक दिखता है. कहा जा सकता है कि यह कैप्टन के लिए चिंताओं से भरा चुनावी साल है. क्या वे अपने जहाज को इस तूफान से सुरक्षित बाहर निकाल पाएंगे? ■

खाद्य तेल

क्यों सुलग उठी रसोई?

शुभम शंखधर

पश्चिम दिल्ली के टैगोर गार्डन में रहने वाले 40 वर्षीय अजय कुमार को इन दिनों कोरोना वायरस के अलावा महंगाई भी डरा रही है. महीने के राशन का बिल बिना सामान बढ़ाए भी बढ़ा जा रहा है. एक लीटर सरसों तेल की कीमत 192 रुपए लीटर तक पहुंच गई, जो बीते साल के करीब डेढ़ गुना ज्यादा है. बीते साल (25 मई, 2020) भाव 132 रुपए लीटर का था. लेकिन हर स्तर पर खलबली मचाकर रखने वाले मौजूदा समय के कड़ाह में सरसों ही नहीं, खाद्य तेल का पूरा बाजार ही खौल रहा है. वनस्पति, सोया तेल, सूरजमुखी, मूंगफली सभी के भाव चढ़े हैं (देखें ग्राफिक्स). खाद्य तेलों में यह तेजी ठीक उस समय देखने को मिली है, जब देश में एक के बाद एक सामान्य मॉनसून, तिलहन की रिकॉर्ड पैदावार और लॉकडाउन के कारण मांग में नरमी है. यानी कीमतों में इजाफे का कोई भी कारण घरेलू नहीं. महंगाई अंतरराष्ट्रीय है.

तो आंच हम पर क्यों?

भारत में तिलहन की पैदावार बीते पांच वर्षों में 44 फीसद से ज्यादा बढ़ी है. साल 2020-21 में कुल 365.65 लाख टन तिलहन की पैदावार का पूर्वानुमान है. 2015-16 में कुल 252.51 लाख टन तिलहन पैदा हुई थी. हालांकि इस रिकॉर्ड पैदावार के बाद भी हम अपनी जरूरत का आधे से कम खाद्य तेल उपलब्ध करवा पाते हैं. देश में प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष 19 किलोग्राम की मौजूदा खपत के आधार पर कुल 2.5 करोड़ टन खाद्य तेल की मांग है, इसमें से 1.05 करोड़ टन की आपूर्ति ही घरेलू स्तर पर हो पाती है. बाकी 60 फीसद खपत आयात पर निर्भर है. विभिन्न कारणों से अंतरराष्ट्रीय बाजारों में तिलहन और खाद्य तेल की कीमतें रिकॉर्ड ऊंचाई पर हैं, जिसका असर घरेलू बाजार पर भी देखने को मिल रहा है.

विश्व बाजार में क्यों लगी है आग?

देश में कुल खाद्य तेल आयात में 86 फीसद हिस्सेदारी पाम और सोयाबीन तेल की है. तो पहले बात पाम ऑयल की. मलेशिया और इंडोनेशिया दुनिया के सबसे बड़े पाम ऑयल निर्यातक देश हैं. यहां पाम ऑयल की कीमतें बीते एक साल में तेजी से बढ़ी हैं. बुर्सा मलेशिया डेरेवेटिव्ज एक्सचेंज पर पाम ऑयल के वायदा ने मई में 4,525 रिंगिट का ऊपरी भाव छुआ. बीते साल मई में कीमतें 1,939 रिंगिट के निचले स्तर तक गई थीं. इस हिसाब से कीमतें सालभर में 133 फीसद से ज्यादा बढ़ीं. फिलहाल, भाव 3,910 रिंगिट के करीब हैं. यानी 1 टन पॉम ऑयल की कीमत करीब 67,000 रुपए. (1 जून को) के स्तर पर है.

पाम ऑयल की कीमतों में तेजी का गणित समझाते हुए द सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (एसईएआइ) के एग्जीक्युटिव डायरेक्टर बी.वी. मेहता कहते हैं, ''पाम ऑयल क्षेत्र गहन श्रम वाला क्षेत्र है. यहां बड़ी संख्या में श्रमिकों की जरूरत होती है. दुनिया के सबसे बड़े निर्यातक देशों में शुमार मलेशिया में पाम ऑयल क्षेत्र की निर्भरता प्रवासी मजदूरों पर है.'' कोविड के कारण बॉर्डर बंद हुए, जिस वजह से श्रमिकों की कमी हुई और उत्पादन प्रभावित हुआ. वे तेजी का एक और बड़ा कारण खाद्य तेलों की मांग का ईंधन क्षेत्र में बढ़ना भी मानते हैं. इंडोनेशिया के बायोडीजल कार्यक्रम में मिश्रण के लिए 30 फीसद पाम ऑयल का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसकी वजह से मांग में लगातार इजाफा हो रहा है.

अब बात सोयाबीन की. अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोयाबीन की कीमत बीते एक साल में 80 फीसद से ज्यादा बढ़ी है. हालांकि पिछले दो हफ्तों से कुछ नरमी देखने को मिली है. फिलहाल, सोयाबीन का जुलाई में 1,542 डॉलर (1 जून) के करीब वायदा कारोबार कर रहा है, जो 12 मई को 1,667 डॉलर के स्तर पर था. बीते साल 1 जून को भाव 840 डॉलर के करीब थे. ब्राजील और अमेरिका दुनिया के सबसे ज्यादा सोयाबीन पैदा करने वाले देश हैं.

भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के महामंत्री हेमंत गुप्ता खाद्य तेलों में तेजी की वजहें बताते हुए कहते हैं, ''चीन सोयाबीन की जबरदस्त खरीदारी किए जा रहा है, जो कीमतों में इजाफे का एक बड़ा कारण है.'' 2021 के पहले चार महीनों (जनवरी से अप्रैल) में चीन ने करीब 2.86 करोड़ टन सोयाबीन का आयात किया, जो पिछले वर्ष की इसी अवधि के मुकाबले 17 फीसद ज्यादा है. वे यह भी कहते हैं, ''दुनिया के सबसे बड़े निर्यातक देश ब्राजील में आई बाढ़ के कारण फसल की कटाई और निर्यात प्रभावित हुआ. इसने सोयाबीन में तेजी की अवधारणा को बल दिया.'' इसके अलावा अमेरिका और ब्राजील समेत कई देश सोयाबीन तेल का इस्तेमाल अक्षय ऊर्जा (रिन्युएबल एनर्जी) बनाने में भी कर रहे हैं. इस वजह से कोविड के बाद भी वैश्विक स्तर पर खाद्य तेलों की मांग में कोई बड़ा असर नहीं दिखा.

तेजी रहेगी जारी

भारतीय रिजर्व बैंक की ओर से हाल में जारी वार्षिक रिपोर्ट में कहा गया है कि साल के दौरान थोक और खुदरा महंगाई के बीच अंतर लगातार आपूर्ति बाधाओं और खुदरा मार्जिन अधिक रहने की ओर इशारा करता है. रिपोर्ट के मुताबिक, ''मांग और आपूर्ति में असंतुलन बने रहने से दलहन और खाद्य तेल जैसे खाद्य पदार्थों की ओर से दबाव बने रहने की

गेट्टी इमेजेज

देश में खाद्य तेल का आयात

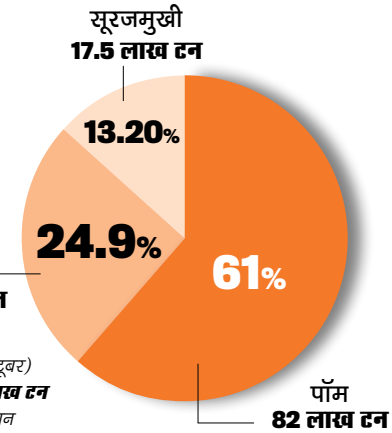

*तेल वर्ष (01 नवंबर से 31 अक्टूबर) 2020-21 में कुल **132.50 लाख टन** खाद्य तेल के आयात का अनुमान*

स्रोतः एसईएआइ

कीमतों में आग
पिछले एक साल के दौरान विभिन्न कारणों से खाद्य तेल की कीमतें बढ़ रही हैं

राष्ट्रीय स्तर पर खाद्य तेलों की औसत कीमत रुपए में

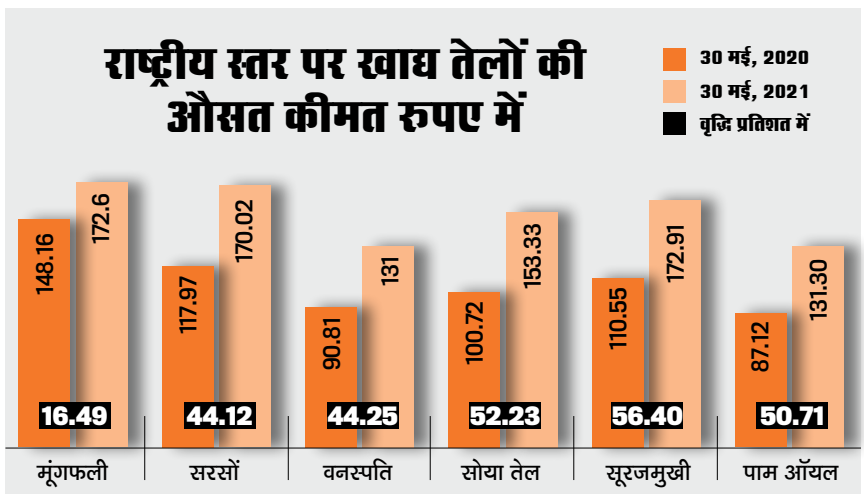

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

संभावना है, जबकि 2020-21 में अनाज की बंपर पैदावार के साथ अनाज की कीमतों में नरमी आ सकती है.''

केडिया कमोडिटी के प्रबंध निदेशक अजय केडिया कहते हैं, ''पूरी दुनिया में तेजी से वैक्सीन लगने के बाद ही मांग की वापसी होगी. ऐसे में कीमतों में किसी बड़ी गिरावट की उम्मीद नहीं लगानी चाहिए.'' हालांकि केडिया का मानना है कि नई फसल की आवक के बाद कीमतों में नरमी दिखेगी लेकिन यह पिछले साल के स्तर पर पहुंचेगी, ऐसी संभावना नहीं है. गौरतलब है कि चीन ने कोविड के थमने के बाद मांग की वापसी की उम्मीद के चलते ही बड़ी मात्रा में आयात किया है.

द सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन फॉर ऑयल इंडस्ट्री ऐंड ट्रेड में क्रॉप एस्टीमेट कमेटी के चेयरमैन अनिल छतर कहते हैं, ''दीवाली तक खाद्य तेलों में किसी बड़ी गिरावट की उम्मीद नहीं है. नई आवक के बाद भाव में कुछ नरमी जरूर आएगी.'' 2020-2021 के दौरान जैसी तेजी देखने को मिली, वह अप्रत्याशित थी. फिलहाल मंडियों में भाव सरकार की ओर से तय न्यूनतम समर्थन मूल्य से काफी ऊपर है. सरकार की ओर से सरसों का तय न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) 4,650 रुपए प्रति क्विंटल का है, जबकि मंडी में भाव 7,800 रुपए के करीब है. वहीं सोयाबीन का एमएसपी 3,880 रुपए प्रति क्विंटल है. मंडी में भाव 7,500 रुपए के करीब है. अनिल बताते हैं कि बीते 15 दिनों में भाव 10 से 12 फीसद कम हुए हैं.

फिर कैसे मिले राहत?

खाद्य तेलों की कीमतों में यह इजाफा उस समय देखने को मिल रहा है, जब कोविड के कारण बड़ी संख्या में लोगों की आय और रोजगार प्रभावित हुए हैं. एसईएआइ का मानना है कि सरकार वायदा बाजार में सटोरिया गतिविधियों पर अंकुश लगाकर कीमतों पर काबू पा सकती है. वायदा बाजार में खाद्य तेल जैसी आवश्यक वस्तुओं के वायदे में डिलिवरी को अनिवार्य किया जा सकता है. इससे बाजार में केवल असली खरीदारों की ही भागीदारी सुनिश्चित हो सकेगी. इसके अलावा, 4 फीसद के अपर सर्किट को घटाकर 2 फीसद किया जा सकता है. ऐसा करने से वे लोग वायदा बाजार से दूर हो जाएंगे जो केवल पैसा कमाने के लिए बाजार का रुख करते हैं.

सुझाव यह भी है कि नीति निर्माताओं को स्पष्ट रखना होगा कि खाद्य तेलों में कितनी गिरावट अर्थव्यवस्था के लिए अच्छी है और उसी के हिसाब से रणनीति तैयार करनी होगी. ऐसा इसलिए क्योंकि जब एक तरफ उपभोक्ता महंगा तेल खरीदने पर मजबूर है, ठीक उसी समय किसानों को घरेलू मंडियों में उसकी उपज के बेहतर दाम भी मिल रहे हैं.

आमतौर पर आयात पर निर्भर वस्तुओं की कीमतों में तत्काल राहत देने के लिए आयात शुल्क में कटौती को एक विकल्प के रूप में देखा जाता है, लेकिन उद्योग संगठन की राय इस मोर्चे पर अलग है. मेहता कहते हैं, ''वैश्विक बाजार में अगर कीमतों में तेजी का सिलसिला जारी रहता है तो आयात शुल्क में कटौती का कोई खास फायदा उपभोक्ता को नहीं मिल पाएगा.'' साथ ही सरकार को भी राजस्व का नुक्सान उठाना पड़ेगा. बेहतर है कि सरकार पीडीएस के रास्ते तेल पर सब्सिडी देकर उपभोक्ता को सीधा फायदा पहुंचाए. ■

इलस्ट्रेशन: सिद्धांत जुमडे

समाचार सार

पेनड्राइव परीक्षा

कांग्रेस नेता **कमलनाथ** शुरू में तो पार्टी विधायक उमंग सिंघार के बचाव में उतरे, जिन्हें प्रेम प्रसंग में रिश्ता खराब होने पर महिला को आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था. मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री ने सिंघार के बचाव में आरोप लगाया कि भाजपा 'बदले की राजनीति' कर रही है. उन्होंने 2019 के हनी ट्रैप कांड का जिक्र भी किया जिसमें कई नेता शामिल थे और दावा किया कि उनके पास एक पेनड्राइव है जिसमें इस मामले से जुड़े अहम सुबूत हैं लेकिन उन्होंने ऐसे मकसद के लिए कभी उनका इस्तेमाल नहीं किया. हनी ट्रैप मामले की जांच कर रही एसआइटी ने नाथ को नोटिस भेज 'अहम सुराग' सौंपने को कहा. अब नाथ का कहना है कि यह पेनड्राइव कई पत्रकारों के भी पास है, उन्हीं से क्यों मांगा जा रहा. एसआइटी उन्हें साक्ष्य दबाए रखने के लिए गिरफ्तार करेगी?

तूफान की आहट

पुरुषोत्तम दिवाकर

राजस्थान की सियासत में उन्हें हाशिए पर धकेलने की कोशिश भले भाजपा केंद्रीय नेतृत्व का एक धड़ा करता रहा हो, पर पूर्व मुख्यमंत्री **वसुंधरा राजे** प्रासंगिक बने रहने के लिए जानी जाती हैं. उनके वफादारों ने राज्य के 15 शहरों में कोविड पीड़ितों के बीच मुफ्त भोजन वितरण शुरू किया. 'वसुंधरा जन रसोई' अब हर नगरपालिका में पैठ बना रही है. राजे भी अब भाजपा के आला नेतृत्व के पक्ष में हैं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार के सात साल पूरे होने पर तारीफ में उन्होंने ट्वीट भी किया था. महारानी 2023 के विधानसभा चुनावों के खेल में अपनी मौजूदगी पक्की कर रही हैं.

अरे! बॉम्बे

महाराष्ट्र के पर्यटन मंत्री **आदित्य ठाकरे** को मुंबई की धरोहरें बहुत पसंद हैं. 2018 में उन्होंने ऐतिहासिक फ्लोरा फाउंटेन की मरम्मत करवाई थी. इस साल 30 मई को उन्होंने जीर्णोद्धार किए गए 153 साल पुराने और ढलवां लोहे के बने फिट्जगेराल्ड फाउंटेन का उद्घाटन किया. पर सोशल मीडिया यूजर्स ने ध्यान दिलाया कि यह ढांचा औपनिवेशिक व्यक्ति सेमोर फिट्जगेराल्ड के नाम पर है, जो तब के बॉम्बे जनपद के पहले गवर्नर थे. सियासी दांव के तहत नए फव्वारे का नाम आज की मुंबई में बदल जाएगा?

शाश्वत अटल

दिवंगत अटल बिहारी वाजपेयी अभी भी लखनऊ में बड़े प्यार से याद किए जाते हैं (इस सीट ने उन्हें पांच बार लोकसभा भेजा था). योगी आदित्यनाथ सरकार में कानून मंत्री **बृजेश पाठक** 21 मई से ही अटल भोजनालय चला रहे हैं और इसके जरिए रोजाना 500 गरीबों को खिला रहे हैं. पिछले दिसंबर में पाठक ने वाजपेयी के जन्मदिन पर कविता महोत्सव आयोजित किया था. इस साल उनकी योजना कॉलेजों में व्याख्यान आयोजन की है. वे वेबसाइट भी शुरू करना चाहते हैं जहां उनकी किताबों और भाषणों का संग्रह हो. एक सच्चा अटल भक्त!

पीटीआइ

घूम गया पहिया

साल 2016 में झारखंड विकास मोर्चा (प्रजातांत्रिक) के मुखिया रहते **बाबूलाल मरांडी** ने चुनाव आयोग को एक ऑडियो टेप सौंपकर पूर्व मुख्यमंत्री रघुबर दास पर राज्यसभा चुनावों में विधायकों की खरीद का आरोप लगाया था. आरोप था कि दास ने कांग्रेस के एक विधायक को भाजपा के पक्ष में वोटिंग के लिए रिझाने की कोशिश की. अब मामला फिर उभरा है. हेमंत सोरेन सरकार ने मरांडी की प्राथमिकी में दास का नाम भी जोड़ दिया है. मरांडी अब भाजपा में हैं.

–संदीप उन्नीथन, साथ में ***राहुल नरोन्हा, रोहित परिहार, किरण तारे, आशीष मिश्र और अमिताभ श्रीवास्तव***

आज तक

देश का नं. 1 हिंदी न्यूज़ ऐप

जुड़े रहिए हर खबर से,
कहीं भी, कभी भी

अभी डाउनलोड करें

aajtak.in/app

उपलब्ध है

अर्थात्

ऐसे आती है गरीबी

अंशुमान तिवारी

सरकार अगर चाहे तो वह बहुत कम वक्त में बहुत बड़ी आबादी को गरीब बना सकती है. यह बात राजनैतिक अर्थशास्त्र के पितामह जॉन मेनार्ड केंज कहते थे जिनकी शपथ लेकर सरकारें बजट तैयार करती हैं. केंज ने बताया था कि सरकारें महंगाई बढ़ाकर आम लोगों की बचत-खपत-संपत्ति घटाकर उन्हें गरीब बना देती हैं.

महंगाई के कारण आय और खर्च की क्षमता घटने से, बीते एक बरस में देश की 97 फीसदी आबादी 'गरीब' हो गई है (सीएमआईई). गरीबी का मतलब फटेहाल हो जाना ही नहीं है. निर्धनता तुलनात्मक है. जो आय के जिस स्तर पर है, उसकी गरीबी उतनी ही मारक है.

महंगाई हमारे लिए नई नहीं है. कमाई और मांग बढ़ने से आने वाली महंगाई के कुछ समर्थक मिल जाएंगे. मौद्रिक पैमानों पर धन की आपूर्ति से कीमतें बढ़ती हैं लेकिन इस वक्त जब कमाई व कारोबार ध्वस्त है और सस्ता कर्ज सबकी किस्मत में नहीं है तब सरकार ही महंगाई थोप रही है.

धूमिल कहते थे कि लोहे का स्वाद लोहार नहीं, घोड़े से पूछो जिसके मुंह में लगाम है. इस महंगाई का वीभत्स असर, केवल घोड़े (आम लोग) ही नहीं लोहार (आंकड़े वाले) भी बता रहे हैं.

खाद्य सामान की कीमत एक फीसद बढ़ने से खाने पर खर्च करीब 0.33 लाख करोड़ रुपए (क्रिसिल) बढ़ जाता है. खाद्य महंगाई बीते एक साल में 9.1 फीसद (कोविड पूर्व से तीन फीसद) की दर से बढ़ी. फल-सब्जी की मौसमी तेजी को अलग रख दें तो भी खाद्य तेल, मसाले, दाल, अंडे की कीमतों ने महंगाई की कुल दर को मीलों पीछे छोड़ दिया.

मिल्टन फ्रीडमैन कहते थे कि महंगाई कानून के बिना लगाया जाना वाला टैक्स है. भारत में अधिकांश टैक्स मूल्यानुसार (एडवैलोरेम) हैं, यानी कीमत बढ़ने से टैक्स संग्रह बढ़ता है. ईंधन, बिजली, सेहत और मनोरंजन की कीमतें, बुनियादी (कोर) महंगाई हैं जो मौसमी उतार-चढ़ाव से नहीं बल्कि टैक्स या कच्चे माल की लागत से प्रभावित होती है. इस मोर्चे पर महंगाई बीते नवंबर से ही बढ़ रही है. पेट्रो उत्पादों पर टैक्स और कीमतें मंदी के जख्म पर मिर्च वाला नमक हैं.

फैक्ट्री उत्पादों की महंगाई ट्यूब से निकला टूथपेस्ट है, जिसे फिर ट्यूब में नहीं भरा जा सकता. मांग की अनुपस्थिति और कच्चे माल व ईंधन की महंगाई के कारण कंपनियों और कारोबारियों ने अधिकांश फैक्ट्री उत्पाद (कपड़े, जूते, प्रसाधन) महंगे कर दिए हैं.

महंगाई और गरीबी के ताजे रिश्ते केवल मौद्रिक नहीं हैं. सरकारों को यह आईना दिखाना जरूरी है कि—

- महंगाई की नई नापजोख अलग-अलग मदों पर उपभोग खर्च की रोशनी में होनी चाहिए. पेट्रोल-डीजल की महंगाई और बीमारी के इलाज पर खर्च के कारण दूसरी जरूरतों को दरकिनार कर दिया गया है. इससे मंदी और गहराई है.
- कोविड में इलाज पर लोगों ने 66,000 करोड़ रु. ज्यादा खर्च किए. कोविड से पहले तक भारतीयों के उपभोग खर्च में स्वास्थ्य पर खर्च औसत 5 फीसद होता था, जो एक साल में 11 फीसद हो गया.
- जिंदगी आसान करने वाले उत्पाद और सेवाओं पर लोगों का खर्च बीते छह माह में करीब 60 फीसद कम हुआ, जिसकी वजह ईंधन पर बढ़ा खर्च है. (एसबीआइ रिसर्च)
- सीएसओ ने बताया कि 2020-21 में प्रति व्यक्ति आय 8,637 रुपए घटी है. निजी और असंगठित क्षेत्र में बेरोजगारी और वेतन कटौती के कारण आय में 16,000 करोड़ रुपए की कमी आई है. (एसबीआइ रिसर्च)

महंगाई सरकारें ही बढ़ाती हैं. यह बात जॉन मेनार्ड केंज ही नहीं एक पुराने अर्थविद् फ्रेडरिक हायेक भी कहते थे, नहीं तो इस महामारी व महाबेरोजगारी के बीच दवाएं, पेट्रोल-डीजल, खाने के सामान पर टैक्स कम हो सकता था. बचत पर ब्याज दर में कटौती टाली जा सकती थी.

महंगाई बहुत कम समय में कुछ लोगों को बहुत अमीर और असंख्य लोगों को अत्यंत निर्धन कर सकती है. जैसे कि बीते सात साल में पेट्रोल-डीजल से टैक्स संग्रह 700 फीसद बढ़ा. मंदी और बेकारी के दौरान 2020-21 में सरकार ने इन ईंधनों से रिकॉर्ड 2.94 लाख करोड़ रुपए का टैक्स वसूला जबकि कंपनियों पर टैक्स में 1.45 लाख करोड़ रुपए की कमी की गई है.

भारत में खुदरा महंगाई में एक फीसद बढ़त से जिंदगी 1.53 लाख करोड़ रुपए महंगी (क्रिसिल) हो जाती है. एक बरस में खुदरा महंगाई की सरकारी (आधा-अधूरा पैमाना) सालाना दर 6.2 फीसद रही जो 2019 से करीब दो फीसद ज्यादा थी. अब यह 8 फीसद की तरफ बढ़ रही है. इसी के चलते 97 फीसद निम्न और मध्यम वर्गीय आबादी एक साल में पहले के मुकाबले गरीब हो गई है.

असंख्य सेवाएं और उत्पाद हमेशा के लिए महंगे हो चुके हैं. खपतमार और गरीबी बढ़ाने वाली महंगाई लंबी मंदी लाती है. महामारी के दौरान जब अन्य देशों ने अपने लोगों की तकलीफ कम की है तो हमारी सरकार ने ही हमें योजनाबद्ध ढंग से गरीब कर दिया. तेल (पेट्रोल-डीजल और खाद्य सामग्री) खरीदते हुए सरकार को बार-बार यह बताना जरूरी है कि उन्हें गरीबी बढ़ाने के लिए वोट नहीं दिया गया था.

@anshuman1tiwari

सरकारें महंगाई बढ़ाकर बड़ी सफाई से हमारी बचत-खपत-संपत्ति घटाते हुए हमें गरीब बना देती हैं

इलस्ट्रेशनः असित रॉय

इंडिया टुडे
देश की भाषा में देश की धड़कन

INDIA TODAY GROUP

यूपी की धान खरीद व्यवस्था में कई छेद
लालफीताशाही के शिकंजे में कारोबार
सरना: पुराने धर्म पर नई बहस
इंडिया टुडे
कोविड-19 वैक्सीन
कितनी सुरक्षित? कितनी कारगर?
बाजार में आने के लिए तैयार नई वैक्सीन से जुड़े सारे अहम सवालों के जवाब

राम मंदिर को माना गया मोदी की प्रमुख उपलब्धि
अनुच्छेद 370 हटाने को मिला जोरदार समर्थन
बेरोजगारी मानी गई सबसे बड़ी समस्या
इंडिया टुडे
देश का मिजाज सर्वेक्षण
मोदी और हिंदुत्व का बोलबाला
देशव्यापी छमाही सर्वेक्षण से जाहिर है कि नरेंद्र मोदी लोकप्रियता के शिखर पर बरकरार हैं और संघ परिवार के एजेंडे को मिली जबरदस्त बढ़त

सबसे भरोसेमंद स्रोतों से, सबसे सटीक जानकारी

सब्सक्राइब करें और पाएं 25% तक की छूट

हां! मैं इंडिया टुडे को सब्सक्राइब करना चाहता/चाहती हूँ

अपनी पसंद के सब्सक्रिप्शन को टिक करें और फॉर्म को इस पते पर भेज दें– वी केअर, लिविंग मीडिया इंडिया लि. सी–9, सेक्टर–10, नोएडा 201302 (भारत)

टिक करें	अवधि	कुल अंक	कवर प्राइस (₹)	ऑफर प्राइस (₹)	डिस्काउंट
☐	3 वर्ष	156	~~6240~~	4680	25%
☐	2 वर्ष	104	~~4160~~	3330	20%
☐	1 वर्ष	52	~~2080~~	1770	15%

कृपया फॉर्म को ब्लॉक लेटर में भरें

मैं चेक/डीडी जमा कर रहा/रही हूँ जिसकी संख्या.....है और इसे दिनांक..... को लिविंग मीडिया इंडिया लिमिटेड के पक्ष में ..... (बैंक का नाम).....रुपये की धनराशि (दिल्ली से बाहर के चेक के लिए ₹ 50 रुपये अतिरिक्त जोड़ें, समान मूल्य के चेक मान्य नहीं होंगे) के लिए बनवाया गया है.

नाम..... पता.....

..... शहर..... राज्य..... पिन.....

मोबाइल..... ईमेल.....

सब्सक्राइब करने के लिए यहां स्कैन करें.

ऑफर के विषय में विशेष जानकारी के लिए निम्न माध्यमों से संपर्क भी कर सकते हैं

हमारे टॉल फ्री नंबर पर कॉल करें 18001800100 (0120) 2479900

ईमेल भेजें wecare@intoday.com

लॉग ऑन करें www.indiatoday.in/indiatoday-hindi

लिविंग मीडिया इंडिया लिमिटेड इस ऑफर या इसके अंश को कभी भी समाप्त करने या आगे बढ़ाने का अधिकार सुरक्षित रखता है. अन्य नियम व शर्तों की जानकारी के लिए कृपया देखें-www.indiatoday.in

“अर्थव्यवस्था एक बड़ी चुनौती से दो-चार है पर उससे निबटने की हमारी पूरी तैयारी है”

कोविड की दूसरी लहर के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था भले फिर से गहरे संकट में नजर आ रही हो लेकिन केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के आत्मविश्वास को देखकर लगता है कि स्थिति पूरी तरह से सरकार के नियंत्रण में है. *ग्रुप एडिटोरियल डायरेक्टर* राज चेंगप्पा *बिजनेस टुडे के संपादक* राजीव दुबे के साथ एक एक्सक्लूसिव बातचीत में वे अर्थव्यवस्था में नई जान डालने की योजना का खुलासा करती हैं. उसी बातचीत के अंश:

सभी फोटो: बंदीप सिंह

प्र जीडीपी सहित सभी बड़े आर्थिक सूचकांक गोता लगा रहे हों तो बतौर वित्त मंत्री आपको कैसा लगता है? क्या आंकड़ों को देख आपका दिल नहीं बैठ जाता?

देखिए, मैं इसे बड़ी चुनौती की तरह देखती हूं, जो यह आश्वस्त करने के लिए अच्छी-खासी एकाग्रता की मांग करती है कि हम हर पल ऐसे कदम उठाने के काबिल हैं, जिससे लोगों की मदद हो. मैं यह बिल्कुल नहीं कहना चाहती कि इस तरह के आंकड़े मुझे परेशान नहीं करते, मगर मुझे लोगों की दुख-तकलीफ और अनेक परिवारों पर टूट पड़ी त्रासदियों के बारे में भी सोचना है. तो, यही मेरे दिल पर एक बोझ की तरह है. मुझे इसके साथ कुछ इस ढंग से पेश आना है कि चाहे यह पूरी तरह न मिटाया जा सके पर उसकी ओर कदम बढ़े.

● **कोविड की दूसरी लहर को लेकर मोदी सरकार की गफलतों के बारे में काफी आलोचना हुई है.**

मैं इसके लिए किसी को दोष नहीं देती. समस्या इतनी भयावह थी, जिस तेजी से दूसरी लहर ने हमला बोला, लोगों को गहरे, त्रासद अनुभव से गुजरना पड़ा, यह स्वाभाविक था कि सरकार पर सवाल उठते. हमें फौरन लोगों की मदद को आगे आना पड़ा और पक्का करना पड़ा कि व्यवस्था सुधरे.

● **वित्त वर्ष 21 में चौथी तिमाही में अपेक्षाकृत उत्साहजनक नतीजों के बावजूद देश की जीडीपी कुल मिलाकर 7.3 फीसद तक नीचे गई. दूसरी लहर के वक्त कई राज्यों में लॉकडाउन के अर्थव्यवस्था पर असर के बारे में आपका आकलन क्या है? इस गर्त से निकलने के लिए देश में जरूरी आर्थिक वृद्धि को लेकर आप कितनी आश्वस्त हैं?**

एक तो दूसरी लहर के असर का आकलन करना अभी जल्दबाजी होगी. यह पिछली बार से अलग है, इसका प्रबंधन राज्य अलग-अलग तरह के लॉकडाउन के जरिए कर रहे हैं. दूसरी लहर की व्यापकता और प्रचंडता पहली से अलग है. दूसरी बात, हमने आत्मनिर्भर पैकेज के जो ऐलान किए थे और कुछ का तो केंद्रीय बजट से ठीक पहले ही हुआ था, उसके नतीजे दिखे हैं. बजट ऐसे समय तैयार हुआ था जब हमारे सामने कोविड ग्रस्त अर्थव्यवस्था थी लेकिन हम आसन्न दूसरी लहर से वाकिफ नहीं थे. इसलिए बजट महामारी के नुक्सान की भरपाई के लिए था. बजट में इन्फ्रास्ट्रक्चर के मद में, और उसी तरह स्वास्थ्य इन्फ्रास्ट्रक्चर पर पूंजीगत खर्चों में काफी बढ़ोतरी है.

● **आखिर वह कौन-सी बात है जो आपको यकीन दिलाती है कि अर्थव्यवस्था पर कोविड की दूसरी लहर के असर के बावजूद बजट 2021 मकसद पूरा करेगा?**

बजट बड़ी शिद्दत से तैयार किया गया है, सभी संबंधित पक्षों से काफी जानकारियां ली गईं और सही प्राथमिकताएं तय की गईं. अगर पूरे साल के संदर्भ में सही अर्थों में अमल हुआ तो बजट कोविड से संबंधित और उससे उपजने वाली अनेक समस्याओं का हल करने में कामयाब रहेगा. इसके अलावा हम राज्यों और उद्योग जगत से सलाह-मशविरे का

> **“पूरे वर्ष को शब्दों और भावों के सच्चे अर्थ में रखकर देखें तो आप पाएंगे कि बजट 2021 में कोविड से उत्पन्न और उससे जुड़ी तमाम समस्याओं से निबटने की क्षमता है. यह जानने के लिए हम राज्यों और उद्योगों से भी निरंतर संवाद में रहेंगे कि आगे और क्या किए जाने की जरूरत है”**

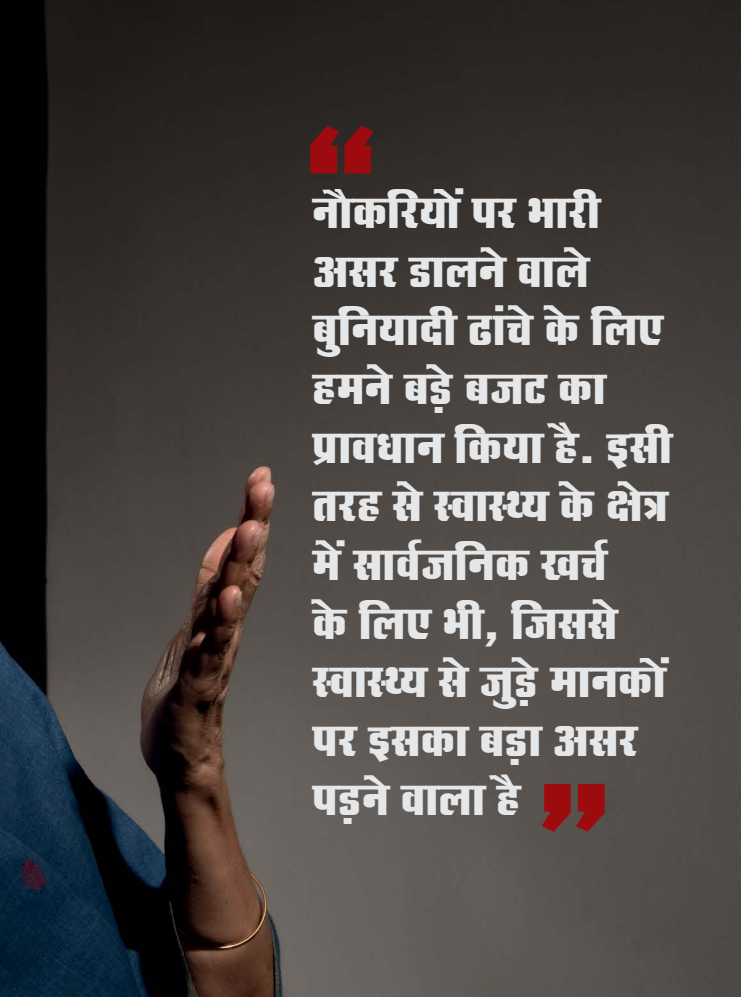
“नौकरियों पर भारी असर डालने वाले बुनियादी ढांचे के लिए हमने बड़े बजट का प्रावधान किया है. इसी तरह से स्वास्थ्य के क्षेत्र में सार्वजनिक खर्च के लिए भी, जिससे स्वास्थ्य से जुड़े मानकों पर इसका बड़ा असर पड़ने वाला है”

सिलसिला लगातार बनाए रखेंगे, ताकि जाना जा सके कि कहीं बजट के दायरे में ही मेरे लिए कुछ और करने की दरकार तो नहीं है. यह स्वीकारना जरूरी है कि पहली तिमाही (वित्त वर्ष 21) में जीडीपी काफी सिकुड़ गई. मुझे बताया गया कि किसी और देश की जीडीपी 23 फीसद तक नहीं सिकुड़ी. लेकिन मैं प्रधानमंत्री की बेहद शुक्रगुजार हूं कि वे सभी संबंधित पक्षों से सलाह-मशविरा करते रहे और हमारे साथ बैठकर समाधान निकालते रहे. हम पांच अलग-अलग (प्रोत्साहन) पैकेज लेकर आए. चौथी तिमाही में ही हमने नकारात्मक वृद्धि पर काबू पा लिया. सकारात्मक आंकड़ों की ओर बढ़ना संभव नहीं हुआ होता, अगर लोगों ने पैकेजों का लाभ नहीं उठाया होता. सबसे बढ़कर लोगों ने प्रधानमंत्री और मोर्चे पर हर वक्त आगे रहने के उनके तरीके पर भरोसा जताया.

● कोविड के प्रकोप के पहले ही जीडीपी वृद्धि में गिरावट दर्ज हो रही थी. तो, कोविड के अलावा क्या वह व्यवस्थागत या ढांचागत खामी है, जिसे दुरुस्त करना है?

जीडीपी जैसे मामलों पर बात करते समय जरा एक दीर्घकालिक नजरिया अपनाते हैं. आप इस पहलू पर गौर कीजिए कि खासकर 1991 में अर्थव्यवस्था को खोलने के बाद से जीडीपी में कैसे उतार-चढ़ाव आते रहे हैं. और अगर आप 2018 और 2019 में ही देखना चाहते हैं तो यह भी देखिए कि हम अर्थव्यवस्था के ‘नाजुक पांच’ वाले क्लब में थे, जो हमें 2014 में विरासत में मिला. इसमें दो राय नहीं कि कुछ हद तक जीडीपी वृद्धि चक्रीय है. वह कभी सिर्फ ऊपर ही ऊपर नहीं चढ़ती रही है. हालांकि मैं तो चाहती थी कि ऐसा ही होता.

● कोविड की लहरों से बड़े पैमाने पर नौकरियां और रोजगार खत्म हुए हैं, कुछ विशेषज्ञों का अनुमान है कि इस बीच 2 करोड़ से ज्यादा लोग बेरोजगार हो गए. दूसरा बड़ा झटका यह है कि दशकों से गिरते गरीबी के आंकड़े बढ़ने लगे हैं और नए गरीब पैदा हो गए हैं. क्या आप उनके लिए कोई प्रोत्साहन या नकद मदद के प्रस्ताव पर सोच रही हैं?

जैसा कि मैंने पहले कहा, बजट दूसरी लहर की जानकारी के बिना, कोविड के बाद के दौर में आर्थिक बहाली के मद्देनजर तैयार किया गया था. हमने इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिए बड़े प्रावधान किए, जिसका रोजगार पर फर्क पड़ेगा. फिर स्वास्थ्य पर सार्वजनिक खर्च बढ़ाया गया जिसका स्वास्थ्य सूचकांक पर असर पड़ेगा. किसानों के लिए पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लाभ के अलावा हमने इस साल प्रत्यक्ष नकद हस्तांतरण विधि से एमएसपी (न्यूनतम समर्थन मूल्य) पर गेहूं और धान की इतनी खरीद की, जितनी पहले कभी नहीं हुई थी. इसका मतलब है कि पैसा किसानों के हाथ में जा रहा है, जिसका ग्रामीण अर्थव्यवसथा पर फर्क पड़ेगा. इसके अलावा हम लोगों को ईपीएफओ (कर्मचारी भविष्य निधि) से पैसा निकालने की इजाजत दे रहे हैं और महामारी में अनाथ हुए बच्चों के भविष्य को सुरक्षित बनाने के लिए उनके खाते में ठीकठाक एकमुश्त रकम डाल रहे हैं.

● विशेषज्ञों की राय है कि ग्रामीण और शहरी दोनों गरीबों को नकद मदद दी जाए. इस पर सरकार की राय क्या है?

आप यह जानने पर जोर दे रहे हैं कि विपक्ष ने एक तरह से लोगों के खाते में कैश ट्रांसफर का जो सुझाव दिया है, उसके बारे में सरकार क्या करना चाहती है.

● विपक्ष ही नहीं बल्कि विशेषज्ञों ने भी इस तरह की सिफारिश की है.

देखिए, क्या किया जा सकता है, यह सब जानने के लिए हम इस पर गहन अध्ययन करते हैं और फिर इस बारे में फैसला करते हैं कि आगे किस तरह से वित्तीय प्रोत्साहन दिया जाए. अगर आप मुझे दो-टूक यह कह रहे हैं कि लोग आपसे मदद नकदी के रूप में हस्तांतरित करने की बात कर रहे हैं तो मेरा जवाब है कि मैं बहुत सारे लोगों को सुनती हूं जो तरह-तरह के सुझाव देते हैं.

● कुछ विशेषज्ञ संसाधनों में इजाफे के लिए रुपए छापने की वकालत कर रहे हैं.

अगर आप यह विचार मुझे दे रहे हैं तो मैं स्वीकार करूंगी.

● विनिवेश कार्यक्रम के बारे में क्या है?

विनिवेश कार्यक्रम पटरी पर है. हमने बजट में जो कहा है, उस पर हम प्रतिबद्ध हैं.

● मतलब आपने बजट में निजीकरण और ऐसेट मॉनेटाइजेशन के जिन साहसिक कदमों की बात की है, उससे कदम पीछे खींचने की कोई बात नहीं है?

सवाल ही नहीं उठता. आप मुझसे एयर इंडिया, बीपीसीएल के बारे में पूछ सकते हैं—आप कैबिनेट से मंजूर पूरी सूची पढ़ सकते हैं. मैं कहूंगी कि सब कुछ सही दिशा में चल रहा है.

● स्वदेशी जागरण मंच जैसे संगठनों के दबाव के बावजूद निजीकरण से पांव पीछे नहीं खींचे गए हैं?

यह पूरी तरह से पटरी पर चल रहा है. यह सब तो बजट में बाकायदा उल्लिखित है और संसद से इसे मंजूरी मिल चुकी है. मैं उस पर कायम हूं. यह हमारा बजट है.

● फिक्की के ताजा सर्वे से पता चलता है कि कारोबारी भरोसा गिर गया है. उसके सुझावों में मध्यम वर्ग के लिए कर राहत और कारोबार के लिए परोक्ष कर घटाने की बात है. आपका इस पर क्या विचार है?

मैं समझती हूं कि 'मध्य वर्ग' को लेकर यह फिक्र बार-बार आगे कर दी जाती है. क्या किसानों में मध्य वर्ग सरकारी खरीद से लाभान्वित नहीं होता? क्या मध्य वर्ग को किफायती और मध्य आय आवास परियोजनाओं का निर्माण पूरा करने के खातिर विशेष खिड़की (एसडब्ल्यूएएमआइएच) जैसे कार्यक्रमों से लाभ नहीं मिलता? इसी तरह एमएसएमई क्षेत्र के लिए इमरजेंसी क्रेडिट गारंटी लिक्विडिटी स्कीम है, जिसके तहत उनके बकाया कर्ज के 20 फीसद तक बिना किसी जमानत के नया कर्ज दिया जाता है, उसके लिए सरकार ही गारंटर होती है. इसे अब 20 फीसद से बढ़ाकर 40 फीसद कर दिया गया है. क्या मध्य वर्ग के लोग उन्हें नहीं चलाते?

● लगता है, फिलहाल सरकारी पूंजीगत खर्च में खासकर इन्फ्रास्ट्रक्चर ही वृद्धि का इंजन बना हुआ है क्योंकि निर्यात, निजी निवेश और खपत तो सिकुड़ ही गए हैं. दूसरे इंजनों को भी चालू करने के उपाय क्या हैं?

एक तो मैं यह चाहती हूं कि सभी लोग 'चार इंजनों' वाली इस अवधारणा से बाहर निकलें. इसमें दो राय नहीं कि वृद्धि के चार इंजनों को चलना चाहिए. बाकी तीन की कीमत पर बस एक की ही बात करना अब कहीं से भी जायज नहीं रहा. आप कह सकते हैं कि उनमें तेजी आनी चाहिए, लेकिन यह कहना कि तीन बैठ चुके हैं और एक ही चल रहा है, यह बिल्कुल ठीक नहीं. सितंबर 2019 के बाद से कोई नहीं जानता था कि क्या होने जा रहा है. कॉर्पोरेट टैक्स घटा दिया गया और मुझ पर कई लोगों ने आरोप मढ़ा कि मैं कॉर्पोरेट का पक्ष ले रही हूं. ऐसी बातें हो रही थीं कि इन कॉर्पोरेट्स ने काफी बचा लिया, अपना कर्ज चुकता कर रहे हैं लेकिन मुनाफे का बंटवारा नहीं कर रहे. इसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं कि वे अपने कर्ज निबटा रहे हैं या मुनाफे का इस्तेमाल अपने शेयरधारकों की ओर से मंजूर तरीकों से कर रहे हैं. लेकिन यह भी सही है कि उस कदम के बाद से आप कइयों को बड़ी विस्तार योजनाओं, संयुक्त उपक्रम के लिए एफडीआइ की तलाश करते देखेंगे. विलय और अधिग्रहण की घटनाओं को देखें, यह देखें कि मध्य वर्ग के कितने लोग शेयर बाजार का रुख कर रहे हैं क्योंकि उन्हें लग रहा है कि कम जोखिम के साथ बैंक के बचत खाते में पैसा रखने की बजाए पारदर्शी, साफ-सुथरे प्रबंधन वाली कंपनियों में निवेश क्यों न किया जाए?

> **"टैक्स के आतंकवाद से छुटकारे के बारे में प्रधानमंत्री ने जो कहा था उसे लोगों ने (खत्म होते हुए) देखा. उनमें यह भाव पैदा हुआ है कि हम काम करके दिखाते हैं और हमारा काम लोगों को प्रताड़ित और परेशान करना नहीं है"**

जहां तक खपत की बात है तो बजट के पहले और आज ग्रामीण भारत में खपत के आंकड़े देखें. अप्रैल की शुरुआत में यह थोड़ी घटी जरूर थी लेकिन ट्रैक्टर तथा कृषि उपकरणों और एफएमसीजी वस्तुओं की बिक्री बदस्तूर बनी हुई है. मैं यह नहीं कह रही कि सब चंगा है, लेकिन हमें सब कुछ भुला नहीं देना चाहिए.

● क्या आप चिंतित हैं कि कोविड-19 की दूसरी लहर के गांवों में फैलने का गंभीर नतीजा हो सकता है?

> **विनिवेश कार्यक्रम पूरी तरह से पटरी पर है. बजट में जो भी हमने कहा है, हम उस पर प्रतिबद्ध हैं. आप मुझसे एयर इंडिया, बीपीसीएल के बारे में पूछिए, कैबिनेट से मंजूरी पूरी लिस्ट पढ़ लीजिए, सब कुछ पूरी तरह से पटरी पर चल रहा है**

इस साल भी ग्रामीण भारत काम पर लगा रहा है. इसी वजह से आपके यहां कई फसलों की अच्छी-खासी पैदावार हो रही है और अगली फसल की बुआई की तैयारी चल रही है. मंडियां पूरी हरकत से सक्रिय हैं. प्रधानमंत्री ने इसके पहले (मुख्यमंत्रियों से) कहा कि ध्यान रखें कि कोविड गांवों में न पहुंचे. ग्रामीण इलाकों में उसके प्रकोप की चिंताएं पहले से ही हैं, इसलिए सावधानियां बरती जा रही हैं.

● क्या आप दूसरी लहर के मद्देनजर बजट के आंकड़ों पर दोबारा विचार करेंगी?

बिल्कुल नहीं. हम अभी बजट के दूसरे महीने में ही हैं.

● ज्यादातर विशेषज्ञों का कहना है कि एक और महामारी के झटके से बचने के लिए लोगों को तेजी से टीके लगाने की जरूरत है. मगर केंद्र सरकार को अपनी वैक्सीन नीति को लेकर यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट से भी आलोचना झेलनी पड़ी है. यह भी कहा गया कि पर्याप्त टीकों का ऑर्डर देने में देरी हुई और राज्यों को अपनी जरूरत की वैक्सीन खरीदने के लिए कहने से गफलत पैदा हुई.

वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स के साथ बातचीत पिछले साल अक्तूबर से ही चल रही थी. प्रधानमंत्री खुद गांधीनगर, पुणे और हैदराबाद स्थित वैक्सीन निर्माताओं की फैक्ट्रियों में गए और उनका हौसला बढ़ाया. उनके पास जो स्टॉक था, उसने 16 जनवरी से टीके लगाने का अभियान शुरू करने और तमाम फ्रंटलाइन वर्करों और 60 साल से ऊपर के लोगों को टीके लगाने में बड़ी मदद की. केंद्र ने ये वैक्सीन खरीदीं और मुफ्त में बांटीं. अप्रैल में हमने टीका अभियान को 45 से ऊपर के लोगों के लिए खोल दिया, यह भी सरकारी अस्पतालों में मुफ्त था. ये टीके भी सरकार ने खरीदे और भेजे.

जनवरी से ही चीख-पुकार मचने लगी कि केंद्र को यह क्यों करना चाहिए और यह राज्यों के ऊपर छोड़ देना चाहिए. मैं उन्हें जिम्मेदार नहीं ठहरा रही हूं, लेकिन यह विश्वसनीय, बार-बार उठ रही और मुखर आवाजें थीं. तो नीति इस तरह बनाई गई कि हम मौजूद वैक्सीन में से 50 फीसद लें और उन्हें मुफ्त में देना जारी रखें, और बाकी 50 फीसद राज्य ले लें और उनका जो चाहे करें. और इसमें अगर छोटी-सी मात्रा उन बड़े अस्पतालों के लिए छोड़ दी जाए जो इसे खरीदना और अपने मरीजों को लगाना गवारा कर सकें, तो (इसे) खोल देना चाहिए—ठीक यही तो किया गया है. यह बदलाव राज्य सरकारों की तरफ से मुखर और साफ आवाजों के बाद किया गया.

● काफी पहले ऑर्डर देने के बारे में क्या कहेंगी, जैसा कि अमेरिका सरीखे देशों ने किया?

जहां तक पहले ऑर्डर देने की बात है, वैक्सीन निर्माताओं के पास रखा पूरा पिछला भंडार या स्टॉक नहीं आता तो हम 16 जनवरी से वैक्सीन भला कैसे दे सकते थे? वे जो बना रहे हैं, वह लिया जा रहा है, और साथ ही साथ उसे बढ़ाया भी जा रहा है. हम नई-नई, बेकार पड़ी क्षमताएं खोज रहे हैं, जिनका इस्तेमाल उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए किया जा सके, और इसी के चलते हमें जून में और जुलाई में भी ज्यादा वैक्सीन मिल रही है. हम घरेलू उत्पादन के लिए वैक्सीन आयात भी कर रहे हैं जैसे कि स्पुतनिक-5.

● सार्वभौम टीकाकरण कार्यक्रम के लिए भी केंद्र ही वैक्सीन खरीदता और राज्यों को बांटता था. तो यह बदलाव क्यों? बदलाव (का नतीजा) अब जबकि राज्य वैक्सीन खरीदने के लिए एक-दूसरे से होड़ कर रहे हैं, ऐसे में मौका देखकर निर्माता कीमतें बढ़ा सकते हैं.

तर्क अच्छा है, लेकिन यह आपको मुझसे पूछना चाहिए या उन लोगों से, जिन्होंने कहा था कि केंद्र को भला क्यों खरीदनी चाहिए वैक्सीन!

● आपने उनकी बात क्यों सुनीं?

अगर मैं नहीं सुनती, तो आप मुझसे फेडरलिज्म को लेकर सवाल करते. यह फैसला करना मेरे ऊपर नहीं है, खासकर उस वक्त जब राज्यों ने इसके लिए कहा और हमने उन्हें सुना और उनकी बात मानी.

● केंद्र ऐसा क्यों नहीं करता कि फिर इसे अपने हाथ में ले ले और गफलत खत्म करे?
आपने मुझसे कहा है और मैं इसे सुझाव की तरह लेती हैं.

● सरकार को बढ़ती महंगाई और खासकर ईंधन की कीमतों को लेकर भी आलोचना झेलनी पड़ रही है. क्या ईंधन की कीमतों में कटौती का विकल्प है?
दलहन, खाद्य तेल और दूसरी जरूरी चीजों की कीमतों में महंगाई के मामले में मंत्रियों का एक समूह नियमित रूप से इसके पीछे की वजहों को देख रहा है और आयात की इजाजत देने पर चर्चा कर रहा है, इस बात का ध्यान रखते हुए कि कीमतों के धड़ाम से गिरने का नुक्सान किसानों को न उठाना पड़े. समूह यह भी पक्का कर रहा है कि सप्लाइ चेन की परेशानियां या जमाखोरी न हो. ईंधन के मामले में, भारतीय कीमतें करीब-करीब वैश्विक कीमत के बराबर ही तय की गई हैं. जहां तक करों की बात है, केंद्र सरकार यह कीमतों के हिसाब से नहीं करती; यह तय दर है, फिर तेल की कीमत चाहे जो हो. राज्यों को जो मिलता है, वह कीमत के हिसाब से मिलता है; तेल की कीमत बढ़ने पर हर बार उनका राजस्व भी बढ़ जाता है. तो केंद्र और राज्य के बीच तेल की कीमत के मुद्दे की कई परतें हैं. सबसे पहले तो हमें यह याद रखना होगा कि केंद्र कीमतें तय नहीं करता; ये कीमतें बाजार की ताकतों से तय होती हैं.

● आपने अर्थव्यवस्था में जबरदस्त मुद्रा झोंकी लेकिन इससे मुद्रास्फीति भी पैदा हुई. तो 'इधर कुआं, उधर खाई' की इस स्थिति में, जहां अर्थव्यवस्था को मुद्रा की पर्याप्त उपलब्धता भी चाहिए पर महंगाई भी तेजी से बढ़ रही है, आपके सामने आखिर विकल्प क्या हैं?
कारोबार जब मुश्किलों से उबरने की कोशिशों में लगे हैं, तरलता जरूरी है. भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआइ) तरलता को संभालता है. मैं उनके साथ विचार-विमर्श करती रहती हूं. आर्थिक मामलों का विभाग (डीईए) उनके साथ नजदीक से मिलकर काम करता है. हमारा रिजर्व बैंक के साथ करीबी तालमेल है ताकि तरलता के अचानक सूखने का असर परवान भरते कारोबारों पर न पड़े. बैंकों को पर्याप्त गुंजाइश दी गई है ताकि वे कारोबारियों के आने पर उधार दे सकें. बैंकों की स्थिति और उनके खाता-बही में निश्चित रूप से सुधार आया है, इसलिए वे इन चीजों के लिए प्रावधान करने की हालत में हैं. उधारी भी संप्रभु गारंटी के साथ दी जा रही है. बैंक जानते हैं कि वे बदतर हालत में नहीं हैं और उन्हें ईसीजीएलएस के मुताबिक कर्ज देना होगा, जिसे हमने अब और ज्यादा सेगमेंट के लिए खोल दिया है.

● ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिहाज से, 'टैक्स टेररिज्म' को लेकर शिकायतें थीं कि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के अलावा केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआइ) और केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) उद्यमियों के बीच डर का माहौल पैदा कर रहे थे. आपने यह धारणा कैसे बदली?
हमने सीवीसी, सीबीआइ, ईडी और बैंकों के साथ लगातार बैठकें कीं और उन्हें बताया कि हमें करदाताओं से निबटते वक्त बहुत ज्यादा प्रोफेशनल होना होगा. बैंकों को भी एहसास हुआ कि सच्चे व्यावसायिक फैसलों को समझना होगा और अगर कुछ गड़बड़ हो गई है तो उसे सुलझाना ग्राहक और उस बैंक के ऊपर है. तो इससे न केवल राजस्व बढ़ाने में मदद मिली बल्कि साफ तस्वीर बनाने में भी कि इस सरकार की मंशा क्या है.

> **"जनवरी से ही यह बात कही जा रही थी कि इसे (वैक्सीन की खरीद और वितरण) राज्यों पर ही छोड़ दिया जाए; सवाल था कि केंद्र को यह काम क्यों करना चाहिए...हम (राज्यों को) जिम्मेदारी नहीं ठहरा रहे लेकिन यह बात चर्चा में लगातार और जोरों से उठती आ रही थी"**

> **दालों, खाद्य तेलों और दूसरी आवश्यक वस्तुओं के दाम बढ़ने के मुद्दे पर मंत्रियों का एक समूह इनके पीछे क कारणों की पड़ताल कर रहा है. इसके अलावा, आयात पर चर्चा करते हुए वह इस बात को भी पक्का कर रहा है कि दाम टूटने से किसानों को किसी तरह का नुक्सान न होने पाए**

साथ ही, जैसा कि प्रधानमंत्री ने वादा किया था, हम करदाताओं के लिए फेसलेस एसेसमेंट (चेहराविहीन आकलन) और फेसलेस अपील (की व्यवस्था) लेकर आए, और यह सब इसलिए कि हमने टेक्नोलॉजी को पूरी तरह से अपनाया. यहां तक कि जब आप अपील के लिए जाते हैं, आपको पता नहीं होता कि कौन-सा अफसर आपका एसेसमेंट करेगा. इस बजट में हमने एक अहम बदलाव यह किया कि छह साल से पहले का कोई भी इनकम टैक्स एसेसमेंट रिकॉर्ड खोला नहीं जा सकता. लोगों ने देखा कि प्रधानमंत्री ने टैक्स टेररिज्म यानी कर आतंकवाद को खत्म करने के संबंध में जो कुछ कहा, वह कई तरीकों से वास्तव में जमीन पर हुआ है. मेरे ख्याल से अब यह आम धारणा है कि हम गंभीर और इरादों के पक्के हैं और यहां लोगों को परेशान करने के लिए बिल्कुल नहीं हैं.

● क्या जीएसटी (माल और सेवा कर) संग्रह में उछाल इसलिए आया कि लोगों में छापों का डर बैठ गया है और वे स्वेच्छा से कर चुका रहे हैं?

यह सच है कि हमारे अफसर डेटा की छानबीन के लिए और यह देखने के लिए कि कर चोरी कहां हो रही है, आर्टिफीशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल कर रहे हैं. हम अब न केवल पकड़ पा रहे हैं कि समस्या कहां है बल्कि उन कड़ियों का पीछा भी कर पा रहे हैं. एक ही बार में आप उस शेल कंपनी का पता लगा सकते हैं जिसने कोई कर चोरी की है या व्यवस्था को चकमा दिया है. उसके बाद तो टेक्नोलॉजी के जरिए सुराग अपने आप सामने आने लगते हैं और आप उन लोगों को पता लगा सकते हैं जो ऊपर से एक दूसरे से जुड़े नहीं मालूम देते. इससे लोगों को एहसास हुआ कि वे छिपे नहीं रह सकते और इससे ज्यादा राजस्व उगाहने में मदद मिली.

● क्या आपको लगता है कि कोविड ने संघवाद की भावना में सेंध लगाई है, खासकर जीएसटी के मामले में तकरार को देखते हुए?

कैसी तकरार? मैं चाहूंगी कि मीडिया जीएसटी काउंसिल सरीखे संघीय निकाय के बारे में बेहतर जानकार बने. जब राज्यों के वित्त मंत्री, और उनमें से कुछ तो यह पोर्टफोलियो संभाल रहे मुख्यमंत्री हैं, मिलते हैं, तो चर्चाएं, खंडन-मंडन और तर्क-वितर्क होंगे, पर यह फोरम इसी के लिए तो है. क्या यह तकरार या संघवाद में सेंध है? जीएसटी परिषद संघीय ढांचे के तहत चर्चा का ही निकाय है. जब हम कहते हैं कि मंत्रियों का एक समूह कोविड के इलाज से जुड़ी चीजों को कर से छूट देने के बारे में फैसला करेगा, तो यह हल निकालने का मैत्रीपूर्ण तरीका है या शत्रुतापूर्ण? जीएसटी परिषद के हरेक सदस्य को श्रेय देना होगा कि वे पूरी तरह एक अगुआ की तरह व्यवहार कर रहे हैं.

● क्या ईसीजीएलएस और दिए गए प्रोत्साहनों तथा मोहलतों के बाद एनपीए की बाढ़ आ गई है? क्या बैंक और वित्त मंत्रालय चिंतित है?

नहीं, अगर आप हमारे उठाए गए कदमों को देखें. हमने ऐसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी (एआरसी) मॉडल इस तरह बनाया कि एनपीए (गैर निष्पादित संपत्तियां) एक धारक कंपनी के पास चली जाएंगी, जो पूरे सोच-विचार के बाद ऐसेट इनवेस्टमेंट फंड को आमंत्रित करेगी कि वे आएं और बोली लगाएं और उसे ले लें. तो हमने जिस तरह इसकी योजना बनाई है, वह यह है कि बैंकों को यकीन है कि पिछले काफी समय से चले आ रहे एनपीए—कोविड से संबंधित नहीं—अपना हल खोज लेंगे और कुछ हद तक पहली बार में फिर आखिरी चरण में उसके बेचे जाने पर अपना वाजिब हिस्सा हासिल कर लेंगे. बाकी बचा हिस्सा बैंकों के पास आ जाएगा.

अब 2020 के दौरान हमने ऋणशोधन अक्षमता और दिवाला संहिता (आइबीसी) की इन धाराओं को निलंबित कर दिया, इसलिए कोई भी लोगों को कोविड से जुड़ी नाकामियों की वजह से इनसॉल्वेंसी (ऋणशोधन अक्षमता) के लिए नहीं पकड़ सकता. इससे काफी मदद मिली और अब हमारे लिए यह साफ है कि आइबीसी, ईसीजीएलएस और दी जा रही अतिरिक्त सहायताओं के बल पर उनमें से कई बचे रह सकेंगे और बेहतर दिनों की तरफ बढ़ेंगे. बैंक व्यावसायिक कामकाज में दबाव के स्तर की लगातार निगरानी करते हैं. मैं कंपनी मामलों के मंत्रालय से भी कह रही हूं कि वे कंपनियों को देखें और बाजार में उनके ऊपर पड़ने वाले दबाव के स्तर को समझें. तो कंपनी मामलों के मंत्रालय और बैंकों के जरिए मंत्रालय रियल-टाइम निगरानी कर रहे हैं. इससे हम इस परेशानी को हल कर पा रहे हैं और लोगों को अचानक नाकाम होने से बचा पा रहे हैं. ■

आखिर कैसे रफ्तार पकड़े अर्थव्यवस्था

कोविड की दूसरी घातक लहर ने पहले से लहूलुहान अर्थव्यवस्था की चूलें हिला दीं, उपभोक्ताओं का भरोसा, उद्योग-धंधों और रोजी-रोजगार की बहाली के लिए अब असाधारण नजरिए और कदमों की दरकार

एम.जी. अरुण और श्वेता पुंज

अचानक ठप्प

1 जून को मुंबई में सिले-सिलाए वस्त्रों का थोक बाजार मंगलदास मार्केट

मंदार देवधर

मई में जब प्रियजनों के लिए अस्पतालों में बिस्तर, ऑक्सीजन और दवाइयों के लिए जद्दोजहद करते लोगों और श्मशानों में लंबी कतारों के मनहूस दृश्य खबरों में छाए थे, कोविड 2.0 चुपचाप कहीं और भी कहर बरपा रहा था और वह थी अर्थव्यवस्था. दूसरी लहर ने जिस अप्रत्याशित प्रचंडता से हमला बोला, उसने पिछले वित्त वर्ष की दूसरी छमाही में देश में हुई थोड़ी-बहुत आर्थिक बहाली को भी पटरी से उतारने का खतरा पैदा कर दिया है (ताजा आंकड़ों के मुताबिक, पिछले वित्त वर्ष की पहली छमाही में नकारात्मक वृद्धि के मुकाबले दूसरी छमाही की दोनों तिमाहियों में सकारात्मक वृद्धि दर्ज हुई). हालांकि इस बार देशव्यापी लॉकडाउन से बचा गया, लेकिन राज्य लॉकडाउन लगाने पर मजबूर हुए. लिहाजा, निवेश फर्म बार्कलेज के मुताबिक, देश को मई के हर हफ्ते करीब 8 अरब डॉलर या 58,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की कीमत चुकानी पड़ी.

फैक्ट्रियों में बंदी और छंटनी ने बेरोजगारी दर को दहाई अंकों में धकेल दिया. 23 मई को खत्म सप्ताह में यह 14.73 फीसद पर पहुंच गई. लॉकडाउन की पाबंदियों के साथ नौकरियों के जाने और तनख्वाह में कटौतियों के चलते एफएमसीजी (उपभोक्ता सामान) श्रेणी की कई चीजों के साथ टीवी, रेफ्रिजरेटर, परिधान और फूटवियर सरीखे टिकाऊ उपभोक्ता सामान की बिक्री थम गई. फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन (एफएडीए) के मुताबिक, कारों की बिक्री में मार्च के मुकाबले अप्रैल में 25 फीसद से ज्यादा की गिरावट आई, जबकि दोपहिया वाहनों की बिक्री 27 फीसद से ज्यादा गिरी. 2020 के सख्त लॉकडाउन से लहूलुहान ट्रैवल और हॉस्पिटैलिटी क्षेत्र अब भी खस्ताहाल है.

कई फर्मों ने देश की वृद्धि के 11-12 फीसद के अनुमानों को घटाकर 8 फीसद या उससे भी कम कर दिया है (देखें ग्राफिक *हताशाजनक अनुमान*). पूर्व वित्त सचिव सुभाष चंद्र गर्ग कहते हैं, ''वृद्धि में तीन फीसद कमी का भी मतलब है अर्थव्यवस्था के लिए 6-6.5 लाख करोड़ रुपए का नुक्सान. पिछले साल हम 20 लाख करोड़ रुपए से हाथ धो बैठे थे.'' तीसरी लहर की स्थिति में बार्कलेज भारत में 'मंदड़िया दौर' की चेतावनी देता है. मौजूदा वित्त वर्ष में वृद्धि अंतत: 7.7 फीसद रह सकती है, जो आरबीआइ (भारतीय रिजर्व बैंक) के 10.5 फीसद के अनुमान से काफी कम है. वह भी तब जब पिछले वित्त साल में भारत की वृद्धि में 7.3 फीसद की गिरावट आई. अधिकारियों का अनुमान था कि अर्थव्यवस्था 8 फीसद सिकुड़ जाएगी.

देश में अव्वल स्टीम इंजीनियरिंग और कंट्रोल इंस्ट्रुमेंटेशन फर्म फोर्ब्स मार्शल के चेयरमैन नौशाद फोर्ब्स ने *इंडिया टुडे* से कहा, ''दूसरी लहर का लोगों के दिलो-दिमाग पर भीषण असर है. उनके बाहर निकलने और खर्चना शुरू करने में थोड़ा वक्त लगेगा.'' वस्तुओं और लोगों की आवाजाही पर नजर रखने वाले गूगल के मोबिलिटी और दूसरे डेटा मई के तीसरे हफ्ते तक खुदरा, किराना, आवाजाही स्टेशनों और टोल नाकों पर कामकाज में मार्च और अप्रैल के मुकाबले गिरावट दिखा रहे हैं. कोटक महिंद्रा ऐसेट मैनेजमेंट के मैनेजिंग डायरेक्टर नीलेश शाह कहते हैं, ''अर्थव्यवस्था पर पहली लहर के मुकाबले (कोविड-19 की) कहीं ज्यादा लंबी छाया पड़ी है. दबी हुई मांग ने पहली लहर के बाद बहाली को सहारा दिया था, पर इस बार उत्साह लौटने में कुछ वक्त लग सकता है.''

अर्थव्यवस्था के 50 खरब डॉलर के लक्ष्य पर पहुंचने की उम्मीदें तो खैर पक्के तौर पर चकनाचूर हो चुकी हैं, खासकर महामारी से पहले भी यह उम्मीद से कम 5 फीसद की वृद्धि दर पर लड़खड़ा रही थी. नरेंद्र मोदी सरकार ने पिछले साल गरीब और लाचार लोगों के लिए गारंटीशुदा कर्ज और सामाजिक योजनाओं में 20 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा झोंके, पर कई सारे सुधार अब भी अधर में अटके हैं.

अधर में नौकरियां

रिसर्च फर्म सीएमआइई (सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी) के मुताबिक, फरवरी और अप्रैल के बीच नब्बे लाख वैतनिक नौकरियां चली गईं. 97 फीसद परिवारों की आमदनियों में गिरावट आई. अर्थव्यवस्था में मांग फूंकने वाला मूल तबका मध्यम वर्ग भी बुरी तरह टूट चुका है. अमेरिका स्थित प्यू रिसर्च सेंटर की मार्च की शोध रिपोर्ट से पता चला कि पिछले साल कोविड ने करीब 3.2 करोड़ हिंदुस्तानियों को मध्यम वर्ग के दायरे से नीचे धकेल दिया, जो रोजाना 10 डॉलर (724 रुपए) से 20 डॉलर (1,449 रुपए) कमाते थे. एक रिपोर्ट के मुताबिक, मध्यम वर्ग एक-तिहाई तक सिकुड़ गया है—महामारी से पहले 9.9 करोड़ से अब 6.6 करोड़ पर आ गया है.

"पहली लहर के दौरान ठहरी हुई मांग से अर्थव्यवस्था में बहाली तेज हुई, मगर इस बार मनोबल काफी टूटा हुआ है"

नीलेश शाह
एमडी, कोटक महिंद्रा एसेट मैनेजमेंट

ग्रामीण इलाकों में हालात और बदतर हैं. पहली लहर में तो ग्रामीण वृद्धि और रोजगार ने अर्थव्यवस्था की गिरावट को संभाल लिया था. मगर इस बार ग्रामीण इलाकों में बढ़ते संक्रमण और पाबंदियों की वजह से ग्रामीण भारत में बेरोजगारी दर 13.5 फीसद पर पहुंच गई है, जबकि शहरी इलाकों में यह 17.4 फीसद है. सीएमआइई के सीईओ और एमडी महेश व्यास कहते हैं, ''श्रम भागीदारी की दर 2016 से ही लगातार गिरती रही है. 2016-17 में 46.1 फीसद से यह 2021 में 39.9 फीसद पर आ गई है. देश में अच्छी नौकरियां नहीं हैं और महिलाओं के लिए श्रम बाजार में हिस्सा लेना ज्यादा से ज्यादा मुश्किल होता गया है.'' इससे 1990 के दशक का फायदों का वह दौर उलट गया है जब कई लोग कृषि से फैक्ट्रियों में काम करने आ गए थे. व्यास कहते हैं, ''अब लोग

फिर खेतों में लौट रहे हैं, जो अर्थव्यवस्था में प्रच्छन्न बेरोजगारी बढ़ा रहा है.''

अनौपचारिक अर्थव्यवस्था में काम कर रहे करोड़ों लोग अब मुश्किल में हैं, जो पहले अपने गांव और कस्बे छोड़कर शहर आ जाते थे और कम हुनर वाले काम-धंधों में, नाई की दुकान, ढाबे या किराने की दुकान सरीखे कामकाज में खपा लिए जाते थे. देश में मैन्युफैक्चरिंग की रीढ़ कहा जाने वाला एमएसएमई क्षेत्र सबसे नाजुक हालत में है. देश में 6.34 करोड़ एमएसएमई हैं, जो मैन्युफैक्चरिंग में 45 फीसद और निर्यात में 40 फीसद का योगदान और करीब 12 करोड़ लोगों को रोजगार देते हैं. ऑल इंडिया मैन्युफैक्चरर्स ऑर्गेनाइजेशन के जून 2020 के एक सर्वे से पता चला कि देश के 35 फीसद एमएसएमई और स्वरोजगार में लगे 37 फीसद लोगों को महामारी की वजह से कारोबार बंद करने पड़े. इस बार नुक्सान केवल आर्थिक नहीं है; कई उद्यमियों को कोविड की वजह से जान गंवानी पड़ी. एफआइएसएमई (फेडरेशन ऑफ इंडियन माइक्रो, स्मॉल ऐंड मीडियम एंटरप्राइजेज) के सेक्रेटरी जनरल अनिल भारद्वाज कहते हैं, ''इस बार नुक्सान दीर्घकालिक है.''

ग्रामीण तबाही

पहली लहर में ग्रामीण अर्थव्यवस्था संकटमोचन बनकर उभरी थी, जब अच्छी कृषि उपज और कुछ हद तक खपत ने संभाल लिया था. कामगार अपनी जेबों में बचत लिए शहरों से अपने गांवों में लौट गए थे और सरकार कमजोरों की मदद के लिए धन झोंक रही थी. कई ने लौटकर खेती-किसानी संभाल ली और दूसरों ने सरकार की ग्रामीण बेरोजगार गारंटी योजना मनरेगा में रोजगार पकड़ लिए.

अलबत्ता, कृषि अर्थशास्त्री और दिल्ली के जेएनयू (जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय) में एसोसिएट प्रोफेसर हिमांशु कहते हैं कि दूसरी लहर में देश के देहात में कोविड-19 के प्रकोप से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को तगड़ा धक्का लगा. राज्य सरकारों को नकदी की तंगी है और लोग अपनी बचत खर्च कर चुके हैं. कृषि में उपजों के दाम घट रहे हैं जबकि खेती की लागत लगातर बढ़ रही है. बहुत रोजगार देने वाला निजी निर्माण क्षेत्र ठहरा पड़ा है.

मोदी सरकार ने 2020 में कुछ खास तबकों, प्रवासी कामगारों, रेहड़ी-पटरी लगाने वाले, छोटे उद्योग-धंधों के लिए कई योजनाएं घोषित की थीं. मसलन, गरीब कल्याण

''जितनी जल्दी हो सके, ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगाई जाए. इससे यकीनन अर्थव्यवस्था की बहाली की रफ्तार तेज होगी''

आर.सी. भार्गव
चेयरमैन, मारुति सुजुकी

रोजगार अभियान का लक्ष्य गांव लौट रहे मजदूरों को बुनियादी ढांचे के निर्माण सहित 25 अलग-अलग किस्म के कामों में 125 दिन का रोजगार मुहैया करना था. योजना में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, झारखंड और ओडिशा सरीखे राज्यों 116 जिलों में लौटे 25,000 प्रवासी कामगारों को शामिल करना था. प्रधानमंत्री रेहड़ी-पटरी आत्मनिर्भर निधि (पीएम-स्वनिधि) योजना का लक्ष्य रेहड़ी-पटरी वालों को सस्ती ब्याज दर पर 10,000 रुपए तक के कर्ज मुहैया कराना था. इसी तरह, उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन (पीएलआइ) योजना का लक्ष्य मैन्युफैक्चरिंग फर्मों को प्रोत्साहन देना था. पीएम-स्वनिधि में 27.3 लाख रेहड़ी-पटरी वालों को कर्ज मिले. केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालय के मुताबिक, कंपनियों ने पीएलआइ के तहत 1,300 करोड़ रुपए का निवेश किया और अपने कामकाज के पहले पांच महीनों में करीब 22,000 नौकरियों का सृजन किया.

विशेषज्ञों का कहना है कि इन योजनाओं ने कुल मिलाकर भुखमरी के हालात पैदा नहीं होने दिया. मगर भारत जितने विशाल देश में इन समाधानों को ज्यादा दूरगामी और प्रभावी ढंग से लागू करने की जरूरत है.

नई जान फूंकने का नुस्खा

विशेषज्ञों का कहना है कि एक तो देश को छोटी, मध्यम और दीर्घ अवधि के लिए क्रमबद्ध आर्थिक उपायों की जरूरत है. गर्ग के मुताबिक, सरकार की चुनौती मौजूदा तकलीफ को दूर करके ज्यादा ऊंची वृद्धि दर का इंतजाम करना है. छोटे वक्त में उन मजदूरों को राहत देनी होगी, जो काम न होने से हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं. मसलन, दिल्ली सरकार ने हरेक पंजीकृत ऑटो और टैक्सी ड्राइवर को 5,000 रु. का अनुदान देने का ऐलान किया है. महाराष्ट्र ने अप्रैल के मध्य में आर्थिक तौर पर कमजोर तबकों के लिए 5,476 करोड़ रु. के राहत पैकेज का ऐलान किया.

केंद्र ने भी मई के आखिर में कोविड पीड़ित परिवारों को राहत देने के लिए पहल शुरू की. उसने कोविड से अनाथ हुए हरेक बच्चे के लिए उसके 18 साल का होने पर 10 लाख रुपए की धनराशि मिलना पक्का करने के उपाय की घोषणा की. कर्मचारी राज्य बीमा निगम योजना के तहत पेंशन का दायरा बढ़ाकर उसमें कोविड से मृत लोगों के आश्रितों को भी शामिल किया गया. कर्मचारियों की जमा से जुड़ी बीमा योजना के लाभ ईपीएफओ (कर्मचारी भविष्य निधि संगठन) के तहत पंजीकृत सदस्यों को भी दिए गए.

फोर्ब्स कहते हैं कि मध्यम अवधि में सरकार को हॉस्पिटैलिटी और रिटेल सरीखे संकटग्रस्त क्षेत्रों को उबारने में मदद देने की जरूरत है. उन्हें लगता है कि लंबे वक्त में देश को रोजगार वृद्धि की मजबूती बहाल करने के लिए काम करना चाहिए. वे कहते हैं, ''अपने इन्फ्रास्ट्रक्चर कार्यक्रमों को वापस पटरी लाना बेहद अहम है.'' केंद्र ने 2019 में पांच साल की अवधि में 110 लाख करोड़ रु. की महत्वाकांक्षी नेशनल इन्फ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन परियोजना शुरू की थी, लेकिन मंदी की अर्थव्यवस्था ने इसकी प्रगति ठप कर दी. कुछ का कहना है कि केंद्र अगर राज्यों को जीएसटी के बकाया 63,000 करोड़ रुपए (31 मार्च 2021 तक) का भुगतान कर दे, तो इससे उनका वित्तीय बोझ कुछ हल्का हो सकेगा.

चाहिए 1991 वाला जज्बा

कोटक के शाह का कहना है कि देश को ''1991 जैसे जज्बे'' की दरकार है. वैसे ही संकल्प की, जिससे नरसिंह राव सरकार ने आर्थिक उदारीकरण एजेंडे से देश की व्यापार और औद्योगिकी नीतियों को पूरी तरह बदल डाला था. इनसे अंततः निजी उद्यमशीलता और उसके बाद वृद्धि को बढ़ावा मिला. वे कहते हैं, ''आरबीआइ ने नकदी बढ़ाने का

“इन्फ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं को फिर जिंदा करना बहुत जरूरी है. उनसे रोजगार बढ़ेगा और लोगों के हाथ में पैसा आएगा”

नौशाद फोर्ब्स, चेयरमैन, फोर्ब्स मार्शल

शानदार काम किया है. अब यह सरकार पर है कि वह उद्यमियों को सहारा दे.'' आइटी, फार्मास्यूटिकल्स और जिंसों के क्षेत्र में कार्यरत कंपनियां बढ़ रही हैं जबकि वाहन, एमएसएमई, ट्रैवल और टूरिज्म और खुदरा क्षेत्र लड़खड़ा रहे हैं.

केयर रेटिंग्ज के चीफ इकोनॉमिस्ट मदन सबनवीस कहते हैं कि सरकार को अपनी नीतिगत घोषणाओं पर अमल भी करना होगा. जन धन योजना उसे हरेक की पृष्ठभूमि जानने की सुविधा देती है, जिसका इस्तेमाल वह जरूरतमंदों के खातों में सीधे नकद हस्तांतरण के लिए कर सकती है. हालांकि ऐसे भी मामले हैं, जिनमें कुछ वरिष्ठ नागरिकों को पिछले साल घोषित पेंशन योजना के प्रति माह 1,000 रु. नहीं मिल पा रहे हैं. उन्हें लगता है कि पीएलआइ योजना केवल बड़ी कंपनियों की मदद करेगी. वे कहते हैं, ''इलेक्ट्रॉनिक्स में विशाल मोबाइल कंपनियां ही कुछ कर पाएंगी, एमएसएमई नहीं.'' वे सिफारिश करते हैं कि सरकार संकटग्रस्त कंपनियों को कर छूट दे. टैक्स रिटर्न के जरिए इन कंपनियों की आसानी से पहचान की जा सकती है. हालांकि हर कोई मोरेटोरियम के पक्ष में नहीं है, क्योंकि वे भुगतान को केवल टालते भर हैं और वह भी बैंकों की वित्तीय सेहत की कीमत पर.

एमएसएमई में नई जान फूंकने के खातिर एफआइएसएमई ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से गुजारिश की है कि वे विशेष उल्लेख खातों (एसएमए) की मौजूदा प्रथा की समीक्षा करें. आरबीआइ ने एनपीए या डूबत कर्ज में बदलने की संभावना वाले खातों की पहचान के लिए 2014 में एसएमए की शुरुआत की थी. अगर कर्ज 90 दिनों के भीतर नहीं चुकाया जाता है तो वह एनपीए बन जाता है. मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, केंद्र आरबीआइ से बातचीत कर रहा है ताकि एनपीए घोषित करने की अवधि मौजूदा 90 दिनों से बढ़ाकर कम से कम 120 दिन की जा सके. साथ ही, एमएसएमई को ठोस रियायती दरों पर कर्ज का मिलना जारी रहना चाहिए. एफआइएसएमई यह भी चाहती है कि केंद्र शीर्ष 10 कच्चे माल की कीमतों में उतार-चढ़ाव की निगरानी करे और बढ़ी हुई कीमतों के संदिग्ध मामलों को भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग को भेज दे. साथ ही, प्रमुख कच्चे माल पर आयात शुल्क घटाकर शून्य कर दे.

‘ज्यादा रुपए छापो’

कोटक महिंद्रा बैंक के एग्जीक्यूटिव वाइस-चेयरमैन और एमडी उदय कोटक ने हाल में एक टेलीविजन इंटरव्यू में कहा कि कोविड से ध्वस्त अर्थव्यवस्था को सहारा देने के लिए देश को नकदी छापने की जरूरत है. उन्होंने कहा, ''मेरे विचार से यह सरकार की बैलेंस शीट के विस्तार का वक्त है, जिसे आरबीआइ का यथोचित समर्थन मिले... मौद्रिक विस्तार या धन की छपाई के लिए. हमारे लिए ऐसा कुछ करने का वक्त आ गया है... अगर अभी नहीं तो कब?'' अर्थशास्त्री और नोबेल पुरस्कार विजेता अभिजीत बनर्जी इसका अनुमोदन करते हैं और कहते हैं कि अतिरिक्त संसाधन गरीबों की सहायता कर सकेंगे.

अलबत्ता दिल्ली स्थित एनआइपीईपी (राष्ट्रीय लोक वित्त और नीति संस्थान) में प्रोफेसर इला पटनायक कहती हैं कि ऐसे कदम जोखिम का गुणा-भाग करने के बाद ही उठाए जाने चाहिए. यह अच्छी तरह तय कर लिया गया हो कि कितनी मुद्रा और छापने की जरूरत है और यह नकदी कब काम में लाई जाएगी. साथ ही, इससे बाहर निकलने की नीति भी साफ तौर पर तय कर ली गई हो.

इंडिया टुडे विशेषज्ञों के बोर्ड के मुताबिक (देखें *अर्थव्यवस्था बहाली का बेहतरीन नुस्खा*), मध्यम अवधि का नजरिया इस पर निर्भर करता है कि देश तीन प्रमुख कारकों से कैसे निपटता है. ये हैं कोविड को बेअसर करना, भविष्य के एजेंडे को आगे बढ़ाना और कारोबार में स्वाभाविक जोश-खरोश दोबारा कैसे लौटे. विशेषज्ञों का मानना है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य व्यवस्था और लागत पर सब्सिडी की योजनाओं को खत्म करने सरीखे कृषि सुधारों को अंजाम देने का यह सही समय है.

खर्च करने की गुंजाइश

संसाधन की कमी से अलबत्ता सरकार के हाथ बंधे हैं. विशेषज्ञों का कहना है कि उसे ज्यादा राजकोषीय घाटे (आमदनी और खर्च के बीच अंतर) को लेकर बहुत चिंतित नहीं होना चाहिए, क्योंकि महज एक फीसद अतिरिक्त खर्च करके बहुत सारी तकलीफ दूर की जा सकती है. वित्त वर्ष 2021 में केंद्र ने अपने राजकोषीय घाटे में 9.4 फीसद की तेज बढ़ोतरी के बाद बजट में मौजूदा वित्त वर्ष के लिए 6.8 फीसद राजकोषीय घाटे का लक्ष्य रखा था और मकसद इस घाटे को धीरे-धीरे कम करके 2026 के वित्त वर्ष तक 4.5 फीसद पर लाना था. केयर रेटिंग्ज के एक शोध पत्र के मुताबिक, मौजूदा और भावी स्थिति के अनुमान से इस लक्ष्य को हासिल कर पाने की संभावना है.

लॉकडाउन से वह इस वित्त वर्ष में कर संग्रह के बजट अनुमान से 15-20 फीसद या 46,000-62,000 करोड़ रुपए कम रहने की उम्मीद कर रही है. इसी तरह, 1.75 लाख करोड़ रुपए के विनिवेश लक्ष्य में भी 25-33 फीसद या 44,000-58,000 करोड़ रुपए की कमी रह सकती है.

आरबीआइ ने हाल में अपने अधिशेष से 99,122 करोड़ रुपए केंद्र को हस्तांतरित किए हैं, जो बजट अनुमान से 45,612 करोड़ रुपए ज्यादा हैं. फिर भी सरकार को कोविड से लड़ने के लिए और 49,000-66,000 करोड़ रुपए की जरूरत है.

मगर किसी भी अन्य चीज से पहले सरकार को साफ और समग्र वैक्सीन नीति बनाने की जरूरत है. टीके लगाने की बदलती रणनीति ने खर्च या निवेश के भरोसे को तोड़कर रख दिया है. मारुति सुजुकी के चेयरमैन आर.सी. भार्गव कहते हैं, ''सरकार को जल्द से जल्द ज्यादा से ज्यादा लोगों को टीके लगाने चाहिए.''

लिहाजा, सरकार को चाहिए कि वह प्राथमिकताएं तय करे, पीड़ित लोगों को तत्काल राहत मुहैया करे, अर्थव्यवस्था को अधिक लीचीला बनाए, ताकि वह भविष्य के झटके झेल सके. कोविड ने अर्थव्यवस्था को झकझोर दिया है, पर देश पहले भी संकटों से उबरकर निकला है. सरकार अपना ध्यान वृद्धि और बहाली पर टिकाए रखती है, तो यह मानने का कोई कारण नहीं कि ऐसा फिर नहीं हो सकता.

—साथ में, **अनिलेश महाजन**

रजनीश कुमार
पूर्व चेयरमैन, भारतीय स्टेट बैंक

डी.के. जोशी
मुख्य अर्थशास्त्री, क्रिसिल

अदिति नायर
मुख्य अर्थशास्त्री, आइसीआरए

अर्थव्यवस्था बहाली का बेहतरीन नुस्खा

कोविड की दूसरी लहर ने देश की आर्थिक बहाली की नाजुक डोर पीछे खींच ली, बोर्ड ऑफ इंडिया टुडे इकोनॉमिस्ट्स का नजरिया कि कैसे लौटेगी गाड़ी पटरी पर

रजनीश कुमार: अर्थव्यवस्था बहाली की चढ़ती रफ्तार को कोविड की दूसरी लहर ने धीमा कर दिया. हालांकि दूसरा लॉकडाउन पहले वाले की तरह सख्त नहीं है, इसलिए अर्थव्यवस्था को वैसी चपत नहीं लगी, जैसी पिछली बार लगी थी. संक्रमण के मामले भी कम होने लगे हैं, यानी चरम स्थिति पार हो गई है. इन हालात में इस लहर की आर्थिक मार 2021-22 की पहली तिमाही तक या खिसककर जुलाई तक जाने की संभावना है. इस मोड़ पर यही सबसे आशावादी तस्वीर उभरती है. इससे महामारी के प्रोटोकॉल पर अमल, वैक्सीन तथा मेडिकल आपूर्ति, स्वास्थ्य सुविधाएं, तीसरी लहर की तैयारी वगैरह के लिए थोड़ी मोहलत मिल जाती है. इसके अलावा लोगों का दुनिया से उठ जाना, रोजगार खत्म होना और उत्पादन बैठना, सब कुछ निराशाजनक ही है.

डी.के. जोशी: जब तक 40 फीसदी आबादी को वैक्सीन नहीं लग जाती (अमेरिका और ब्रिटेन ने इसे अर्थव्यवस्था खोलने की पहली शर्त बनाया), डर बना रहेगा और राज्यों को पूरी तरह खोलने के पहले सवाधानी बरतनी होगी. हमें आशंकित तीसरी लहर के लिए भी तैयार रहना है.

आर्थिक गतिविधि पर इन सभी वजहों का असर विभिन्न सूचकांकों में दिखता है. पहली लहर में पर्यटन, होटल-रेस्तरां और हवाई यात्रा जैसे ठेका आधारित सेवाओं में कामकाज और रोजगार पर बड़ी मार पड़ी और इस साल भी उनकी हालत खस्ता है. इसी से वृद्धि दर के अनुमानों में संशोधनों का पता चलता है,

एस.सी. गर्ग
पूर्व वित्त सचिव

पिनाकी चक्रवर्ती
डायरेक्टर, नेशनल इंस्टीटयूट ऑफ पब्लिक फोइनेंस ऐंड पॉलिसी

डी.के. श्रीवास्तव
मुख्य पॉलिसी सलाहकार, ईवाइ इंडिया

प्र अर्थव्यवस्था को कितनी बुरी मार पड़ी है? खासकर अनलॉक 2.0 धीरे-धीरे होता है तो मध्यावधि में वृद्धि दर का आकलन क्या है?

जो कुछ महीने पहले के दहाई अंक से इकाई पर आ टिके हैं. अगर वैक्सीन की आपूर्ति योजना के मुताबिक अगस्त के बाद बढ़ती है और वैक्सीन लगाने की दर रफ्तार पकड़ती है तो वित्त वर्ष के दूसरे हिस्से और अगले वित्त वर्ष की संभावना उज्ज्वल होगी.

मध्यावधि में निजी निवेश और उत्पादन से जुड़ी सरकारी प्रोत्साहन योजनाओं की मदद से सालाना 6 और 6.5 फीसद वृद्धि दर की उम्मीद है. लेकिन कुल मिलाकर लंबी अवधि में अर्थव्यवस्था पर असर पड़ेगा.

बढ़ती गैर-बराबरी और पारिवारिक बजट सिकुड़ने से आर्थिक बहाली कमजोर पड़ सकती है. फिलहाल, यह तय लगता है कि सरकार को भारी खर्च करना होगा-सिर्फ स्वास्थ्य क्षेत्र में ही नहीं, बल्कि उसे हर तरह के नुक्सान की भरपाई करनी होगी.

› एस.सी. गर्ग: 2019-20 में सिर्फ 4 फीसद की वृद्धि दर से 2020-21 में 7-8 फीसद तक सिकुड़ जाने के बाद 2021-22 में भी सुस्त बहाली, देश मानो थम गया है.

अर्थव्यवस्था 2018-19 के वास्तविक जीडीपी दर पर ठहरी हुई है, यह दुर्भाग्यपूर्ण है. इसका मतलब है कि करोड़ों की नौकरियां जा रही हैं और आमदनी टूट रही है. इससे सरकारी कर संग्रह को भी चपत लगी, सिर्फ पेट्रोलियम टैक्स ही कायम रहा, जिसे सरकार ने ढिठाई से बेहिसाब ऊंचा रखा हुआ है.

मध्यावधि संभावनाएं इस पर निर्भर करेंगी कि देश तीन प्रमुख पहलुओं पर कैसे आगे बढ़ता है—एक, कोविड संक्रमण पूरी तरह सामान्य हो जाता है. दो, सरकार भविष्य के एजेंडे पर जरो देती है. और तीन, कारोबार अपनी स्वाभाविक रफ्तार पकड़ लेते हैं. अगर ये सभी स्थितियां वृद्धि को प्रोत्साहन देने वाली हुईं तो देश 2022-23 से 7 से 8 फीसद वृद्धि दर की ऊंची पटरी पर चल पड़ सकता है. अगर सरकार अपना हिसाब दुरुस्त नहीं कर पाती, या कारोबार रफ्तार नहीं पकड़ते तो देश 4-5 फीसद की निम्न वृद्धि दर की ओर फिसल जाएगा.

› अदिति नायर: दूसरी लहर में खासकर ग्रामीण इलाकों में रोजना संक्रमण मामलों में तेज उछाल का लोगों की क्रय-शक्ति पर लंबे समय तक असर दिखेगा. इसके अलावा कोविड इलाज के भारी-भरकम खर्च और पेट्रोल-डीजल की ऊंची कीमतें ग्रामीण और शहरी इलाकों में खर्चने लायक आमदनी को कम कर सकती हैं. हालांकि सुस्त घरेलू मांग कीमतों पर ऐसे दौर में अंकुश लगाएंगी, जब वैक्सीन से उपजी उम्मीदों ने उपभोक्त वस्तुओं की कीमतें दुनिया भर में बढ़ा दी हैं. इससे घरेलू उत्पादकों का पड़ता कम हो सकता है. लिहाजा, वित्त वर्ष 2022 में जीडीपी में दहाई वृद्धि दर की उम्मीदें हमेशा के लिए बुझ गई हैं. दूसरी बात यह है कि वैक्सीन लगाने से तीसरी कोविड लहर रुकती है, तो वित्त वर्ष 2022 के अंत में आर्थिक गतिविधियों में उठान दिख सकता है.

› पिनाकी चक्रवर्ती: दूसरी लहर में देशव्यापी लॉकडाउन नहीं हुआ. वैक्सीन आ गई है, और उम्मीद है कि तीसरी लहर की रोकथाम के लिए पर्याप्त सावधानी हम बरत पाएंगे. बड़े पैमाने पर टीकाकरण ही सामान्य आर्थिक गतिविधि के लौटने की शर्त है.

› डी.के. श्रीवास्तव: अर्थव्यवस्था को 2021-22 की पहली तिमाही में भारी झटका लगेगा. निर्माण, व्यापार, परिवहन, होटल और उत्पादन क्षेत्र में बुरा असर दिखेगा. सरकार दूसरी और अगली तिमाहियों में ठोस वित्तीय प्रोत्साहन देती है तो नुक्सान की कुछ भरपाई हो सकती है. टीकाकरण की रफ्तार बढ़ाई जाए. 2021-22 में 9-9.5 फीसद जीडीपी वृद्धि दर संभव है. 2020-21 के लिए एनएसओ का अस्थाई वृद्धि दर का अनुमान (-)7.3 फीसद है, इसके पहले उसका अनुमान (-)8 फीसद था. मध्यावधि में देश 7 फीसद दर हासिल करने और उसे बनाए रखने की दिशा में बढ़ सकता है. ■

प्र इतनी नौकरियों के खत्म होने और छोटे उद्योग-धंधों के चौपट हो जाने के बाद आय में मदद के क्या उपाय हैं?

रजनीश कुमार: विशुद्ध रोजगार सर्वेक्षणों से पता चला है कि अनेक नौकरियां स्थायी रूप से समाप्त हो गईं जिससे बेरोजगारी में तेज वृद्धि हुई है. विश्व बैंक के ताजा आंकड़ों के अनुसार 2019 में देश की कुल श्रम शक्ति 49.5 करोड़ से घट कर 47.2 करोड़ हो गई. एक अनुमान के अनुसार, कर्मचारियों की तनख्वाह से निकलने वाला कुल ईपीएफओ और एनपीएस योगदान पिछले वित्त वर्ष की तुलना में लगभग 19 लाख रुपये कम था. करीब 284 सूचीबद्ध कंपनियों के कर्मचारियों के खर्च के आंकड़ों के विश्लेषण में पाया गया कि वित्त वर्ष 2021 में बड़ी कंपनियों (1000 करोड़ रु. से अधिक कारोबार वाली) के कर्मचारियों को छोड़ कर, सभी कंपनियों के कर्मचारियों के खर्च में गिरावट आई है. बड़ी गिरावट छोटी फर्मों में दिखी.

आय में इजाफे के लिए उद्योग-धंधों को मदद की दरकार है. देश में सबसे अधिक रोजगार वाले खुदरा, आतिथ्य और एमएसएमई क्षेत्र के लिए प्रोत्साहन पैकेज के साथ तत्काल नकद राहत की आवश्यकता है.

डी.के. जोशी: भारतीय रिजर्व बैंक ने कई बिलकुल ठीक कदम उठाए हैं. मसलन, सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्रों की मदद और कोविड के खिलाफ लड़ाई में अग्रिम मोर्चे पर मौजूद स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में नकद प्रवाह बढ़ाने के साथ ही माइक्रोफाइनेंस संस्थानों और छोटे तथा मझोले उद्यमों को समर्थन. लेकिन राजकोषीय नीति में अपेक्षित बदलाव नहीं हो रहा है, जो इस कठिन समय में अधिक प्रभावी हस्तक्षेप कर सकती है.

सबसे अधिक तकलीफ में शहरी गरीबों की मदद के लिए विशिष्ट और तत्काल उपायों की आवश्यकता है. ग्रामीण भारत में संक्रमण तेजी से बढ़ा है, इसलिए लंबे समय से उपेक्षित रहे ग्रामीण स्वास्थ्य ढांचे को बेहतर करने के लिए खर्च करने की दरकार है. रोजगार बढ़ाने और आजीविकाओं की रक्षा के लिए महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) के तहत आवंटन जरूर बढ़ाया जाना चाहिए.

एस.सी. गर्ग: सही मदद कार्यक्रम के लिए यह देखने की जरूरत है कि कौन से व्यवसाय पीड़ित हैं और किन्हें पटरी पर लाया जा सकता है. मोटे तौर पर अपरिवर्तित मांग और अनुकूल मानसून की प्रकृति के कारण पहले लॉकडाउन में कृषि पर फर्क नहीं पड़ा. लॉकडाउन 2.0 में भी शायद यह अप्रभावित रहेगी.

दुनिया भर में अधिकांश खाद्य और अन्य कृषि वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि हुई है. आयात की काफी मांग है जिसके कारण पिछले साल भारतीय कृषि निर्यात में काफी वृद्धि हुई. अफसोस की बात है कि जिंसों की कीमतों में उछाल के इस दौर में भी सरकार को 40 प्रतिशत से अधिक गेहूं की फसल की खरीद करनी पड़ी और प्रधानमंत्री किसान योजना को जारी रखना पड़ा. न्यूनतम समर्थन मूल्य तथा इनपुट सब्सिडी खत्म करने जैसे कृषि सुधारों यह सही समय है. इनके स्थान पर आय सहायता कार्यक्रम लागू किए जाने चाहिए, जिनसे किसानों और कृषि का बहुत भला होगा.

> “मनरेगा में आवंटन बढ़ाने से सबसे निचले पायदान की आबादी को आर्थिक मदद मिल सकती है और मांग बनाए रखी जा सकती है”
>
> अदिति नायर

देश में असंगठित छोटे धंधों में लगे लोगों का कोई डेटाबेस नहीं है. सरकार को ऐसे उद्योग-धंधों और श्रमिकों तक पहुंच बनाकर उन्हें प्रत्यक्ष वित्तीय सहायता प्रदान करनी चाहिए. इन धंधों को बैंक ऋण नहीं मिलता है. पिछले 12 महीनों में चार बार विस्तार के बावजूद कुल तीन लाख करोड़ रुपए की भी गारंटी न प्रदान कर सकी आपात ऋण साख गारंटी योजना का विस्तार करने से कोई लाभ नहीं है क्योंकि यह 90 फीसद छोटे धंधों के लिए कारगर नहीं है.

अदिति नायर: दूसरी लहर के दीर्घकालिक असर को देखते हुए, ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में मांग बढ़ाने के लिए मदद की आवश्यकता पड़ सकती है. अभी अप्रैल-मई 2021 के लिए घोषित मुफ्त खाद्यान्न उपलब्ध कराकर ऐसा किया जा सकता है. इसके अतिरिक्त, लक्षित नकद हस्तांतरण पर विचार किया जा सकता है. श्रमिक ग्रामीण क्षेत्रों में लौट गए हैं, इसलिए मनरेगा आवंटन में वृद्धि से सबसे निचले पायदान के लोगों को मदद मिल सकती है और मांग बनाए रखी जा सकती है. इसके अलावा, पेट्रोल-डीजल की कीमतें रिकॉर्ड ऊंचाई पर हैं, उत्पाद शुल्क में कटौती से खासकर शहरी क्षेत्रों में मदद हो सकती है, .

पिनाकी चक्रवर्ती: पहली लहर के दौरान रुकी हुई मांग का लाभ मिला तो कुछ भरपाई हुई थी. दूसरी लहर में ऐसा नहीं है. मध्यम अवधि में मांग कमजोर रह सकती है. श्रेणीबद्ध तरीके से राजकोषीय और मौद्रिक दोनों तरह की मदद की दरकार है.

डी.के. श्रीवास्तव: शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारों को तत्काल सहायता की आवश्यकता है. यह पहली और दूसरी तिमाही में सबसे जरूरी है. एमएसएमई क्षेत्र में भी तेजी से गतिविधियां शुरू हों तो मदद मिल सकती है, बशर्ते उसे रियायती दरों पर ऋण प्राप्त हो. केंद्र के शुद्ध कर राजस्व में अप्रैल, 2021 में आई तेज उछाल की मदद से ऐसा करना आसान होगा. ध्यान रहे कि सीजीए के आंकड़ों के अनुसार, अप्रैल 2020 में लगभग 21,000 करोड़ रुपए की तुलना में अप्रैल 2021 में कुल राजस्व 1.31 लाख करोड़ रुपए था. यह भी तय करना चाहिए कि राजस्व प्राप्तियां कम रहें तब भी खर्च में कमी न हो. राजस्व कम पड़े तो उसे अतिरिक्त उधारी से पूरा किया जाना चाहिए. ■

प्र

सरकार की प्राथमिकता में किस किस्म का बदलाव होना चाहिए? क्या यह मोदी सरकार के लिए 1991 जैसा क्षण है, यानी उसे कुछ बड़े बदलाव करने की कोशिश करनी चाहिए?

रजनीश कुमार: बदहाल क्षेत्रों को सीधे वित्तीय प्रोत्साहन देना पहली प्राथमिकता होनी चाहिए. कोविड पीड़ितों के परिवारों को सीधे नकद हस्तांतरण की भी जरूरत है ताकि टूट चुकी खपत कुछ बढ़े. मंदी के पहले के दौर में ऐसा नहीं हुआ, मगर इस बार निजी खपत घटी, सेवा क्षेत्र और कम हुनरमंद कामगारों की छंटनी हुई है. समाज के सबसे कमजोर तबकों को सीधे वित्तीय सहायता वक्त की जरूरत है. सरकार को खासकर व्यापार और वाणिज्य के केंद्रों में टीके लगाने को प्राथमिकता देनी चाहिए, ताकि कारोबार तेजी से खुल सकें. साथ ही, टेक्नोलॉजी कारोबारों के चलते रहने में अहम भूमिका निभाती है, इसलिए सरकार को टेक्नोलॉजी के बुनियादी ढांचे में निवेश करना चाहिए.

डी.के. जोशी: यह 1991 के संकट से ज्यादा बड़ी चुनौती है—आर्थिक के साथ-साथ मानवीय संकट भी है. फिर 1991 में भारतीय अर्थव्यवस्था सकारात्मक जीडीपी वृद्धि के साथ बढ़ रही थी, जबकि 2021 के वित्तीय साल में यह तकरीबन 8 फीसद सिकुड़ गई है.

फिर भी पहली प्राथमिकता लोगों की सेहत ही होनी चाहिए. इसका मतलब है समूची आबादी को जल्द से जल्द टीके लगाना और वैक्सीन की दूसरी डोज का समय पर इंतजाम करना. अमेरिका और ब्रिटेन सरीखे उन्नत देशों से हम सीख सकते हैं कि लक्ष्य रखकर उन सेवाओं को ज्यादा तेजी से सक्रिय किया जा सकता है, जिनमें एक-दूसरे का संपर्क जरूरी है. जब तक हम यह नहीं हासिल कर लेते, राजकोषीय नीति को कमजोर उद्योग-धंधों और घर-परिवारों को उबारने के लिए उदारता से मदद का हाथ बढ़ाना ही चाहिए.

एस.सी. गर्ग: 1991 आर्थिक, वित्तीय और राजकोषीय नीतियों के ढांचागत बदलाव का क्षण था. असल में देश ने बदलाव के ऐसे दो क्षण देखे—1951 और 1991. 1951 में देश ने समाजवाद की राह पकड़ी, जो शुरुआत में भावनात्मक तौर आकर्षक थी लेकिन अंतत: बहुत नुक्सानदायक और महंगी साबित हुई. 1991 में देश में बड़े ढांचागत सुधार शुरू करके अर्थव्यवस्था को फिर पटरी पर लाने के लिए विदेशी मुद्रा संकट का इस्तेमाल किया गया. देश अपनी अर्थव्यवस्था को आज भी अनिवार्यत: 1991 के सुधारों के तहत ही चला रहा है.

देश 1991 के सुधारों की ज्यादातर ताकत का इस्तेमाल करने के बाद काफी समय से निचली वृद्धि में अटका है. अगला उछाल अगले ढांचागत सुधारों से आ सकता है और ये हैं सार्वजनिक क्षेत्र का निजीकरण, सरकार का केवल सार्वजनिक और लाभदायक सेवाएं मुहैया करवाने पर ध्यान देना और डिजिटल अर्थव्यवस्था की ताकत को पूरी तरह खोलना.

सामान और सेवा क्षेत्र सहित ज्यादातर कारोबार ज्यादा से ज्यादा डिजिटल हो रहे हैं. देश में स्टार्ट-अप के लिए अनुकूल वातारण को बहुत ज्यादा बढ़ावा देने की जरूरत है.

इसके अलावा, भारत को पर्यावरण से जुड़े सामान और प्रदूषण को संभालने में भारी सरकारी निवेश की दरकार है. उसे डिजिटल अर्थव्यवस्था के माकूल बुनियादी ढांचे का निर्माण करने और उसे प्रोत्साहन देने की भी जरूरत है. सरकार के सामने इन सुधारों को भारत के लिए 2021 का क्षण बनाने का मौका है. 2021-22 के बजट में कुछ ऐलान ऐसे थे जिनसे सरकार के इस संकल्प का इशारा मिलता है कि वह 2021 के इस क्षण को पकड़ रही है. मगर इस एजेंडे को बढ़ाने और रफ्तार को बनाए रखने की जरूरत है.

इसमें दो राय नहीं कि 2021 का यह दौर भारत को निम्न मध्यम आय अर्थव्यवस्था की जकड़बंदियों से आजाद करने और 2035 तक 10 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था के रास्ते पर ले जाने के लिए अंतिम जोर लगाने का मौका दे सकता है.

अदिति नायर: बीते एक साल में हमने सरकार को तमाम मौद्रिक उपायों के साथ-साथ कई किस्म के राजकोषीय कदम उठाते देखा है. 2022 के वित्तीय साल में हम उम्मीद करते हैं कि सरकार मौजूदा टूलकिट से ताकत लेगी.

ऊपर आय और मांग की सहायता के जो रूप बताए गए हैं, उनके अलावा फोकस के अन्य क्षेत्रों में इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम (ईसीएलजीएस) में आगे के जरूरी बदलाव और टीका अभियान के लिए धनराशि बढ़ाना शामिल हैं.

इस पड़ाव पर हल्का-सा जोखिम है कि वित्तीय साल 2022 में सरकार का राजकोषीय घाटा बजट अनुमान (15.1 खरब रुपए) से ज्यादा होगा, खासकर विनिवेश की प्राप्तियों में कमी की वजह से. लिहाजा वित्तीय प्रोत्साहन की गुंजाइश सीमित है और इसलिए असरदार ढंग से लक्ष्य साधना बेहद जरूरी है.

पिनाकी चक्रवर्ती: केंद्र और राज्यों दोनों की ओर से वृद्धि को बढ़ावा देने वाले पूंजीगत खर्चों और रोजी-रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा के लिए बेहद जरूरी मदद में एक तरह का तालमेल होना चाहिए. 2021-22 के बजट में पूंजीगत खर्चों पर जोर दिया गया है.

डी.के. श्रीवास्तव: केंद्र और राज्य सरकारों दोनों को स्वास्थ्य पर खर्चों को प्राथमिकता देनी चाहिए. इसमें वैक्सीन की खरीद को तेज करना, स्वास्थ्य के बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देने के लिए निर्माण कार्य हाथ में लेना और मौजूदा तथा नए अस्पतालों में स्वास्थ्य पेशेवरों को लाना शामिल है. इसके अलावा सरकार को पूंजीगत खर्चों पर ध्यान देकर उस क्षेत्र में खर्च करना चाहिए जिसे 'सार्वजनिक प्रशासन, प्रतिरक्षा और अन्य सेवाएं' कहा जाता है. साफ संकेत दिखाई दे रहे हैं. सीजीए डेटा के मुताबिक, खासकर केंद्र के पूंजीगत खर्च में अप्रैल 2020 के मुकाबले अप्रैल 2021 में 66.5 फीसद का इजाफा हुआ. मनरेगा और ऐसी शहरी योजना के जरिए ग्रामीण और शहरी आमदनियों को सहारा देकर मांग को मजबूती देने की भी जरूरत है. ■

प्र तीसरी लहर की चिंताओं को देखते हुए आप स्वास्थ्य से जुड़े किन उपायों की सलाह देंगे, जिनसे कारोबार-धंधों को सहारा मिले और उपभोक्ताओं का भरोसा कायम हो?

रजनीश कुमार: हमारी बहुत बड़ी आबादी और वायरस की फितरत को देखते हुए जब तक हम तेजी से टीके नहीं लगाते हैं, तीसरी लहर के प्रकोप की काफी आशंका है. जो देश तेजी से और बड़े पैमाने पर अपने लोगों को टीके लगा रहे हैं, वहां संक्रमण का ग्राफ उतरने लगा है. साथ ही, स्वास्थ्य का बुनियादी ढांचा विकसित करने पर जोर देने से भरोसा पैदा होगा.

डी.के. जोशी: और तेजी से टीके लगाएं, स्वास्थ्य के बुनियादी ढांचे को, खासकर ग्रामीण इलाकों में उन्नत बनाएं और उद्योग-धंधों, रोजी-रोजगार तथा घर-परिवारों के लिए वित्तीय सहायता देने के कार्यक्रम शुरू करें.

एस.सी. गर्ग: देश को सार्वजनिक और निजी दोनों तरह की स्वास्थ्य सुविधाओं और बुनियादी ढांचे का विस्तार करना होगा. देश की स्वास्थ्य सेवाओं में सबसे ज्यादा किल्लत डॉक्टरों और पारा-मेडिकल स्टाफ का है. कई संकीर्ण वजहों से मेडिकल एसोसिएशन सहित भारतीय नीति-निर्माताओं ने मेडिकल शिक्षा का विस्तार नहीं होने दिया. देश की जरूरतों को पूरा करने के लिए, और इस क्षेत्र में निर्यात के जबरदस्त अवसरों का फायदा उठाने के लिए भी, देश को डॉक्टर और पारामेडिकल स्टाफ तैयार करने पर जोर देना चाहिए.

चिकित्सा उपकरणों के उत्पादन के लिए पीएलआइ किस्म की योजनाओं के अलावा देश को चाहिए कि देश के हरेक कस्बे में निजी क्लिनिक स्थापित करने के लिए प्रोत्साहन देने का कार्यक्रम प्राथमिकता के आधार पर चलाए.

सरकार ने 2021-22 के बजट में टीकाकरण के लिए 35,000 करोड़ रुपए मुहैया करके अच्छी शुरुआत की. ये 100 करोड़ लोगों को वैक्सीन की दो दो डोज देने के लिए काफी होने चाहिए. मैं समझ नहीं पाता कि ऐसा क्यों है, लेकिन केंद्रीय टीकाकरण कार्यक्रम को खासा हल्का कर दिया गया है. अच्छा होगा कि केंद्र कमर कस ले और देश में केंद्रीय तालमेल के साथ, एक ही जगह खरीदे गए टीकों के साथ एक ही बिंदु से निगरानी में टीकाकरण कार्यक्रम चलाए.

सरकार के लिए सबसे अहम उपाय यह होगा कि वह स्वास्थ्य क्षेत्र के सार्वजनिक बुनियादी ढांचे में नए सिरे से भारी निवेश करे. एम्स का विस्तार सर्वाधिक स्वागतयोग्य है. ज्यादा अहम यह होगा कि जिला अस्पतालों और सार्वजनिक स्वास्थ्य केंद्रों का कायाकल्प करके उन्हें जिलों और कस्बों में चिकित्सा सेवा के सक्रिय और हमेशा तत्पर रहने वाले केंद्रों में बदले. इन सुविधाओं में दस गुना निवेश बढ़ाने की जरूरत है.

"समूचे देश में केंद्रीय पहल में एक तरह की खरीद और निगरानी व्यवस्था में टीकाकरण कार्यक्रम चलाया जाए"
एस.सी. गर्ग

अदिति नायर: युवा वयस्कों के लिए ज्यादा तेजी से टीके लगाने की शुरुआत होनी चाहिए, जो आर्थिक गतिविधि के एक बेहद अहम इंजन की तरह हैं, मौजूदा मोड़ पर भरोसा बढ़ाने वाला प्रमुख उपाय होगा.

इसके अलावा बच्चों को वैक्सीन लगाने की रफ्तार तेज करने और बच्चों के लिए स्वास्थ्य सुविधाएं बढ़ाने पर ध्यान देने से संभावित तीसरी लहर को लेकर पैदा चिंताएं कुछ कम होंगी.

पिनाकी चक्रवर्ती: इसका ज्यादातर वास्ता लोगों के व्यवहार में आने वाले बदलावों से है. कोशिश यह होनी चाहिए कि लोग कोविड की रोकथाम के माकूल व्यवहार करें और टीके लगाने के लिए आगे आएं. हमें सजग रहना होगा और अपने लोगों को यथासंभव तेजी से टीके लगाने होंगे ताकि हमें फिर लॉकडाउन से न गुजरना पड़े.

डी.के. श्रीवास्तव: पहली प्राथमिकता टीकाकरण कार्यक्रम में तेजी लाकर कोविड की तीसरी लहर के असर से बचने या उसे कम करने की होनी चाहिए. शहीर बस्तियों और खासकर घनी बसी आवादी वाली बस्तियों में पूरी तरह टीके लगाने चाहिए. इसमें युवा आबादी (12 साल की उम्र से ऊपर की) शामिल हो. स्वास्थ्य पर बजट में तय पूंजीगत खर्च में अच्छी-खासी बढ़ोतरी करके स्वास्थ्य का अतिरिक्त बुनियादी ढांचा खड़ा करने पर सरकारी खर्च करने से चक्रवृद्धि प्रभाव के जरिए मांग को सहारा मिलेगा. पूरे साल लगातार वित्तीय प्रोत्साहन की गुंजाइश है और कारोबार-धंधों को कम ब्याज दरों पर कर्ज मुहैया करवाया जाए और कुछ हद तक वित्तीय प्रोत्साहन दिया जाए. ■

INDIA TODAY

HIDDEN STORIES SURFACE

ONLY ON GROUND ZERO

Get all sides of the elections

DOWNLOAD THE APP NOW

AVAILABLE ON

देहात में छिपा दानव

ग्रामीण भारत में बेहद अपर्याप्त स्वास्थ्य ढांचे की बात सबको पता है, लेकिन आधिकारिक अनुमान संकट पर पर्दा डालते हैं जिससे महामारी के खिलाफ लड़ाई और मुश्किल हो जाती है

कौशिक डेका और आशीष मिश्र

ओ

झौली उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गृह जिले गोरखपुर से 50 किमी दूर गोला तहसील का एक गुमनाम-सा गांव है. बताया जाता है कि करीब 4,500 की आबादी वाले इस गांव ने बीते महीने कोविड सरीखे लक्षणों के बाद 30 लोगों को मरते देखा. गोला स्थित सबसे नजदीकी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) से उन्हें कोई जवाब नहीं मिला. ओझौली के मूल बांशिदे नीलरंजन ओझा ने 20 मई को गोरखपुर के जिला पंचायती राज अधिकारी हिमांशु ठाकुर की मौत की इत्तेला दी. तब स्वास्थ्य अधिकारियों की एक टीम फौरन गांव आई और आठ लोगों को गोरखपुर के कोविड अस्पताल में भर्ती करवाया गया.

ग्रामीण इलाकों में कोविड के मामलों को लेकर हरकत में आने में महाराष्ट्र के सरकारी अफसर भी इसी तरह ढीले-ढाले और लेत-लतीफ रहे हैं. रोजाना राज्य के करीब 20 फीसद कोविड टेस्ट अकेले मुंबई में किए जा रहे हैं, जिसकी महाराष्ट्र की आबादी में महज 1.5 फीसद हिस्सेदारी है. अहमदनगर, बुलढाणा, सतारा, बीड

अपना इंतजाम खुद
उत्तर प्रदेश के शामली में खेड़ा गडाई गांव में कोविड मरीज होम आइसोलेशन के दौरान ऑक्सीजन सपोर्ट पर

चंद्रदीप कुमार

तथा ऐसे ही कुछ अन्य ग्रामीण जिलों में, जहां पॉजिटिविटी दर 23-30 फीसद है, रोज 5,000 से भी कम टेस्ट किए जा रहे हैं. बीड में मई के दूसरे हफ्ते में विवाद खड़ा हो गया जब जिला प्रशासन कोविड से जुड़ी 240 मौतें राज्य की गिनती में जुड़वाने में नाकाम रहा.

आंकड़े कम बताना भी केवल महाराष्ट्र तक सीमित नहीं है. देश जब दूसरी लहर पर काबू पाने की जद्दोजहद में लगा है, आधे-अधूरे आंकड़ों से हालात और ज्यादा खतरनाक हो जाते हैं. सरकारी आंकड़े बर्बादी का सटीक खाका पेश नहीं करते, जिससे उनका मुकम्मल उपाय भी नहीं हो पाता. दिल्ली के मेडिकल एपिडीमियोलॉजिस्ट डॉ. चंद्रकांत लहरिया कहते हैं, ''ग्रामीण भारत में कोविड की भरोसेमंद निगरानी और आंकड़े नहीं होने के कारण हम महामारी की वास्तविक हद और (तीव्रता) के बारे में पक्का पता नहीं लगा सकते. देश के कुल आंकड़े शहरी इलाकों में फैलाव घटने का इशारा करते हैं, लेकिन (यह मुमकिन है कि वायरस) ग्रामीण भारत में अब भी फैल रहा हो.''

एसबीआइ रिसर्च की 7 मई की एक रिपोर्ट का अनुमान है कि करीब 48.5 फीसद नए मामले अब ग्रामीण जिलों में हैं, जो अप्रैल के 45.5 फीसद और मार्च के 37 फीसद से ज्यादा हैं. लेकिन नए मामलों से ज्यादा ये मौतें ही हैं जो भारत के गांवों में कहर बरपा रही हैं. सितंबर 2020 में भारत में कोविड से हुई 11 फीसद मौतें केंद्र के बैकवर्ड रीजन ग्रांट फंड के तहत रकम हासिल करने वाले 243 जिलों में थीं. अब यह आंकड़ा 16 फीसद है. इनमें ओझौली और बीड सरीखी जगहों के कई मामले तो शामिल ही नहीं हैं क्योंकि ये जगहें नाकाफी मेडिकल इन्फ्रास्टक्चर, टेस्ट करवाने में हिचकिचाहट और प्रशासनिक बेरुखी के कारण रडार से दूर चली गई हैं. मसलन, 1 और 23 मई के बीच महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने राज्य में कोविड के मामलों की समीक्षा के लिए चार बैठकें कीं, लेकिन इनमें से केवल एक 16 मई की बैठक में ग्रामीण इलाकों पर प्राथमिकता से ध्यान दिया गया. ठाकरे ने भी स्थिति का संज्ञान तब लिया जब यह साफ हो गया कि राज्य के करीब 70 फीसद नए मामले 1,00,000 से कम आबादी वाले तालुकाओं में दर्ज किए जा रहे थे.

उसी दिन केंद्र सरकार ने निर्देश दिया कि राज्य प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों (पीएचसी), सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों और उप-जिला अस्पतालों में बिस्तर, ऑक्सीजन, टेस्टिंग किट और एंबुलेंस जैसे संसाधनों की सुलभता बढ़ाएं तथा अस्थायी कोविड देखभाल केंद्र बनाकर ग्रामीण मेडिकल इन्फ्रास्ट्रक्चर में सुधार लाएं. निर्देशों में यह भी कहा गया कि सभी पीएचसी, उप-केंद्रों (एससी) और स्वास्थ्य तथा आरोग्य केंद्रों पर रैपिड ऐंटीजन टेस्ट (आरएटी) किट मुहैया करवाई जाएं, सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारियों और सहायक नर्स दाई (एएनएम) को रैपिड ऐंटीजन टेस्ट करने का प्रशिक्षण दिया जाए और मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं (आशा) को गांवों में सक्रिय निगरानी का काम सौंपा जाए.

राज्यों की तैयारी

ज्यादातर राज्यों ने निर्देशों के मुताबिक कदम उठाना शुरू कर दिया है. कुछ तो निर्देश मिलने से पहले ही ऐसा कर रहे थे. पर यह बहुत भारी-भरकम काम है. महामारी का गैर मामूली काम आने से पहले भी ग्रामीण भारत की स्वास्थ्य सेवाएं दयनीय बुनियादी ढांचे, मानवबल की कमी और नीतिगत उपेक्षा से कृशकाय थीं. देहात में स्वास्थ्य सेवाओं की चरमराती रीढ़ का निर्माण करने वाले एससी, पीएचसी और सीएचसी की जबरदस्त कमी है. केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक, देश में एससी 23 फीसद, पीएचसी 28 फीसद और सीएचसी 37 फीसद कम हैं. पिछले साल जारी ग्रामीण स्वास्थ्य सांख्यिकी रिपोर्ट बताती है कि औसतन हरेक एससी चार गांवों, हरेक पीएचसी 27 गांवों और हरेक सीएचसी 128 गांवों की सेवा करता है. दूसरे ढंग से कहें तो सीएचसी करीब मुंबई के आकार के 596 वर्ग किलोमीटर इलाके के लिए जिम्मेदार हैं.

यहां तक कि जब नए कोविड-समर्थ बुनियादी ढांचे की बात आती है, तब भी स्थिति शहरी इलाकों के हक में बहुत ज्यादा झुकी हुई है. मसलन, मध्य प्रदेश में कोविड के इलाज के लिए 819 चिकित्सा सुविधाएं स्थापित की गईं. इनमें से महज 69 ग्रामीण इलाकों में हैं. केवल 14 फीसद आइसोलेशन बिस्तर, एक फीसद ऑक्सीजन बिस्तर और 0.54 फीसद

आइसीयू ग्रामीण इलाकों में हैं.

स्वास्थ्य कर्मियों के मामले में भी स्थिति कमोबेश यही है. हालांकि बीते 15 सालों में देश भर के पीएचसी में एलोपैथिक डॉक्टरों की संख्या 40 फीसद बढ़ी है, लेकिन अब भी सात फीसद कम है. ज्यादा अहम यह कि सीएचसी में 76.1 फीसद विशेषज्ञ डॉक्टर कम हैं. जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में स्कूल ऑफ सोशल साइंसेज के सामाजिक चिकित्सा और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की प्रोफेसर संघमित्रा शील आचार्य कहती हैं, ''पीएचसी और एससी का सबसे बड़ा नेटवर्क शायद भारत में है. लेकिन इनमें कर्मचारियों और खासकर जमीनी कार्यकर्ताओं की सख्त दरकार है क्योंकि ये ही पहले संपर्क (का बिंदु) हैं.''

इसके चलते उन्नत बुनियादी ढांचा भी पंगु हो जाता है. मसलन, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देशों के मुताबिक, हर जिले में चार सीएचसी 50 बिस्तरों, एक ऑक्सीजन कंसेंट्रेटर और डॉक्टरों की एक टीम वाले समर्पित कोविड अस्पतालों में बदले जाने हैं. ऐसा ही एक शंभूनाथ सीएचसी आगरा से 70 किमी दूर बाह में है. इसमें 10 ऑक्सीजन बिस्तर तो हैं पर ऑक्सीजन की सप्लाइ संभालने के लिए प्रशिक्षित कर्मी नहीं हैं. यहां डॉक्टरों के 21 स्वीकृत पद हैं, पर केवल तीन ही पदस्थ हैं. यहां डिजिटल एक्स-रे मशीन है, पर रेडियोलॉजिस्ट नहीं है और पैथोलॉजिस्ट न होने से पैथोलॉजी यूनिट बंद पड़ी है. नतीजा यह कि कोविड मरीजों को यहां भर्ती ही नहीं किया जा रहा है. कमी से निपटने के लिए राज्य सरकार सेवानिवृत्त मेडिकल स्टाफ को तैनात करने पर विचार कर रही है. मुख्यमंत्री ने डॉक्टरों, नर्सों, पैरामेडिकल स्टाफ और चौथी श्रेणी के कर्मचारियों को कोविड ड्यूटी के लिए बेसिक वेतन पर 25 फीसद अतिरिक्त प्रोत्साहन देने का ऐलान किया. जरूरत के आधार पर मेडिकल इंटर्न, एमएससी नर्सिंग के छात्र, बीएससी नर्सिंग के छात्र, एमबीबीएस अंतिम वर्ष के छात्र और फार्मा छात्रों को भी दैनिक मानदेय पर पदस्थ किया जाएगा. पड़ोसी हरियाणा में भी मानवबल बढ़ाने के लिए रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर (आरएमपी) और दूसरे साल से ऊपर के मेडिकल छात्रों को लाया गया है.

अलबत्ता मानवबल बढ़ाना आसान नहीं है, जैसा कि पश्चिम बंगाल में देखा गया. राज्य सरकार ने हालांकि जिला मजिस्ट्रेटों और चीफ मेडिकल तथा स्वास्थ्य अधिकारियों को मेडिकल स्टाफ की भर्ती का पूरा अधिकार दिया है, पर कम मेहनताने की वजह से यह मुहिम लड़खड़ा गई. एसोसिएशन ऑफ हेल्थ सर्विस डॉक्टर्स के सेक्रेटरी डॉ. मानस गुमटा कहते हैं, ''निजी अस्पताल डॉक्टरों को 500 रुपए प्रति घंटा अदा करते हैं, वहीं सरकार 40,000 रुपए मासिक तनख्वाह देती है. अगर हम 50 डॉक्टरों की भर्ती करना चाहें, तो हमें केवल 25 आवेदन मिलते हैं.'' बिहार में भी यही हालत है. राज्य सरकार ने सितंबर 2020 में जनरल ड्यूटी मेडिकल ऑफिसर के तौर पर 3,186 डॉक्टरों की नियुक्ति की और अगस्त 2020 में 929 विशेषज्ञ डॉक्टर भी बढ़ाए. तिस पर भी विशेषज्ञ डॉक्टरों के 4,149 पद और 3,206 सामान्य पद खाली हैं. लैब तकनीशियनों की भी भारी कमी है (हालांकि स्वास्थ्य विभाग ने पिछले साल एएनएम को कोविड-19 के टेस्ट के लिए प्रशिक्षित करने का गैरपारंपरिक कदम उठाया था.)

राज्य सरकारों ने ग्रामीण इलाकों में निगरानी बढ़ाने के लिए भी कदम उठाए हैं, ताकि वहां शहरी इलाकों सरीखी स्थिति दोहराई न जाए जहां कोविड के तेजी से बढ़ते मामलों तले मेडिकल इन्फ्रास्ट्रक्चर चरमरा गया था. गरीबी और सामाजिक सुरक्षा विशेषज्ञ डॉ. भवानी आर.वी. कहती हैं, ''हमारे कृशकाय ग्रामीण बुनियादी ढांचे में उस किस्म का भार उठाने की क्षमता नहीं है जो हमने कोविड की लहर में शहरी इलाकों में देखा.'' तकरीबन सभी राज्यों ने निगरानी और टेस्टिंग बढ़ाने के लिए एएनएम,

ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ता खतरा

ग्रामीण भारत में मामलों और मौतों की सही संख्या न पता चलने के बावजूद आधिकारिक आंकड़ों में पिछले तीन महीनों के दौरान कोविड के केसों में 12 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज हुई है

181 जिले, ऐसे 254 जिलों में से जिनमें (24 से 30 मई) 10 प्रतिशत से ज्यादा पॉजिटिविटी दर थी, ग्रामीण आबादी बहुल हैं

केवल **136** जिलों में, जो कि इन 254 में शामिल हैं, 50 प्रतिशत आरटी-पीसीआर टेस्ट हुए हैं

19% टेस्ट पॉजिटिविटी दर

1.6% मामलों में मृत्यु दर

रही है चार उत्तर पूर्वी राज्यों-मणिपुर, मेघालय, नगालैंड और सिक्किम में जहां औसतन 65 प्रतिशत ग्रामीण आबादी रहती है

रेबेका कोनवे/गेट्टी इमेजेज

जान पर आफत
राजस्थान में सीकर जिले के जाजोड़ की सीएचसी में एक मरीज और उनकी तीमारदार

सर्वाधिक संक्रमण वाले 5 बड़े राज्य

हालांकि बुरी तरह प्रभावित इलाकों में शुमार दक्षिणी राज्य ग्रामीण बेड के मामले में बेहतर हैं

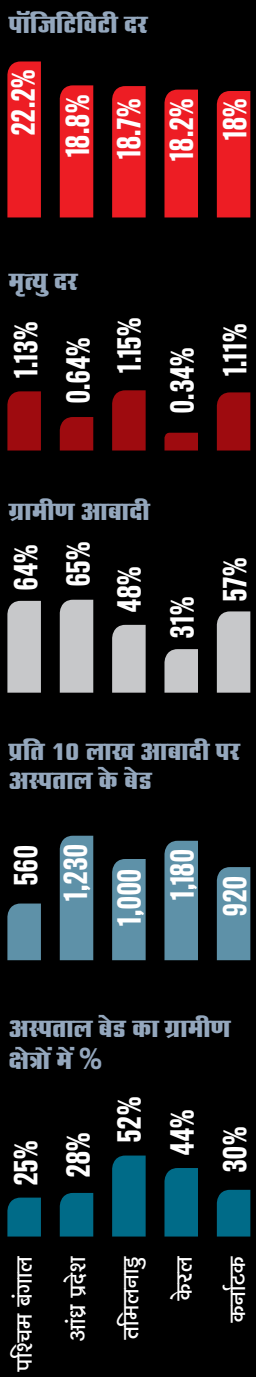

सर्वाधिक मृत्यु दर वाले 5 बड़े राज्य

ग्रामीण पंजाब में मृत्यु दर सबसे ज्यादा चिंताजनक है हालांकि यहां पॉजिटिविटी दर सबसे खराब नहीं है

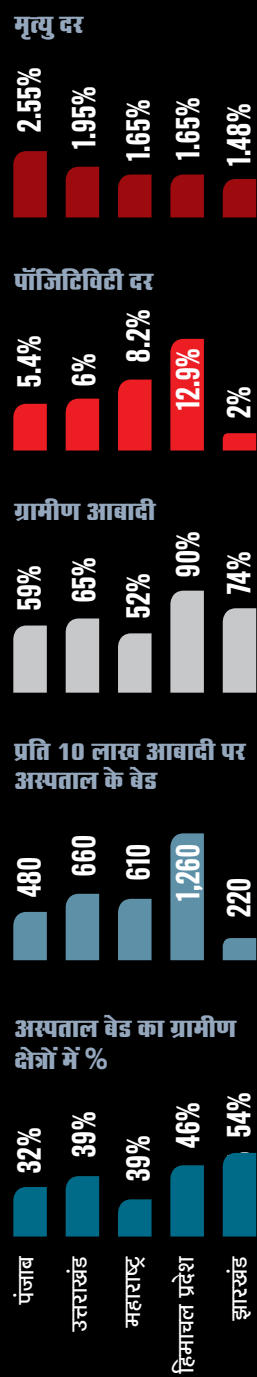

पॉजिटिविटी दर और मृत्यु दर 24 मई से 30 मई के सात दिनों का औसत है; स्रोत : परिवार और स्वास्थ्य कल्याण मंत्रालय; ग्रामीण स्वास्थ्य सांख्यिकी, 2019-20 ; हाऊ इंडिया लिव्स

आशा और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को लाया गया है. कुछ राज्यों ने तो ग्रामीण इलाकों में मोबाइल टेस्टिंग इकाइयां भी शुरू की हैं.

उत्तराखंड के ग्रामीण इलाकों में भी कोविड पैर फैला चुका है. पौड़ी और अल्मोड़ा जिलों में पॉजिटिविटी दस प्रतिशत से ऊपर चल रही है. पिथौरागढ़, चमोली जैसे दूरदराज के जिलों में भी कोरोना के मरीज निकल रहे हैं. मैदानी गांवों में कुछेक स्थानों पर टेस्टिंग की सुविधाएं हैं लेकिन पहाड़ी गांवों में स्वास्थ्य सुविधाएं तो दूर मामूली दवाएं लेने के लिए भी काफी मेहनत करनी पड़ती है. देहरादून, नैनीताल जैसे मैदानी जिलों में टेस्टिंग और इलाज की सुविधाएं काफी हद तक हैं.

नदारद आंकड़े

फिर भी मामले नजर से छूट रहे हैं, खासकर इसलिए भी कि ग्रामीण जांच-पड़ताल आरएटी टेस्ट पर बहुत ज्यादा निर्भर है. टेस्ट के नतीजे आसानी से नहीं मिलने के कारण भी मुश्किल बढ़ जाती है. सेंटर फॉर हेल्थ ऐंड सोशल जस्टिस की एक इकाई सहर की डायरेक्टर संध्या गौतम कहती हैं, ''अगर किसी का (टेस्ट) हुआ है, तो उसे टेस्ट रिपोर्ट सुलभ होनी चाहिए.'' विशेषज्ञ इलाज के जरूरतमंद लोगों की पहचान के लिए टेस्ट के नतीजों पर बहुत ज्यादा निर्भरता के विरुद्ध भी आगाह करते हैं. पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट प्रोफेसर के. श्रीनाथ रेड्डी कहते हैं, ''चूंकि टेस्ट व्यापक रूप से मौजूद नहीं हैं और झूठे नेगेटिव (भी दे सकते हैं), लिहाजा, आइसोलेशन और इलाज का फैसला करते वक्त व्यक्ति के संपर्क में आने के इतिहास और नैदानिक लक्षणों का ध्यान रखने की भी जरूरत है.'' अनुकरण के मॉडल के तौर पर वे करनाल जिले में चल रही हरियाणा सरकार की संजीवनी योजना का जिक्र करते हैं. इसमें सहायता और निगरानी से लैस होम केयर का समग्र बहुघटकीय कार्यक्रम है और जरूरत पड़ने पर उन्नत देखभाल सुविधाओं तक जाने के लिए निश्चित आपातकालीन ट्रांसपोर्ट भी मुहैया किया जाता है.

जहां तक बात होम आइसोलेशन में मामलों की निगरानी की है, गुजरात और महाराष्ट्र सहित कई राज्यों का प्रदर्शन इसको लेकर बहुत खराब रहा है. फोन कॉल के माध्यम से पूछताछ करने के अलावा, संक्रमण की निगरानी के लिए या यहां तक कि यह सुनिश्चित करने के लिए भी कोई व्यवस्था नहीं है कि रोगियों की ओर से आइसोलेन (पृथकवास) के नियमों का कड़ाई से पालन किया जा रहा है या नहीं. इस खामी को दूर करने के लिए, बिहार सरकार ने होम आइसोलेशन में संक्रमित रोगियों की ऑनलाइन निगरानी के लिए एक ऐप्लिकेशन लॉन्च किया है जिसका इस्तेमाल एएनएम और आशा कार्यकर्ता करती हैं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार सरकार से केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के साथ ऐप का विवरण साझा करने का अनुरोध किया है ताकि इसे पूरे देश में अपनाया जा सके.

सरकार के प्रयासों को ग्रामीण आबादी के प्रतिरोध का सामना भी करना पड़ रहा है, इसकी मुख्य वजह कोविड के बारे में जागरूकता की कमी और अफवाहों का प्रसार है. अगर कोई व्यक्ति जांच में कोरोना संक्रमित पाया जाता है तो उसे सामाजिक कलंक और जबरन अलगाव का डर होता है और बहुत से लोग तो इस डर से रोग के लक्षणों की जानकारी भी नहीं देते कि कहीं उन्हें जबरन अस्पताल में भर्ती न करा दिया जाए. अस्पतालों से आने वाली डरावनी कहानियों—बिस्तरों और ऑक्सीजन की कमी और अस्पतालों के बहुत खराब रखरखाव की विचलित करने वाली तस्वीरों और मौतों की खबरें—ने इन आशंकाओं को और बढ़ा दिया है. कलकत्ता स्कूल ऑफ ट्रॉपिकल मेडिसिन के पूर्व निदेशक डॉ. पी.के. कुंडू कहते हैं, ''लोग जांच कराने या अस्पताल जाने से घबरा रहे हैं. वे क्वारंटीन किए जाने से डरते हैं. विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य केंद्रों और चिकित्सा संस्थानों पर लोगों का भरोसा बहुत कम है और यह एक बड़ा मुद्दा है.'' पश्चिम बंगाल के पश्चिम मिदनापुर जिले के केशियारी ब्लॉक की हीरामनी मंडी जैसी आशा कार्यकर्ताओं का कहना है कि इस

किस तरह राज्य कर रहे हैं मुकाबला

हालांकि पूरे भारत में कोविड संक्रमण में गिरावट दिख रही है और राज्य इसे फैलने से रोकने के लिए ग्रामीण इलाकों पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं. लेकिन गांवों में कमजोर स्वास्थ्य ढांचे के कारण यह काम बहुत चुनौतीपूर्ण हो गया है

रोज के केस
रोज की मौतें

राजस्थान

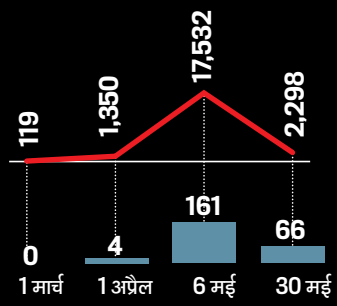

- 16 मई के बाद 30 बिस्तर, 2 ऑक्सीजन सिलिंडर और 1 एंबुलेंस वाले 70 सीसीसी खोले गए; 257 कोविड कंसल्टेशन सेंटर खोले जा रहे हैं; 355 सीएचसी को सीसीसी में बदला जा रहा है
- अगले दो महीनों में ग्रामीण इलाकों में 20,000 ऑक्सीजन बेड मुहैया कराने का लक्ष्य; 30,000 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर का ऑर्डर दिया
- गांवों में 7,353 सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी तैनात होंगे

हरियाणा

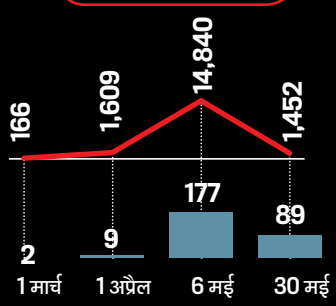

- राज्य के ग्रामीण इलाकों में आशा, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, स्वास्थ्य सेवा देने वालों और पंचायत अधिकारियों की 8,000 टीमें तैनात की हैं जिनमें से प्रत्येक पर 5,000 घरों की स्क्रीनिंग की जिम्मेदारी

महाराष्ट्र

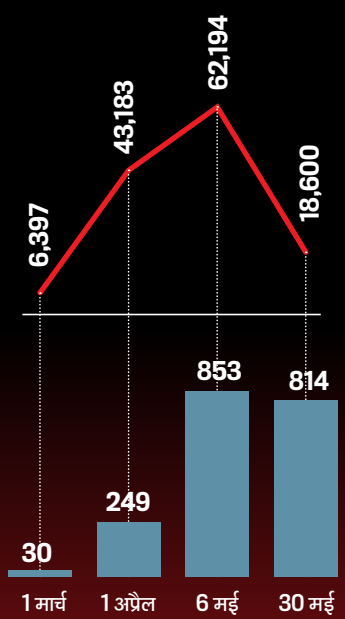

- 400 कोविड केयर सेंटर (सीसीसी) जिनमें से प्रत्येक में 30 बिस्तर, 2 ऑक्सीजन सिलिंडर ओर एक एंबुलेस की सुविधा
- प्रत्येक सीसीसी में एक एमबीबीएस डॉक्टर, एक बीडीएस/बीएएमएस (दंत चिकित्सक और आयुर्वेदिक डॉक्टर) और दो नर्सों का प्रवाधान
- राज्य ने 16 मई के केंद्र सरकार के निर्देश न मानते हुए मौजूदा ढांचे पर ही भरोसा किया

ज्यादा कोविड केस वाले जिले

295 जिलों में 24 मई से 30 मई 2021 के बीच प्रति दिन 100 से ज्यादा मामले आए

इलस्ट्रेशन: नीलांजन दास

उत्तर प्रदेश

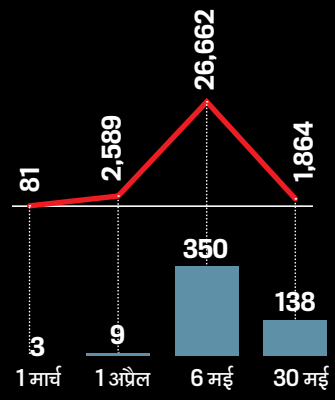

- 75 जिलों में 300 सीएचसी को सीसीसी में बदला जा रहा है
- ग्रामीण जिलों के 4 सीएचसी को एल-1 सीसीसी में बदला जा रहा है. बिस्तरों की संख्या 30 से बढ़ाकर 50 जिनमें 10 बच्चों के लिए आरक्षित
- गांवों के एल-1 सीसीसी में मई के अंत तक 8,000 ऑक्सीजन बेड थे; इनके जून तक 15,000 होने का अनुमान
- एल-1 सीसीसी के लिए 17,000 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर खरीदे जा रहे हैं जो जून में लगा दिए जाएंगे
- ग्रामीण क्षेत्रों में 100 से ज्यादा एल-1 सीसीसी में ऑक्सीजन उत्पादन प्लांट लगाए जाएंगे
- हर ग्रामीण सीसीसी में कम से कम सात डॉक्टर, छह नर्स और चार फार्मासिस्ट तैनात होंगे

मध्य प्रदेश

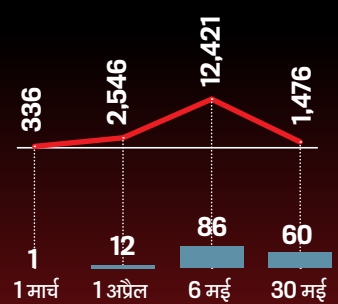

- राज्य में 355 सीसीसी लेकिन सभी शहरी इलाकों में स्थित हैं
- कोविड का इलाज 819 चिकित्सा प्रतिष्ठानों में हो रहा है पर इनमें से केवल 69 ही ग्रामीण क्षेत्रों में हैं

पंजाब

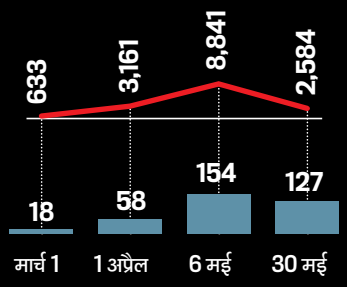

- मिशन फतेह 2.0 शुरू किया ताकि ग्रामीण इलाकों में जांच क्षमता बढ़ाने के साथ ग्रामीण स्वास्थ्य ढांचा और कार्यबल तैयार किया जा सके
- ग्रामीण इलाकों में प्रावधान लागू करने के लिए पंचायत अधिकारियों, आशा और आंगनवाड़ी वर्करों के साथ 13,000 पूर्व सैनिकों को निगरानी के लिए जोड़ा

बिहार

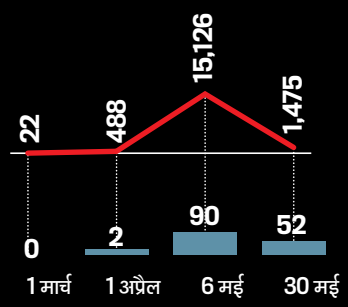

- 165 सीसीसी जिनमें 11,382 बिस्तर, 3,359 ऑक्सीजन बेड
- सब डिविजन स्तर पर 7,871 बिस्तर वाले 110 डेडिकेटेड कोविड हेल्थ सेंटर (डीसीएचसी), जिनमें से 5,158 ऑक्सीजन बेड, 90 आइसीयू, 81 वेंटिलेटर और 600 बाइपेप मशीन बेड
- प्रत्येक सीसीसी और डीसीएचसी में कम से कम 30 बिस्तर, दो ऑक्सीजन सिलिंडर और दो एंबुलेंस
- प्रत्येक सीसीसी के लिए एक एमबीबीएस डॉक्टर, एक बीडीएस/बीएएमएस, दो नर्स और दो पैरामेडिक्स का प्रावधान

आंध्र प्रदेश

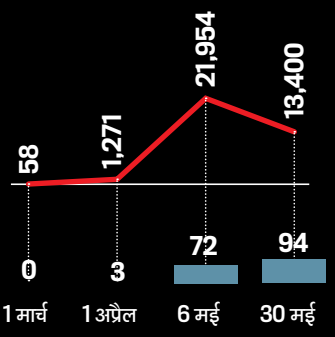

- 15,870 बिस्तर वाले 64 सीसीसी ग्रामीण आबादी के लिए जिसकी आबादी में हिस्सेदारी 66 प्रतिशत है
- प्रत्येक सेंटर के लिए पांच ऑक्सीजन कंसंट्रेटर/सिलिंडर
- राज्य व जिला स्तर पर नोडल अफसर की तैनाती के साथ सरकार-एनजीओ समन्वय केंद्र खोले जाएंगे

पश्चिम बंगाल

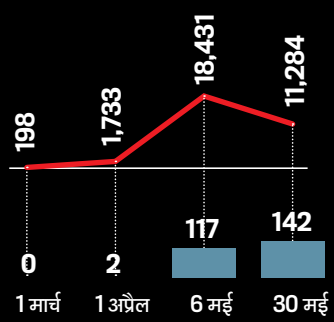

- 1,356 ग्रामीण स्वास्थ्य केंद्रों और पीएचसी में 5 से 10 बेड हैं पर ऑक्सीजन या वेंटिलेटर नहीं
- 345 ब्लॉक सीएचसी हैं और प्रत्येक पर 1,00,000 से 3,00,000 लोगों की सेवा का दायित्व
- सीएचसी में बेड की संख्या 30 से बढ़कर 60 की गई

सीसीसी: कोविड केयर सेंटर (न्यूनतम आवश्यकता: 30 बिस्तर, पांच लीटर के दो ऑक्सीजन सिलिंडर, एक बेसिक लाइफ सपोर्ट एंबुलेंस)

डीसीएचसी : डेडिकेटेड कोविड हेल्थ सेंटर (न्यूनतम आवश्यकता: 30 बेड, प्रति बिस्तर एक ऑक्सीजन का माध्यम, पांच सेल्फ इनफ्लेटिंग रिससिटेशन बैग, एक एक्स-रे यूनिट, खून और बायोकेमिस्ट्री टेस्ट की सुविधा और एक बेसिक लाइफ सपोर्ट एंबुलेंस)

पीएचसी: प्राइमरी हेल्थ सेंटर,
सीएचसी: कम्युनिटी हेल्थ सेंटर,
एससी: सब सेंटर

खतरे का खाका

सर्वाधिक ग्रामीण आबादी वाले 10 राज्यों में बिहार का प्रति किलोमीटर जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है जो आंशिक रूप से स्पष्ट करता है कि एससी व सीएचसी के प्रावधान में राज्य की स्थिति खराब क्यों है. घनत्व कम हो के कारण हिमाचल प्रदेश जैसे अन्य राज्य आगे हैं

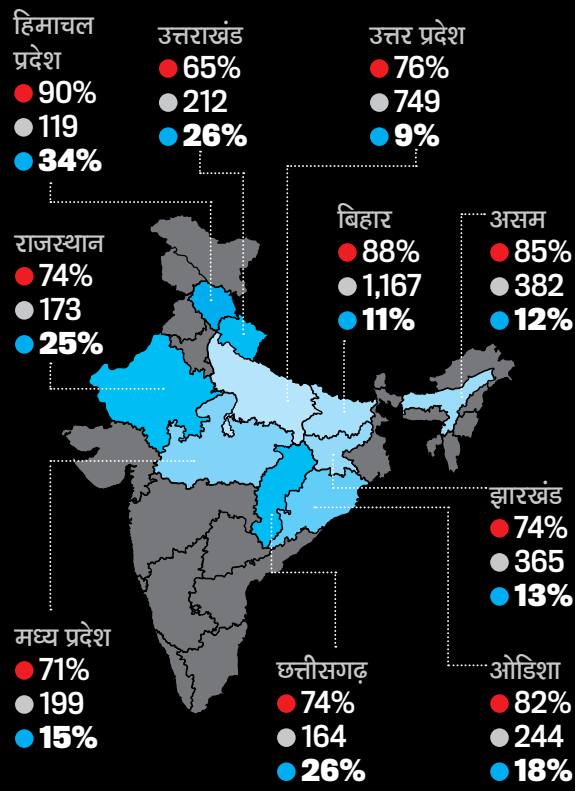

राज्य	एससी की कमी	पीएचसी की कमी	सीएचसी की कमी	ग्रामीण अस्पतालों में बेड का %
हिमाचल प्रदेश	सरप्लस	सरप्लस	सरप्लस	46%
बिहार	58%	51%	94%	47%
असम	28%	10%	27%	64%
ओडिशा	23%	8%	सरप्लस	34%
उत्तर प्रदेश	41%	51%	51%	51%
झारखंड	44%	73%	37%	54%
राजस्थान	सरप्लस	सरप्लस	सरप्लस	27%
छत्तीसगढ़	3%	7%	20%	54%
मध्य प्रदेश	28%	47%	45%	32%
उत्तराखंड	सरप्लस	सरप्लस	सरप्लस	39%

● %ग्रामीण जनसंख्या ● ग्रामीण जनसंख्या घनत्व (प्रति वर्ग किलोमीटर) ● % उस योग्य आबादी (18+) का जो एक टीका लगवाने लायक है

भरोसे की कमी ने उन्हें लोगों को अपनी जांच कराने के लिए राजी करने में असमर्थ बना दिया है.

संस्थागत मदद लेने की अनिच्छा के कारण गांवों में मृत्यु दर भी अधिक है. जैसे, पंजाब में ग्रामीण क्षेत्रों में मृत्यु दर 2.3 प्रतिशत है जबकि शहरी क्षेत्रों में यह 0.7 प्रतिशत है. राज्य सरकार के अधिकारियों का कहना है कि ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग 83 प्रतिशत मरीज अस्पतालों का रुख तभी करते हैं जब बीमारी बढ़ जाती (एडवांस स्टेज) है, जिससे मृत्यु दर बढ़ जाती है.

डर और अविश्वास भी ग्रामीण क्षेत्रों में मामलों और मौतों की कम रिपोर्टिंग को बढ़ावा दे रहा है. जहां शहरी क्षेत्रों में मौतों की पुष्टि करने के कई तरीके हैं—जैसे, श्मशान घाटों और कब्रिस्तानों के रिकॉर्ड के आंकड़ों से सही संख्या आंकी जा सकती है—ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसा कोई विकल्प नहीं है.

गांवों में अविश्वास

सरकारी अधिकारी कोविड से मरने वालों के परिवारों को जबरन क्वारंटीन कर सकते हैं, इस डर से भी ग्रामीण दाह संस्कार से पहले कोविड के संदिग्ध मामलों की रिपोर्ट नहीं देते हैं. कम रिपोर्टिंग के आरोपों के बीच राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य में हुई मौतों के ऑडिट के आदेश दिए हैं. उन्होंने जिला प्रशासन से कहा है कि कोविड के मृत मरीजों के शवों के परिवहन और दाह संस्कार के लिए भुगतान करें. कई विशेषज्ञ कोविड-19 से लड़ने के लिए सरकारी पहल में, ग्रामीण नागरिकों को सक्रिय रूप से भागीदार बनाने के लिए अधिक जागरूकता और भरोसा पैदा करने की जरूरत पर जोर देते हैं.

गौतम कहते हैं कि सूचनाओं के प्रसार और लोगों को संस्थागत मदद लेने के लिए प्रोत्साहित करने में पंचायतों को सक्रिय भूमिका निभानी होगी जैसा कि हिमाचल प्रदेश जैसे राज्यों में देखा जाता है. प्रो. रेड्डी कहते हैं, ''कम संसाधनों वाले क्षेत्रों में महामारी का प्रभावी ढंग से मुकाबला करने के लिए एक पूरे समाज की सह-भागीदारी के दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है. सामुदायिक जुड़ाव महत्वपूर्ण है. स्थानीय निकाय, महिला स्वयं सहायता समूह और युवा वॉलंटियर्स इसके प्रमुख संसाधन हैं. यह तीसरी लहर के लिए प्रभावी और उचित बहु-क्षेत्रीय प्रतिक्रिया के लिए क्षमता निर्माण में भी मदद करेगा.''

हालांकि, इस तरह के मॉडल के लिए सरकारी मशीनरी की आवश्यकता होती है जो वायरस के प्रसार को रोकने के लिए त्वरित प्रतिक्रिया देती है. ग्रामीण इलाकों में प्रसार को रोकने के लिए राज्यों को दिशानिर्देश जारी करने में केंद्र ने जितना समय लगाया, उससे देश में दूसरी लहर शुरू होने के छह सप्ताह बाद भी जमीन पर स्थिति उत्साहजनक नहीं है. जैसा कि डॉ. लहरिया कहते हैं, इससे थाह लगाई जा सकती है कि महामारी पर प्रतिक्रिया देने में भारत दरअसल कहां खड़ा है. तैयारियां अपर्याप्त और उपाय बहुत धीमे हैं.

—साथ में रोमिता दत्ता, अमिताभ श्रीवास्तव, राहुल नरोन्हा, किरण डी. तारे, रोहित परिहार और **अखिलेश पांडे**

एएनआइ

कौशिक रॉय

खड़े-खड़े चित
(बाएं) सुशील कुमार 23 मई को दिल्ली में दिल्ली पुलिस के हाथों गिरफ्तार होने के बाद; सोनीपत में 2012 में भारतीय खेल प्राधिकरण के केंद्र पर प्रशिक्षण के दौरान

खास रपट **अपराध**

दंगल में भला कौन सुशील

हत्या के मामले में एक ओलंपिक पदक विजेता की गिरफ्तारी ने भारतीय कुश्ती की ग्लैमरस दुनिया की कठोर वास्तविकताओं पर से परदा उठाया

सुहानी सिंह और अनिलेश एस.महाजन

हरियाणा की फोगाट बहनों और उनके दबंग पिता-कोच महावीर के जीवन पर आधारित 2016 की फिल्म *दंगल* के साथ बॉलीवुड ने लोगों को कुश्ती से प्यार करना सिखाया. लेकिन बड़े पर्दे पर फिल्माने के लिहाज से एक प्रेरक, शून्य से शिखर तक पहुंचने की माकूल कहानी तो सुशील कुमार के पास थी. एक बस ड्राइवर का बेटा सुशील एकमात्र भारतीय एथलीट है, जो ओलंपिक में व्यक्तिगत स्पर्धा में दो पदक—2008 में कांस्य और 2012 में रजत—जीता और विश्व चैंपियनशिप का खिताब जीतने वाला एकमात्र भारतीय पहलवान है. उसके पास एशियाई खेलों में कांस्य, चार एशियाई चैंपियनशिप पदक और तीन राष्ट्रमंडल खेलों के स्वर्ण पदक भी हैं.

इधर, एक अरसे के बाद सुशील टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालीफाइ करके वापसी की उम्मीद कर रहा था, जो कोविड-19 महामारी के कारण साल भर के लिए टाल दिए गए थे. 23 वर्षीय पहलवान और पूर्व जूनियर राष्ट्रीय चैंपियन सागर धनखड़ की हत्या के आरोप में देश के सबसे चर्चित पहलवान के जेल पहुंचने के बाद उन योजनाओं पर पानी फिर गया है.

हत्या के मामले ने न सिर्फ अंतरराष्ट्रीय ख्यातिप्राप्त पहलवान रहे सुशील कुमार की प्रतिष्ठा को तार-तार कर दिया है बल्कि इस घटना ने

पहलवानों और अपराधी गिरोहों के बीच चली आ रही सांठगांठ पर से भी परदा उठा दिया है

दिल्ली पुलिस ने आरोप लगाया है कि 4 मई को दिल्ली के छत्रसाल स्टेडियम की पार्किंग में धनखड़ और दो अन्य के साथ मारपीट करने वाले गिरोह की अगुआई सुशील ने की थी. इस विवाद ने दो खिलाड़ियों के खेल करियर समाप्त कर दिए.

यह मामला न सिर्फ इसलिए चौंकाने वाला है क्योंकि इसमें कथित तौर पर खेल का एक नायक शामिल है, बल्कि इसलिए कि यह पहलवानों और दिल्ली के आपराधिक गिरोहों के बीच गठजोड़ को उजागर करता है. धनखड़ के सहयोगियों में से एक और सुशील तथा उसके गुर्गों के हाथों पिटने का दावा करने वाला सोनू महाल कुख्यात गैंगस्टर काला जठेड़ी का भतीजा है, जिसके खिलाफ राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली में आपराधिक मामले दर्ज हैं.

संदिग्ध कड़ियां

फरार सुशील को 23 मई को दिल्ली में गिरफ्तार किया गया था. 4 मई की रात की घटना में उसे मदद करने वाले दिल्ली और आसपास के इलाकों के काला असौदा और नीरज बवाना गिरोह के गुर्गे बताए जाते हैं. दिल्ली पुलिस ने नौ लोगों को गिरफ्तार किया है. यह झगड़ा एक संपत्ति विवाद को लेकर शुरू हुआ, ऐसा अंदेशा है. उसी में सुशील ने गुर्गों से धनखड़ को दिल्ली के मॉडल टाउन के एक घर से उठाने और स्टेडियम लाने को कहा था. पुलिस के मुताबिक, फिर सुशील ने अपने गुर्गों से उन्हें कूटने को कहा, ताकि धनखड़ और उनके साथियों को सबक सिखाया जा सके.

14 साल की उम्र में प्रशिक्षण के लिए अकादमी में आने के बाद से छत्रसाल स्टेडियम ही एक मायने में सुशील का घर रहा. 2015 तक स्टेडियम चलाने वाले पूर्व पहलवान से कोच बने सतपाल सिंह की सेवानिवृत्ति के बाद उत्तर रेलवे ने सुशील को विशेष कार्य अधिकारी के रूप में नियुक्त किया, ताकि सतपाल की जगह भरते हुए उसे उभरते पहलवानों के लिए कोच बनाया जा सके. बताते हैं, सुशील ने स्टेडियम अपनी जागीर की तरह चलाया. यहां बाकी शिष्यों के साथ धनखड़ भी उसे आदर देते थे, जो उसी से प्रेरित होकर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सफल होने को स्टेडियम आए थे.

नाम न छापने की शर्त पर कुछ पुलिस अफसर बताते हैं कि सुशील के पहले जठेड़ी गिरोह से ताल्लुकात थे. हरियाणा पुलिस के साथ एक मुठभेड़ के बाद जठेड़ी की फरारी के दौरान सुशील उसके प्रतिद्वंद्वी असौदा और बवाना से जा मिला. पुलिस अफसरों का शक है कि दिल्ली पुलिस के एक हेड कांस्टेबल के बेटे धनखड़ का खुद जठेड़ी गिरोह से ताल्लुक था. दिल्ली पुलिस के प्रवक्ता, डीसीपी (मुख्यालय) चिन्मय बिस्वाल का कहना है कि किसी भी धारणा को सच मान लेना जल्दबाजी होगी. उन्होंने कहा, ''हम सभी कोणों से जांच कर रहे हैं.''

दिल्ली पुलिस की जांच जारी है लेकिन सुशील की इज्जत को तो पलीता लग गया. निशानेबाज अभिनव बिंद्रा ने 2008 बीजिंग ओलंपिक में व्यक्तिगत श्रेणी में भारत का पहला स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रचा था, लेकिन सुशील की उपलब्धि भी कम न थी. 56 साल बाद भारत ने पहला कुश्ती पदक जीता था. दिल्ली के उपनगर नजफगढ़ के एक गांव बापरोला में जन्मे सुशील कुमार ने पिता दीवान सिंह को एक शौकिया पहलवान के रूप में अभ्यास करते देख कुश्ती के मैदान में कदम रखा था. दीवान सिंह ने अपना सब कुछ बेटे पर खर्च कर दिया और उसे सतपाल के अधीन प्रशिक्षण के लिए छत्रसाल स्टेडियम भेजा.

मेहनत से मिली सफलता

एक शर्मीले और समर्पित शिष्य सुशील की दुनिया कुश्ती के इर्द-गिर्द घूमती थी. स्टेडियम के साथी पहलवान याद करते हैं कि सुशील ने छुट्टियों और त्योहारों पर भी प्रशिक्षण से अवकाश नहीं लिया. उसके समर्पण ने कोच सतपाल और उनके सहयोगी रामफल मान का ध्यान खींचा. सुशील ने 2011 में सतपाल की बेटी सावी से उन दिनों राज्यसभा में विपक्ष के नेता दिवंगत अरुण जेटली के दिल्ली आवास पर शादी की. मान कहते हैं, ''यह एक गुरु से अपने शिष्य को एक अनूठा पुरस्कार है.''

मैट पर सुशील की वीरता ने उसे पहचान और दौलत दिलाई. उसे सरकार की ओर से 6 करोड़ रुपए से अधिक का नकद पुरस्कार मिला. उसने माउंटेन ड्यू, आयशर ट्रैक्टर्स, पतंजलि और नेशनल एग कोऑर्डिनेशन कमेटी (एनईसीसी) के विज्ञापनों में अभिनय करके भी कमाई की, जिसके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने उसे सालाना रिटेनरशिप शुल्क के रूप में 1 करोड़ रुपए दिलाए.

लंदन ओलंपिक के बाद सुशील 66 से 74 किलोग्राम भार वर्ग में आ गया था. अब सुशील का दबदबा भी बढ़ा. फिलहाल हरियाणा के गोहाना में ओलंपिक पदक विजेता योगेश्वर दत्त की अकादमी में प्रशिक्षण दे रहे मान बताते हैं, ''छत्रसाल स्टेडियम में अपने कार्यकाल में मैंने कुछ संदिग्ध तत्वों को स्टेडियम में आते देखा था. मैंने उन्हें बाहर जाने के लिए कहा तो बीचबचाव के लिए सुशील आ पहुंचा. मैंने फिर इसे नजरअंदाज ही करने का फैसला लिया. अब सुन रहा हूं कि सुशील को इन [आपराधिक] गतिविधियों में धकेलने वाले वही लोग थे.''

इससे पहले भी सुशील अपने एक विरोधी पहलवान के साथ बहुत तीखे विवाद में शामिल रहा है. साल 2016 में रियो यानी लगातार तीसरे ओलंपिक में खेलने के अपने संकल्प के तहत सुशील ने नरसिंह यादव से अपनी एक बाजी कराने की मांग की थी. दरअसल, विश्व चैंपियनशिप पदक जीतकर नरसिंह यादव ने भारत के लिए रियो जाने का कोटा हासिल कर लिया था. लेकिन जब भारतीय कुश्ती महासंघ ने सुशील को इनकार कर दिया तो वह दिल्ली हाइकोर्ट जा पहुंचा. लेकिन हाइकोर्ट में भी उसको हार का सामना करना पड़ा. नरसिंह यादव ने बाद में सुशील के गुर्गों पर उनके खाने में स्टेरॉयड मिला देने का आरोप लगाया. लेकिन, ड्रग मामले की वजह से ओलंपिक में खेलने का नरहिं यादव का सपना भी टूट गया और उनके

उल्कापिंड-सा उत्थान-पतन

एपी

2008 सुशील कुमार ने 2008 बीजिंग ओलंपिक में कांस्य पदक जीता

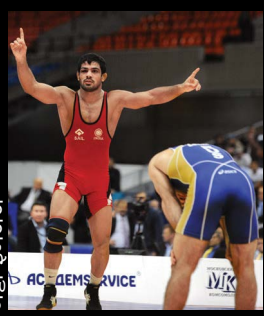

गेटी इमेजेज

2010 विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण जीतने वाला पहला और अब तक का एकमात्र भारतीय

2012 लंदन ओलंपिक (2012) में रजत पदक; लगातार दो ओलंपिक में व्यक्तिगत स्पर्धा में पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय

एपी

2016 भारतीय कुश्ती महासंघ और दिल्ली हाइकोर्ट ने नरसिंह यादव के खिलाफ चयन परीक्षण का सुशील का अनुरोध ठुकराया. यादव ने 2016 रियो ओलंपिक के लिए भारत का कोटा जीता था

दिसंबर 2017 राष्ट्रमंडल खेलों के ट्रायल में प्रवीण राणा पर कुमार की जीत के बाद दोनों के समर्थक आपस में भिड़ गए. राणा का आरोप है कि कुमार ने उन्हें धमकी दी थी

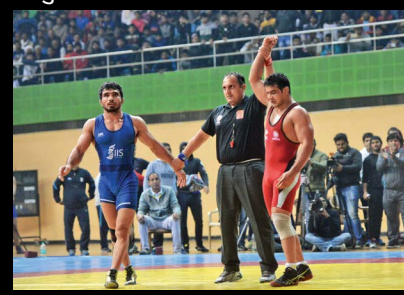

के आसिफ/मेल टुडे

जनवरी 2020 कंधे की चोट से उबरने के बाद सुशील ने महासंघ से 2020 टोक्यो ओलंपिक का नेशनल ट्रायल स्थगित करने की अपील की. उसका अनुरोध नामंजूर कर दिया गया

4 मई, 2021 दिल्ली के छत्रसाल स्टेडियम के बाहर साथी पहलवान सागर धनखड़ की पिटाई करने का आरोप. धनखड़ ने दम तोड़ दिया. सुशील फरार हुए

23 मई विश्व कुश्ती दिवस के दिन सुशील को दिल्ली में गिरफ्तार किया गया

खेलने पर चार साल का प्रतिबंध लगा दिया गया. हालांकि, इस मामले की सीबीआइ जांच में पिछले साल दायर क्लोजर रिपोर्ट में सुशील को दोषमुक्त करार दिया गया.

इंदौर में 2017 की राष्ट्रीय चैंपियनशिप में सुशील को क्वार्टर फाइनल से तीन वॉकओवर मिले, जिसमें से एक पहलवान ने तो उसके पैर तक छुए. दिसंबर 2017 में 2018 कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए दिल्ली में आयोजित ट्रायल के फाइनल में सुशील के प्रवीण राणा को हराने के बाद दोनों के समर्थक आपस में गुत्थमगुत्था हो गए थे. राणा ने आरोप लगाया कि सुशील ने उन्हें धमकी दी और प्रतियोगिता के अधिकारी भी पक्षपाती थे. कुश्ती बिरादरी में कइयों ने उस बेईमानी को भांप लिया था. लेकिन अंतरराष्ट्रीय मंचों पर सुशील के मजबूत प्रदर्शन ने इन आरोपों को उभरने ही नहीं दिया.

हालांकि, पहलवान बिरादरी के कुछ सदस्यों के लिए सुशील अब भी एक आदर्श है. लंदन ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले साथी पहलवान अमित दहिया कहते हैं, ''जो हुआ वह एक 'दुर्घटना' है. लोग पहलवानों को गुंडा समझते थे. सुशील ने वह धारणा बदल दी.'' विडंबना देखिए कि वही शख्स (सुशील कुमार) अब उस रुढ़िवादी धारणा को मजबूत कर रहा है. दिल्ली और हरियाणा के कई पहलवानों ने *इंडिया टुडे* से दावा किया कि सुशील ने रियल एस्टेट दिग्गजों को बाउंसर मुहैया किए और अपने गुर्गों से टोल प्लाजा, रेस्तरां और पबों को नियंत्रित किया.

मार्च 2021 में स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में फिर से चुने जाने के बाद एक प्रशासक की भूमिका लेने के बावजूद सुशील ने कुश्ती से अपनी विदाई नहीं ली. वह अगर ऐसा करता तो उसे विज्ञापनों आदि से हाथ धोना पड़ता. दिसंबर 2017 में वह प्रो रेसलिंग लीग में सबसे महंगा खिलाड़ी था. दिल्ली सुल्तान्स ने उसके लिए 55 लाख रुपए की बोली लगाई थी. साल 2019 तक महासंघ ने उसे 'ग्रेड ए' अनुबंध से सम्मानित किया, जिसके लिए उसे 20 लाख रुपए का वार्षिक पारिश्रमिक मिला.

हालांकि, साल 2018 तक सुशील का करियर अंत की ओर था. वह उस वर्ष जकार्ता में एशियाई खेलों में पदक जीतने में नाकामयाब रहा और 2019 विश्व चैंपियनशिप के पहले ही दौर में वह बाहर हो गया था. जनवरी 2020 में कंधे की चोट के कारण उसने महासंघ से एशियाई चैंपियनशिप और ओलंपिक क्वालीफायर के लिए 74 किलो वर्ग के ट्रायल टालने का अनुरोध किया पर महासंघ ने इनकार कर दिया.

देश के प्रतिष्ठित पद्मश्री सम्मान और अर्जुन तथा राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त सुशील फिलहाल जेल से बाहर निकलने और अपने ऊपर लगे आरोपों से बेदाग निकलने की उम्मीद करेगा. लेकिन अतीत उसके पीछे लगा है. 30 मई को दिल्ली पुलिस ने मॉडल टाउन के एक दुकानदार की तरफ से पिछले सितंबर में दर्ज कराई प्राथमिकी में फिर से जांच शुरू कर दी है. उस दुकानदार ने 4 लाख रु. के किराने के सामान का बकाया मांगने पर सुशील और उसके गुर्गों पर छत्रसाल स्टेडियम में अपनी पिटाई कराने का आरोप लगाया था. ऐसे में हत्या, गैर-इरादतन हत्या और अपहरण सहित कई आरोपों के साथ यह पहलवान अब अनिश्चित राह पर है. ■

तेजपाल बनाम राज्य अब हाइकोर्ट में

पत्रकार-लेखक तरुण तेजपाल को कथित यौन उत्पीड़न के सनसनीखेज मामले में बरी करने के फैसले को गोवा सरकार ने चुनौती दी है. मील का पत्थर माने जाने वाले इस मामले में आखिर क्यों एक और ट्रायल होने जा रहा है

संदीप उन्नीथन और किरण डी. तारे

कार्यस्थल पर कथित बलात्कार और यौन उत्पीड़न के भारत के सबसे सनसनीखेज मामले में 21 मई को उतना ही नाटकीय फैसला आया. गोवा में मापुसा की एक सत्र अदालत के 527 पन्नों के आश्चर्यजनक फैसले में मुख्य आरोपी पत्रकार और लेखक तरुण तेजपाल को आरोपों से बरी कर दिया.

लंबे-से, पोनीटेल रखने वाले तेजपाल ने 2001 में रक्षा सौदों और राजनीतिक भ्रष्टाचार के खुलासे के साथ स्टिंग पत्रकारिता के युग की शुरुआत की थी. फिर 18 नवंबर, 2013 को *तहलका* पत्रिका में काम करने वाली एक पत्रकार ने गोवा के पांच सितारा होटल में पत्रिका के साहित्यिक कार्यक्रम में अपने प्रधान संपादक तेजपाल पर दो बार यौन उत्पीड़न करने का आरोप लगाया. प्रबंध संपादक शोमा चौधरी को भेजे ई-मेल की एक शृंखला में आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि दोनों हमले 7 और 8 नवंबर, 2013 की रात को होटल की लिफ्ट में किए गए.

तेजपाल ने पीड़िता के शिकायती पत्र का जवाब दो माफी पत्रों के साथ दिया. पहला 19 नवंबर को लिखा गया. 20 नवंबर को प्रतिवादी को औपचारिक ई-मेल में तेजपाल ने लिखा कि ''निर्णय की शर्मनाक भूल पर मैं बिना शर्त माफी मांगता हूं. इसके चलते मुझे आपकी स्पष्ट अनिच्छा के बावजूद 7 और 8 नवंबर, 2013 को दो मौकों पर मैंने आपसे यौन संबंध बनाने की कोशिश की, जबकि आप मुझसे ऐसी अपेक्षा नहीं रखती थीं.''

गोवा पुलिस ने मामले की सोशल मीडिया रिपोर्टों का स्वत: संज्ञान लेते हुए तेजपाल को तीन दिन बाद गलत तरीके से बंधक बनाने, बलात्कार और हमले के कई आरोपों में गिरफ्तार किया. छह महीने बाद उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया गया.

अपने 21 मई, 2021 के फैसले में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश क्षमा एम. जोशी ने तेजपाल को संदेह का लाभ दिया, ''क्योंकि अभियोजन पक्ष (पीड़ित) के आरोपों का समर्थन करने वाला कोई सबूत नहीं है''. मामले का मुख्य आधार यह आरोप था कि तेजपाल ने पीड़िता से छेड़छाड़ करते हुए दो मंजिला इमारत की लिफ्ट चालू रखी. जज जोशी ने जोर देकर कहा कि ऐसा नहीं था. फैसला कहता है, ''भूतल की अतिथि लिफ्टों के सीसीटीवी फुटेज स्पष्ट रूप से दिखाते हैं कि बाईं तरफ की लिफ्ट (जो अहम है) 7 नवंबर, 2013 को कथित घटना के दो मिनट के दौरान गति में थी और बाईं लिफ्ट के दरवाजे भूतल पर कम से कम दो बार खुले.'' इसका अर्थ या तो यह हो सकता है कि जब दरवाजा खुला तो आरोपी और युवती लिफ्ट के अंदर थे या अंदर नहीं थे.

जज ने तेजपाल को बरी करने से पहले कहा कि पीड़िता का बयान ''सुधार और भौतिक विरोधाभासों और चूकों व संस्करणों के परिवर्तन को भी दर्शाता है, जिस पर विश्वास नहीं होता है''. 2013 में शुरुआती बयान में युवती ने कहा कि तेजपाल ने घेरे में रखने के लिए लिफ्ट में कई बटन दबाए थे. लेकिन 2020 में जिरह के दौरान कहा कि उसे नहीं पता था कि लिफ्ट स्थिर थी या चल रही थी और आरोपी ने केवल एक बटन दबाया था. फैसले में कहा गया है कि जांच अधिकारी (आइओ) ने सीसीटीवी फुटेज और उसके बयानों में स्पष्ट विरोधाभासों पर अभियोजक से सवाल नहीं किया.

कोर्ट ने कहा कि अभियोजन पक्ष ने केवल यह स्थापित किया कि तेजपाल, *तहलका* के प्रधान संपादक के रूप में भरोसे या अधिकार की स्थिति में थे और पीड़िता पर नियंत्रण या प्रभुत्व जमा सकते थे. यह आइपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत पांच अन्य महत्वपूर्ण आरोपों को साबित करने में विफल रहा, जिसमें गलत ढंग से नियंत्रण, शील भंग करने के इरादे से हमला और बलात्कार करने वाले व्यक्ति की स्थिति शामिल है.

जज ने कहा कि एक महत्वपूर्ण सबूत—तेजपाल और पीड़िता गलती से पहली मंजिल पर लिफ्ट से निकल रहे थे, जो हमले के

पीटीआइ

आरोप का खंडन कर सकता था—उसे पुलिस ने नष्ट कर दिया. फैसले में कहा गया कि युवती को लिखे तेजपाल के माफीनामे को दोषी ठहराने के लिए सही नहीं ठहराया जा सकता, क्योंकि यह किसी अपराध की स्वीकृति या दोष स्वीकारोक्ति नहीं थी, बल्कि *तहलका* को एक पत्र था कि वे आरोपों के कारण प्रधान संपादक के पद को छोड़ रहे हैं.

महिला अधिकार कार्यकर्ताओं और वकीलों का कहना है कि सत्र अदालत ने आरोपी के बजाए पीड़िता का ट्रायल कर दिया. मुंबई के महिला अधिकार समूह बेबाक कलेक्टिव की प्रमुख हसीना खान कहती हैं, ''घटना की पूछताछ के बाद उनकी गरिमा और व्यवहार को देखकर स्तब्ध हूं.''

फैसले के चार दिन बाद 25 मई को गोवा सरकार ने बॉम्बे हाइकोर्ट की राज्य पीठ में अपील दायर की. हाइकोर्ट के जस्टिस एससी गुप्ते ने 2 जून को तेजपाल को नोटिस जारी कर 24 जून या उससे पहले जवाब देने को कहा है. जज ने निचली अदालत से सारे रिकॉर्ड मांगे हैं. समाचार एजेंसी पीटीआइ की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि न्यायालय ने फैसले को 'बलात्कार पीड़ितों के लिए मैनुअल' कहा, क्योंकि इसमें बताया गया है कि ऐसे मामलों में पीड़िता को कैसी प्रतिक्रिया देनी चाहिए.

इंडिया टुडे से गोवा सरकार के अफसरों ने कहा कि वे सत्र अदालत के फैसले में ''तथ्यात्मक और तार्किक खामियों'' को चुनौती देने की योजना बना रहे हैं. उनका मानना है कि कोर्ट ने तेजपाल के लिखित ई-मेल माफी जैसे महत्वपूर्ण पुष्टिकारक सबूतों की अनदेखी की.

तेजपाल मामला ऐतिहासिक घटना है, जो महिलाओं के खिलाफ यौन हिंसा के मामलों में दो महत्वपूर्ण मील के पत्थर-दिसंबर 2012 में नई दिल्ली में 23 वर्षीया 'निर्भया' से सामूहिक बलात्कार और हत्या तथा 2017 के वैश्विक #मी टू आंदोलन के बीच में है. यह केस निर्भया कांड के बाद मार्च, 2013 में भारत में बलात्कार कानूनों में बदलाव के तहत जांच किए जाने वाले पहले बड़े अभियोगों में से एक था. 2013 के फौजदारी कानून (संशोधन) अधिनियम ने यौन संबंधों को बलात्कार के व्यापक कृत्यों के साथ स्थापित किया, जिनमें से कुछ इस मामले में भी सामने आए.

फैसले में आरोप लगाने वाले के यौन इतिहास की गहराई में जाने से वकील और कार्यकर्ता हैरान हैं. सुप्रीम कोर्ट की वकील करुणा नंदी का कहना है कि इस फैसले में शीर्ष अदालत की मिसाल और वैधानिक कानून के कई उल्लंघन हैं. ''सबसे पहले, ट्रायल कोर्ट के जजों को कई स्पष्ट निर्देश हैं कि वे चिकित्सा साक्ष्य की अनुपस्थिति को 'सहमति' नहीं मानें और अभियोक्ता को 'आदर्श शिकार' होने की मांग न करें. दूसरी बात, आप अभियोक्ता के यौन इतिहास का परीक्षण नहीं कर सकते—यह उसकी निजता का उल्लंघन है. और अंत में, बचाव पक्ष के साक्ष्य के मूल्यांकन के लिए जिस तरह का मुफ्त पास दिया गया, वह चौंकाने वाला है. आपके पास एक पत्र था, जिसमें आरोपी कहता है कि वह गैर-सहमति से यौन संबंध बनाने के लिए गहराई से माफी मांगता है.''

अपील की राजनीति

सत्र अदालत के फैसले के खिलाफ गोवा सरकार की अपील पर बॉम्बे हाइकोर्ट की पणजी पीठ में सुनवाई के एक दिन पहले 1 जून को इसमें संशोधन किया गया. पहले, अपील पीड़िता की पहचान और घटना के बाद के उसके व्यवहार के बारे में सवालों के संदर्भों को हटाने पर केंद्रित थी. संशोधित अपील में अब सत्र अदालत की ओर से तेजपाल के माफी संबंधी ई-मेल की अनदेखी का भी जिक्र किया गया है. सरकार का मानना है कि मामला फिर से सुनवाई के लायक है.

गोवा सरकार की अपील में कहा गया है, ''ट्रायल कोर्ट ने बचाव पक्ष के गवाहों के सबूतों को परम सत्य माना, लेकिन बिना किसी निष्कर्ष के अभियोजन पक्ष के गवाहों के सबूतों को खारिज कर दिया.''

सत्र अदालत द्वारा 21 मई को तेजपाल को बरी करने के कुछ घंटों बाद, गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने फैसले को चुनौती देने की राज्य की मंशा जताई. सावंत ने उसी दिन शीर्ष कानूनी अधिकारियों की बैठक बुलाई और उन्हें अपील दायर करने का निर्देश दिया. जब गोवा सरकार ने केंद्र के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता (देश के दूसरे सबसे वरिष्ठ कानूनी अधिकारी) को हाइकोर्ट में अपील पर बहस करने के लिए नियुक्त किया, तो कानूनी समुदाय में भौंहें तन गईं.

एक राजनीतिक सूत्र का कहना है कि तेजपाल को बरी करने पर गोवा सरकार में दो तरह के विचार हैं. पहला तो यह कि सावंत व्यापक संदेश देना चाहते हैं कि महिलाओं के खिलाफ अपराध को हल्के में नहीं लिया जाएगा. राजनीतिक रूप से, भाजपा भी तेजपाल के खिलाफ अपील को अपने आलोचकों को जवाब देने का क्षण मानती है. 2018 में कई पूर्व महिला सहकर्मियों की ओर से यौन उत्पीड़न के आरोपों ने भाजपा के केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री एम.जे. अकबर को पद छोड़ने के लिए मजबूर किया था. भाजपा का मानना है कि तेजपाल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुखर आलोचक, 'लुटियंस मीडिया' (मोदी आलोचक) की पहचान हैं. *तहलका* ने 2001 में पहले स्टिंग ऑपरेशन में तत्कालीन भाजपा अध्यक्ष बंगारू लक्ष्मण को रिश्वत लेते हुए उजागर किया था. 2007 में, उन्होंने गुजरात दंगों पर एक खुलासा किया था, जिसमें संघ परिवार के कार्यकर्ताओं ने अपने नजरिये से दंगों का वर्णन किया था.

एक भाजपा नेता ने बताया, ''गोवा विधानसभा चुनाव नौ महीने दूर है (फरवरी, 2022 में). चुनावी साल में मुख्यमंत्री मोदीजी या गोवा की महिलाओं को नाराज नहीं कर सकते. हम पूरी ताकत के साथ हाइकोर्ट में केस लड़ेंगे.'' आखिरकार, मामला तरुणजीत तेजपाल बनाम गोवा राज्य का है. ■

फैसले की घड़ी

तरुण तेजपाल और उनकी पत्नी 21 मई को गोवा की मापुसा सत्र न्यायालय में जाते हुए

फैसले में तेजपाल को संदेह का लाभ मिल गया, लेकिन महिला ऐक्टिविस्ट हैरान हैं और कह रही हैं कि अदालत ने तो अभियुक्त की बजाए पीड़िता का ट्रायल कर दिया

राग की रंगत में विचार

शास्त्रीय गायक **टी.एम. कृष्ण** का गद्य भी उनके संगीत की ही तरह भेदक होता है. उनके लिखे हुए का नया संकलन इसी हफ्ते आया है पर उनका कहना है कि उनकी निगाह में कुछ भी, यहां तक कि उनका खुद का संगीत भी ठोस और स्थायी नहीं

● आपकी किताब *द स्पिरिट ऑफ इन्क्वायरीः नोट्स ऑन डिसेंट* आपके उम्दा आलेखों का संकलन है. पुराने आलेखों को आपने किस ढंग से जांचा-परखा और उनका चुनाव किया?

संकलन के पीछे मूल बात यही थी कि वह विचारोत्तेजक हो. आलेखों का चुनाव इस आधार पर किया कि भले ही वे किसी फौरी विषय पर प्रतिक्रिया के रूप में लिखे गए हों पर वे उस घटना से उपजते व्यापक मुद्दों पर बात करते हैं. मैं नहीं मानता कि महज इसलिए कि कभी कुछ सार्वजनिक रूप से कहा/लिखा है तो उस पर अड़ा रहूं. तभी तो वर्षों पहले लिखे गए एक लेख की मैंने जमकर आलोचना की है. संग्रह में नए आलेख जोड़कर मैंने अपनी वैचारिक बहस को ज्यादा गंभीर और परतदार बनाने की कोशिश की है.

● आप तो राष्ट्रगान पर भी एक किताब लिख रहे हैं, उसके प्रतीकों के पीछे की सोच और उसके अर्थ जानने के नजरिए से. इस किताब का ख्याल कैसे उपजा?

प्रतीक खूबसूरत भी हैं और खतरनाक भी. वे हमें ताकत और साझेपन का एक भाव भी देते हैं पर अक्सर हमें अपनी अर्जित और उपार्जित प्रासंगिकताओं के भंवर में फंसा लेते हैं. इस किताब में आलोचनात्मक ढंग से उन्हें परिकल्पित कर पाऊंगा, ऐसी उम्मीद है.

● हर लेखक की अपनी एक चर्या और एक लय-ताल होती है. आपनी प्रक्रिया क्या है?

मेरा सब कुछ बहुत ही अव्यवस्थित रहता है, वह चाहे संगीत हो या लेखन. मेरा ऐसा कोई व्यवस्थित नियम-कायदा नहीं है. शुरू करने में तो मुझे अच्छा-खासा समय लग जाता है लेकिन उसके बाद एक लय बन जाती है.

● इधर के वर्षों में शब्दों के साथ लगातार संवाद के चलते अब बतौर संगीतकार क्या आप शब्दों को स्वर के रूप में सोचते हैं?

वैसे तो शब्दों और स्वरों दोनों का स्वभाव ध्वन्यात्मक ही है, पर हम कह सकते हैं कि शब्द अपने अर्थों के जरिए स्मृति में आते हैं और स्वर रागों के जरिए. पर दोनों में यह क्षमता है कि वे हमें थोड़ा ठहरकर सोचने के लिए प्रेरित करें.

–अखिला कृष्णमूर्ति

आज तक

देश का नं. 1 हिंदी न्यूज़ ऐप

जुड़े रहिए हर खबर से,
कहीं भी, कभी भी

अभी डाउनलोड करें

aajtak.in/app

उपलब्ध है

IndiaContent

SEARCH FOR EDITORIAL IMAGES ENDS HERE